

Demands for Supplementary Grants (2025-26)- First Batch- continued concluded

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : सभापति जी, धन्यवाद । अनुदानों की अनुपूरक मांगों, 2025-26 में 72 अनुदान मांगों शामिल हैं । इसमें कुल राशि एक करोड़ बत्तीस लाख दो सौ अड़सठ करोड़ रूपये है और अतिरिक्त अनुदान की मांग इकतालीस हजार चार सौ पचपन करोड़ रूपये है । (व्यवधान) इसमें दो तिहाई यानी 27 हजार करोड़ से अधिक सब्सिडी पर खर्च करने की बात कही गयी है । (व्यवधान)

मान्यवर, ये आंकड़े कागज पर तो चमकदार लगते हैं, लेकिन हकीकत में एक ऐसी सरकार की कहानी बयान करते हैं जो प्राथमिकताओं से भटक गई है । (व्यवधान) क्योंकि यह न केवल व्यर्थ का खर्च है, बल्कि आम आदमी की पीड़ा को नजरअंदाज करने का प्रमाण भी है । (व्यवधान) मान्यवर, किसानों के लिए रसायन, उर्वरक पर जो मांग रखी गयी है, उसमें ज्यादातर धन सब्सिडी के लिए रखा गया है । (व्यवधान) मान्यवर, अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से किसानों का बुरा हाल रहा । लोगों को न तो फास्फोरस, पोटैशम मिला, न यूरिया मिला, न डीएपी मिला । इस अनुपूरक मांग में 23,423 करोड़ रूपये सब्सिडी में लगाने की बात कही गयी है । आज जहां हमारा किसान एमएसपी की मांग को लेकर दर-दर भटक रहा है, लेकिन उसको एमएसपी नहीं मिल रहा है । किसान सड़कों पर खड़ा है, लेकिन सरकार सब्सिडी के नाम पर विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है । आयातित यूरिया पर इतना खर्च क्यों? सरकार अपनी क्षमता बढ़ाने में नाकाम रही है, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिला । किसान को केवल मंहगाई और कर्ज मिला । किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है । हम सरकार से मांग करते हैं कि सब्सिडी को पारदर्शी बनाया जाए, आयात पर निर्भरता कम करें और किसान कल्याण को प्राथमिकता दी जाए, तभी अनुपूरक मांगों का कोई महत्व होगा ।

मान्यवर, बहुत सारे विभागों की इसमें चर्चा की गई है । हम प्रमुख रूप से शिक्षा विभाग पर बात करना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग का जो हाल है, जिस तरह से शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यह जो अनुपूरक मांग की गयी है, इसमें उच्चतर शिक्षा के लिए 1303.72 करोड़ रूपये की मांग की गयी है । इसमें 2023.25 करोड़ की एक नई योजना 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' लायी गयी है । वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस के लिए 65.45 करोड़ रूपये की मांग की गयी है ।

सभापति महोदय, यह क्या मजाक है? आज भारत के ग्रामीण अंचल के बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं । गांव के स्कूल बंद किए जा रहे हैं । ऐसे में 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' का क्या मतलब है? डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए 42.63 करोड़ रूपये की मांग की गयी है, जबकि एससी के लिए मात्र 2.04 करोड़ और एसटी के लिए तो केवल 33 लाख रूपये की मांग की गयी है । यह भेदभाव क्यों? शिक्षा का अधिकार अधिनियम का जो कानून है वह अधर में लटका हुआ है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वादा अधूरा है, लेकिन पूरक मांगों में एलिट इंस्टीट्यूशन को प्राथमिकता दी गयी है । हमारी मांग है कि बुनियादी शिक्षा पर फोकस किया जाए, आरटीई को मजबूत बनाएं, न कि चमकदार योजनाओं के नाम पर फंड बर्बाद करके यह जो 90,812 करोड़ के ग्रास बैग का हिस्सा है, वह सेविंग से मैच तो हो रहा है, लेकिन सेविंग कहां से आयी? यह शिक्षा बजट में कटौती करके आयी है । शिक्षा के

बजट को काटा न जाए, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को भी महत्व दिया जाए, यह हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं ।

मान्यवर, जो अनुपूरक बजट आया है, इस बजट में अच्छा होता कि हमारे बरेली के अंदर एक सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड रबर फैक्ट्री के 1400 से अधिक स्थायी और हजारों अस्थायी श्रमिक बेरोजगार हो चुके हैं । वहां फैक्ट्री बंद है और लगभग 1432 कर्मचारियों की देनदारी का मामला अभी लंबित है । बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के कारण इन परिवारों पर जीवन-यापन का गहरा संकट लगातार बना हुआ है । फैक्ट्री प्रबंधन ने बकाया वेतन और अन्य भत्तों का समुचित भुगतान नहीं किया । सरकार की उदासीनता के कारण ये परिवार भूखों मरने पर मजबूर हैं । अगर सरकार इन श्रमिकों के भुगतान की व्यवस्था भी इन अनुपूरक मांगों में करती तो शायद उन परिवारों का भी कुछ भला हो जाता, लेकिन सरकार ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया ।

मान्यवर, अनुपूरक बजट आता है, मुख्य बजट आता है और हम यहां 543 लोग चुन कर आते हैं । जब हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता हर तरफ विकास की बात करती है, क्योंकि यहां से विकसित भारत का एक नारा दिया जा रहा है । मेरा जो आंवला क्षेत्र है, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी रास्ते अच्छे नहीं हैं, सड़कें अच्छी नहीं हैं, पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हैं । (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात कनक्लूड कीजिए ।

श्री नीरज मौर्य : मान्यवर, जब हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों को कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, वे हमसे विकास की बात करते हैं और कुछ उम्मीद करते हैं । जब केन्द्रीय सरकार को खर्च करने का बजट कम लगा तो सरकार ने अनुपूरक की मांग कर ली । हम सांसदगणों को बहुत कम सांसद निधि 5 करोड़ रुपये की दी जाती है । (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप कृपया कनक्लूड कीजिए ।

श्री नीरज मौर्य : जब हमारे पास विकास कार्यों के लिए पैसे की कमी आती है और हम काम नहीं कर पाते हैं तो हम किससे पैसा मांगें? इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार को हम सांसद लोगों की निधि को बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए ।

मान्यवर, जहां तक मुझे जानकारी है, सांसद निधि सन् 2010 में 5 करोड़ रुपये की गई थी । वह 5 करोड़ रुपये तब की गई थी, जब जीएसटी नहीं था । आज पूरे देश की कई विधान सभाओं में, जो विधान सभा के सदस्य हैं, उनका क्षेत्र छोटा होता है, लेकिन उनकी निधि हम सांसदों से ज्यादा है । सांसद निधि में 5 करोड़ रुपये दिए जाते हैं, उसमें से 10 लाख रुपये कंटीजेंसी के काट लिए जाते हैं और जीएसटी लगाया जाता है । (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी ।

श्री नीरज मौर्य : मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिए । (व्यवधान) मैं कनक्लूड कर रहा हूं । (व्यवधान) वर्ष 2010 के मुकाबले महंगाई बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, मतदाता भी बढ़े हैं, लेकिन सांसद निधि बढ़ाने पर विचार नहीं हुआ । ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार विकास नहीं कराना चाहती है । अगर विकास कराना चाहती है तो सांसद निधि को बढ़ाया जाए, जिससे हम लोग छोटे-छोटे काम कर सकें । (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपने अपनी मांग रख दी है ।

प्रो. सौगत राय जी ।

श्री नीरज मौर्य : मान्यवर, मैं कनक्लूड कर रहा हूँ । (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दम दम) : आप उनको बैठने के लिए कहिये । (व्यवधान)

माननीय सभापति : सौगत राय जी, आप बोलिये ।

(व्यवधान)

माननीय सभापति : नीरज जी, हम आपको तीन बार मौका दे चुके हैं ।

श्री नीरज मौर्य : मान्यवर, मुझे 20 सैकेंड का समय दे दीजिए । (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप 20 सैकेंड में अपनी बात पूरी कीजिए । सौगत राय, जी आप बैठ जाइये ।

श्री नीरज मौर्य : मान्यवर, जो प्राथमिकताएं हैं, वह तो गड़बड़ लग रही हैं । 1.32 लाख करोड़ रुपये का जो व्यय है, इसमें किसान, युवा, महिला, गरीब कहां हैं? यह सरकार अमीरों के लिए अनुपूरक बजट लेकर आई है । इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि कारपोरेट्स की सब्सिडी पर ध्यान न दिया जाए, बल्कि हमारी जो गरीब जनता है, उस पर ध्यान दिया जाए । (व्यवधान) मैं इस अनुपूरक मांग का विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

HON. CHAIRPERSON: Now, Prof. Sougata Ray Ji.

Next, hon. Member Shri T. R. Baalu ji will be speaking.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I rise to speak on the Supplementary Demands for Grants. I resent the fact that the Finance Minister is not here. The Minister of State is there, and he has become the President of BJP, Uttar Pradesh. What will he look into finance?

Sir, this demand is for additional Rs. 41,000 crore budget outgo, but actually the total Supplementary Demand is Rs. 1.32 lakh crore. Out of this, Rs. 90,000 crore is technical because this amount will be made up from savings of different departments, and Rs. 41,000 crore roughly will be outgo from the Government. Out of this Rs. 41,000 crore, Rs.18,000 crore is for fertilizers. Out of that, Rs. 11,000 crore is for fertilizer subsidies, and Rs. 7,000 crore is for import of urea. Similarly, Rs. 9,500 crore is meant for the Petroleum Ministry. Out of that, the oil companies will be made up for their loss as far as LPG is concerned. Unfortunately, this country produces only 33 per cent of its petroleum requirement, so you can understand the situation.

Now, I would say that the Finance Minister has tried to do a reasonable job in the sense that only 4.4 per cent is the fiscal deficit target, which we shall be able to meet this year. Even though the Finance Minister does not have a finance background, yet she has worked hard. I must say that. But, there are severe fault lines in the Supplementary Demands. What are the fault lines? Fertilizers like urea are in crisis. The farmers are lining up every day from morning to get urea. Now, urea is being sold in black market. The Government is doing nothing about that. Our production will be hit because of lack of urea.

The second thing I want to mention is that oil marketing companies want to be fully compensated for their loss in supplying LPG. We may be in for another LPG price rise. I would urge the Government that let them give more money but do not increase the price of LPG. I am saying that there are some fault lines in this whole budget.

Another issue is related to Vodafone. The Government is considering relief for this financially stretched company. I would like to know whether the Government will actually give the answer on this.

Sir, you are a studious man. You must have noticed. Five months ago, Modi's friend Trump said: India is a decaying economy, a finished economy. This is what Trump said. I want to know what the Central Government says.

Sir, the IMF has said that India is in C category. IMF retained its C grade for India's national account statistics or GDP data. They are saying that GDP growth is there, but IMF is saying that this is in C grade in statistics. The Government will have to reply on this. *(Interruptions)* Sir, everybody will congratulate you for your election, but you listen to me. *(Interruptions)*

Sir, the other point I want to say, and where we are terrible, is the rise in the fall of rupee. The rupee became Rs. 89.46 against the dollar from Rs. 89.12. Our currency has fallen against all other major currencies, more against the euro and also against the dollar. We are in a very bad situation. All imports including petroleum imports will cost more. This is a very bad situation. We have to reply to President Trump that we are not a dead economy. He said on record that India is a dead economy and that is why we are not in a hurry to have a trade pact with India. The IMF has put our country in C Grade category. We should be very concerned about all this.

Sir, we were discussing education a little while ago. India's rank in the Human Development Index released by UNDP is 130. We are the 130th country in the Human Development Index. This index measures countries in terms of health, education and other matters. What explanation does the Government offer regarding this?

I do not want to speak for a long time since Shrmati Pratima Mondal will also speak on behalf of our party. Sir, I want to pose one question. Why is the Finance Minister depriving West Bengal in the matter of MGNREGA? This year the MGNREGA dues to West Bengal is Rs. 7,000 crore. It is Rs. 52,000 crore for the last two years and total dues of West Bengal is Rs. 2 lakh crore. Why is West Bengal being deprived? Do you think, we shall be kept down forever? We have already protested. We shall continue to protest. There are some people who are inimical to West Bengal like Sukanta Majumdar. They do not want West Bengal to get money. But, in spite of everything, we shall give poor people their sustenance and we shall win the elections in 2026.

Sir, supplementary demand is an essential part of the budget making exercise. We know that if the Government has shortfall, it has to be made up. We know that there is also technical savings in the sense that they will be made from savings of other Departments. In this way, another technical supplementary expenditure is Rs. 8,337 crore, which is sought for transfer to monetisation of National Highways, to fund Infrastructure Investment Trust (InvIT), and Rs. 35,950 crore is sought for investment under conversion of outstanding spectrum auction dues into equity in respect of Vodafone Idea Limited. So, all is not well in the state of Denmark. Even though the Government says that our economy will be the third economy in the world. It will be a five trillion-dollar economy.

HON. CHAIRPERSON : You may conclude.

PROF. SOUGATA RAY : The economy has serious fault lines. I hope that the Finance Minister, who insulted this House by not coming to the House in the time of debate, will reply to all these questions whenever she comes here.

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Although I am interested to take part in the discussion on the First Batch of the Supplementary Demands for Grants for the current year amounting 1,32,000 crore, I am analyzing why there is such an additional demand of 1,32,000 crore within a period of six months of the presentation of Budget. They say two aspects. One

aspect is the gross additional expenditure of Rs. 90 thousand 812 crore, matched by savings of the Ministries and Departments. Secondly, a net cash outgo of over Rs. 41,400 Crore. Additional expenditure of Rs. 90,812 crore which they state is not an unexpected expenditure. How will you get savings? Whether they have put in the Savings fund? Otherwise whether this money is allocated extra? You have even already allocated sufficient funds in the General Budget. Now you are coming with the supplementary demands. It is not fair to say and prove that these are all unexpected spending. As they have excess money, they are returning. Why then they are terming it as revenue? How can they get more revenue? By keeping commercial sectors in hand, did they get more revenue through Department of Trade? Or something else. Both reasons are very much confusing and unbelievable. There is an additional expenditure of Rs. 41, 458 crore. Hon Minister says that as she has more expenses, she has gone for Supplementary Demands for Grants. Out of this, Rs. 41458 crore, 18,575 crore is for fertilizer subsidy. An amount of Rs 9,500 crore is the subsidy to be given to crude oil companies. These two expenses are annual expenses which are expected every year. Fertilizer subsidy is a regular one

given every year. Similarly the subsidies meant for Crude oil, petroleum department and that of oil are annual expenditures. How did not they expect this?

14.57 hrs (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

Not only that Rs. 2500 crore for Department of Home Affairs; Rs. 1200 crore for Education and Rs. 1300 crore for External Affairs Ministry. Approximately they need almost Rs. 41,500 crore. It is unfair to ask now as this was known to them already. My question is that why have they not included in the actual Budget itself? While replying I want a clarification that Hon Minister should say about expenses of Rs. 9,818 crore and Rs. 41,458 crore. Another main aspect in this Supplementary Demands for Grants is what is said by the International Monetary Fund. As per IMF, the financial statements and the accounts handled by them in India are all not up to the mark and are substandard in nature. They call our financial position, accounting procedures and several other things as substandard ones and hence provided C Grading. What is the main reason for this C Grading provided by IMF? You said there will be a growth rate of 10.1 per cent. Even at the time of presentation of Budget they said that the growth rate will be 8.1 per cent. But Hon Prime Minister has agreed to the fact that our growth rate is 8.2 per cent. Why is there a sudden decline of 2 per cent in the GDP? Since the economy is going down

they have given C Grade to us. Among the categories of A, B, C and D, IMF has given us the C Grading to India. This situation has been created by us. That is why the actions and economic activities of the Government are seen with a ray of doubt in mind by many.

Dr Arvind Subramaniam and Dr Arun Kumar, both these persons are experts of economy. They have said this. They say that these are unbelievable for them as well. Not only that, they collect Cess every year. For a particular period this Cess is collected for a particular Department. That amount collected through Cess should be provided to the Department for which it was collected. But it is not provided to the respective Department. This Petroleum tax was levied in the year 1975. But this Cess of Petroleum has been continuously collected for the last 50 years. It comes to approximately 2.98 lakh Crore.

15.00 hrs

Approximately they have collected Rs 3 lakh Crore. Out of this collected money of 2 lakh 98 thousand Crore, only a meagre amount of Rs 902 Crore has only been spent for the Petroleum Ministry. There is the Department called OIDB which means Oil Industry and Development Board. This 2 lakh and 92 thousand Crore would have gone to Petroleum Ministry. But it was not spent for them. If it was spent, they would have got new Schemes. There is a Crude Oil deficit of more than 70 per cent. We import more than 80 percent of Crude Oil. There would have a reason so not to import from External Affairs Ministry. For this indiscipline, I wish to say that the IMF has given C grade and made us low. Indian Financial Department is their Department. They make Cess collection and they take themselves for their expenses. After giving only Rs 902 Crore to Petroleum Department and the remaining amount of more than 2 lakh and 80 Lakh Crore are kept by themselves. I want to ask whether it is fair. They are betraying the States in the same manner.

Sir, I need some five or ten minutes please. How are they betraying? This MGNREGA Scheme, since it is in the name of Mahatma Gandhi you try to change. This Government is in worst condition. This is the example to prove that this Government is getting worse day after day. Not only the 100 Man days of work. This number of Man days is on the decline. Tamil Nadu was once having 30 crore Man days and now it has come down to Rs 12 crore whether it is not a shameful one? So far the Union Government has to give 1,690 crore to the Government of Tamil Nadu. Money was not provided. This is actually the money given by Tamil Nadu government for the material purchased for implementing MGNREGA. Not

only that, an amount of Rs 31,450 crore should be allocated for implementing the schemes of Railways. Out of this Rs 31,450 crore, the Department of Railways has only been allocated Rs 301 crore. What does that mean? Out of 95 per cent, not even 1 per cent is released. Out of the tax collection Tamil Nadu gives almost 1 lakh crore. But Tamil Nadu is given just 91 crore by the Union Government. How can it be good with this amount?

Railway Department is given just Rs. 301 crore. How will this be sufficient? We had sent the proposal regarding Metro Rail Scheme 5 years ago. This proposal sent 5 years ago, was returned to the Tamil Nadu Government by the Union Government just some time ago. Madurai and Coimbatore are two Metropolitan Cities and we want Metro Rail in these Cities. Without any proper reason they have turned down this Proposal. All of a sudden, now they say these two Cities in Tamil Nadu have a population less than 20 lakh people each. The population figures quoted by them belong to 2011 Census. They claim that the population in these two Cities are less than 20 lakh and hence Metro rail project cannot be implemented. This they are saying now. I want to ask them how Metro railway was approved for Cities like Agra, Indore, Bhubaneswar and Navi Mumbai. Will the population figures of these Cities not be the criterion? Should you see the Population figures or the viability? Should you not see the profitability or viability of the project? I wish to say that the criteria they look at seems to be the worst. The distance between Poonamalle to Chennai is just 10 kms. This stretch is already completed. Although the safety certificate was provided, they have not this project functional. This is the worst situation and this shows how the Union Government treats the Tamil Nadu Government.

Another issue is relating to moisture content in Paddy. Farmers grow paddy and even in September month there were rains. After rains the situation has further worsened. The farmers cannot avoid harvesting paddy. Paddy that was harvested was brought to the threshing field. Moisture content of paddy got increased further at the threshing field. The Government procures paddy with only 17 per cent of moisture content. But our Hon Chief Minister of Tamil Nadu *Thalapathi* Shri M.K. Stalin has demanded that the level of moisture content for procurement of paddy should be increased from 17 per cent to 22 per cent. He has written letters to Hon Prime Minister time and again. But the Union Government has not accepted this demand. What will you now? The situation in delta district of Thanjavur is similar to that of Kanchipuram and Chengelpet. They will have a meeting in Thanjavur within 2 or 3 months from now. Let us wait and watch as to how the

Prime Minister will be received in Thanjavur by the farmers when he goes for a meeting there. They are avoiding the request to increase the moisture content of paddy from 17 percent to 22 percent. Next is the Educational Scheme.

The Union Government has to give Rs 3,548 Crore for Samagra Shiksha Scheme, SSA. They are not releasing this fund. Why cant you release? They want us to accept the New Educational Policy. Why should we accept the NEP? It is not an Act. It is just a policy. There can be different policies for the State and the Union Governments. How can you insist on us? How can you ask us to follow your policy? We will not accept this. Not only today, we will never be accepting Hindi. Imposition of Hindi will never be accepted in Tamil Nadu. We will continue to oppose imposition of Hindi. This is the policy of Perarignar Anna and Annan Dr. Kalaignar. We will never deviate from the path laid by them.

This New Educational Policy will never be accepted by us in Tamil Nadu. Teachers were appointed in the year 2010. Almost 4 lakh teachers were appointed in Tamil Nadu. Now they come with a policy. These Teachers should clear a test named Teacher Eligibility Test for continuing their service. They were all appointed in 2010. But you bring this policy in 2024. Just 14 years after their appointment. You say that these Teachers should clear this eligibility test within a span of two years. Only when they pass this TET, they can work as Teachers. They cannot pass this test. Is it possible? I rather urge that the Union Government should approach the hon. Court and a find to a relief to such Teachers. Otherwise, these Teachers may be affected The Union Government should take a humanitarian view on this issue.

My dear friends, we demand (i) Immediate release of pending MNREGA funds due for Tamil Nadu as regards labour and material allocation. (ii) To approve the increased moisture content of paddy from 17per cent to 22 per cent. (iii) Immediate approval of the metro projects pertaining to Coimbatore and Madurai cities. (iv) Immediate release of rightful due of Rs 3,548 Crore under Samagra Shiksha Scheme SSA without any further delay. Teachers have to continue in their Jobs and for that I urge the Union Government should approach Hon Court and get a relief for protecting the lives of these Teachers.

Vanakkam. Thank you.

SHRI KESINENI SIVANATH (VIJAYAWADA): Thank you, Sir. I rise to speak on the First Batch of Supplementary Demands for Grants for year 2025-2026. This Batch

covers 72 grants, with the Government seeking Parliament's approval for an additional gross amount of Rs.1.32 lakh crore.

Sir, some hon. Members from the Opposition have spoken about economic disorder. However, the facts are different. Under the leadership of our hon. Prime Minister, Narendra Modi ji, FDI has crossed 81 billion US Dollars. The Minimum Support Price for major crops has increased by 50 to 70 per cent with record procurement helping farmers, and over 75 per cent of the defence capital budget is now kept for Indian industry, boosting jobs and national security.

Now, while speaking on Supplementary Demands for Grants 2025-2026, I would like to submit that under the Supplementary Grants, Minister of Chemicals and Fertilisers has re-appropriated funds amounting to Rs 31,000 crore, a significant portion of which will strengthen the urea subsidy scheme. Urea is not merely a fertiliser, it is the backbone for crop growth. Any delay in its supply threatens entire agricultural cycle. This year, Andhra Pradesh faced a sudden surge in demand during the peak *kharif* season. At this critical moment, our hon. Chief Minister, Nara Chandrababu Naidu personally intervened, and took up the issue with the Union Government. The hon. Minister, Shri J.P. Nadda, swiftly responded, released fresh stocks and ensured uninterrupted supply across the State. This timely assistance protected our farmers, our crops and their livelihoods.

Sir, an amount of Rs.18,800 crore has been re-appropriated to the Ministry of Road Transport and Highways. The Union Government has built 10,660 kilometres of highways in Financial Year 2025, exceeding its target of 10,400 kilometres. This indicates Government's commitment to ensure connectivity across the country. Another critical transport project to ensure connectivity is the metro rail. Among all the Southern States, Andhra Pradesh is the only State without metro rail system. In this background, Vijayawada and Vizag metro projects are not just transport systems, they are necessary for the growth of this region and achieving Prime Minister's goal of Viksit Bharat.

Sir, Rs.1,303 crore is being re-appropriated to the Ministry of Education. One of the key sectors in education is medical, for which building of new colleges is essential. When there is a crunch in financial resources, the Central Government, from time to time, comes up with innovative models to ensure that development does not stop. But YSRCP Party today in AP is opposing the development of medical colleges. This is the sector they themselves have neglected with inaction and false promises. They promised to build 17 new medical colleges, but the truth is that not even a

single stone was laid for most of them. In four years of YSRCP Government, instead of Rs.85,000 crore, they have spent less than Rs.1,000 crore. At this pace, it will take 15 years for completion of these 17 medical colleges.

After failing so badly, the same party now opposes nationally approved PPP model. The Department of Economic Affairs, Government of India has notified this model and the apex body for medical education, the National Medical Commission has recommended to build PPP medical colleges.

Also, the Parliaments Standing Committee on Health and Family Welfare recommended colleges of this model. Yet, YSRCP is against this model because they do not understand the difference between PPP and privatization. Under PPP model, the Government keeps full control while the private partners only support infrastructure, operation, and completing the construction within two years. Half the seats remain under Government quota, all the reservations stay the same, and the fees for these seats are capped to protect the students. In these hospitals, 70 per cent of beds are reserved for Ayushman Bharat patients. This model ensures better infrastructure while safeguarding the students and the poor. If YSRCP is really committed for public, they would have not spent Rs.500 crore of Government money to build a palace for their Chief Minister, a gross ugly waste of public wealth. They could have instead used Rs.500 crore for the operation of these medical colleges. Their opposition to medical colleges through PPP model exposes their hypocrisy. Neither they will work nor they will allow anyone else to work. They cannot digest the development being pursued by our hon. Chief Minister, Nara Chandrababu Naidu Ji.

Finally, I conclude. The Supplementary Grants show the Government's clear commitment to welfare, agriculture, education, and health. Under the leadership of our hon. Prime Minister, Narendra Modi Ji, India has delivered 8.2 per cent of GDP growth despite global uncertainty. Together we build a stronger and brighter nation for our people. Thank you, Sir.

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you, hon. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants. Basically, these Demands for Grants were introduced in December 2025, covering about 72 demands and one appropriation.

Today, the truth about Indian economy is staring us in the face. The rupee is weak, prices are high, jobs are lacking, and confidence is collapsing. This is not a bad luck;

this is bad governance by this Government. The rupee has fallen to its lowest ever level, closing at 90 against the US dollar and still sliding. This is not a small technical issue. The hon. Finance Minister is not present here. The Government is asking Parliament to approve Rs. 1,32,000 crore, yet the hon. FM is not here. I think for a discussion on the Supplementary Demands for Grants, the presence of FM is needed. When we raise the issue of the falling rupee, she tells us that it will not affect the economy at all. But what is the reality? A weaker rupee means higher fuel prices, costlier imports, and increasing pressure on the common man. When the hon. Prime Minister was the Chief Minister of Gujarat, and the rupee had fallen to 58 against the US dollar, he remarked that there is a competition going on between the rupee and the Government in Delhi as to whose dignity goes down faster. This was said by our hon. Prime Minister. Today, the rupee has touched 90 against the US dollar. So, whose dignity is now going down? At that time, the Chief Minister of Gujarat compared it with the Union Government. Whose dignity is lower now? Certainly, it is the Union Government's dignity which is lower compared to the rupee. It is very, very unfortunate. Even more worrying is that the GDP rates projected by the Government are being questioned internationally. The IMF has flagged serious weakness in India's GDP data. Still the Government is saying that our GDP is better. But IMF is already contesting it.

I would like to point out a concern with regard to the Ministry of Road, Transport and Highways. We are passing Supplementary Demands for Grants for the Ministry of Road, Transport and Highways. For the year 2025-26, the Ministry of Road, Transport and Highways proposed an expenditure of nearly Rs. 2.87 lakh crore, which is higher than last year. The allocation for roads and bridges alone is more than Rs. 1.16 lakh crore. India today has the second largest road network in the world. I agree that the national highway network is developing and expanding. But the House must ask a fundamental question. Is this massive spending resulting in safer roads, accountability, and value for public money, or is it creating a system where public funds are converted into private profit for a chosen few? The debate is not about opposing highway development. We are all for development. The debate is about the corruption taking place in this area. We have discussed Bharatmala Project many times. It was intended to complete within five years. Now, eight years have passed, and even 50 per cent of the work has not been completed.

I now come to my State of Kerala. The consequences of this reckless model are most visible in Kerala. From Kasargod in the North to Kollam in the South, national highway projects particularly NH-66 and NH-544 are collapsing before the eyes of

the public. The roads are virtually collapsing. I think, Sir, you are also aware of this. The roads of national highways are collapsing like anything in Kerala. Elevated structures are sinking, retaining walls are collapsing, service roads are flooded, and fresh cracks are appearing on newly constructed roads. In May, this year, the entire elevated highway structure at Kooriyad collapsed. The scene was catastrophic, and the entire structure is now beyond repair. Recently, a retaining wall on NH in Kollam collapsed, an issue already raised by Shri Premachandran. I can list dozens of such incidents. What is the problem? In my own constituency, one death has been reported. Forty people have died at the construction site because there is no proper management. What is happening in Kerala is not an act of nature; it is the result of a system where speed and profit were prioritized over safety and scientific planning.

The House must understand that these failures are not accidental. They are the outcome of a development model designed to maximize corporate profit, not public safety. This brings me to the core issue behind these Supplementary Demands for Grants, which is basically a highway scam. Let us look at one project, Azhiyur-Vengalam stretch of NH-66 in North Kerala. This is a road of just 40 kilometres. This project was awarded to Adani Enterprises for Rs. 1,832 crore.

Adani did not build it, Sir. What they have done is they have sub-contracted the entire work to Wagad Infraprojects Pvt. Ltd., an Ahmedabad-based firm, for just Rs. 971 crore. You see, Sir, the total contract was for Rs. 1,838 crore. He has given the sub-contract for Rs. 971 crore, that is almost half the amount. Basically, the actual construction cost is Rs 23.7 crore per km, but Adani is being paid Rs. 45 crore per km, Sir. Sir, Adani will earn Rs. 2,043 crore from this one project alone, an excess profit of Rs. 1,310 crore, funded entirely by public money. This *loot* is legal, Sir. I am not telling it is illegal. This *loot* is legal because the system was designed for it. Kerala NH 66, a six-lane highway project, has been divided into more than 19 phases. Some of these phases are being executed under the EPC model and some are in the HAM model. The projects executed under EPC model in Kerala have cost between Rs. 26 crore and Rs. 32 crore per km, even for roads with higher complexity. The bridges are there. Actually, the area is designed. Areas are also very much complicated, but their money is lesser. The scam is not accidental, Sir. It was designed and facilitated through the Hybrid Annuity Model (HAM), introduced in 2016 under the Modi Government. Here is how HAM works. About 40 per cent of the project cost is paid during the construction itself, 60 per cent is paid over 15 years annuity with interest of the bank rate plus 3 per cent.

A separate contract covers 15 years of maintenance on top of Rs. 1,838 crore. Sir, you can see that in this case, the contractor got Rs. 735 crore during the construction itself. He will get Rs. 1,102 crore over 15 years as annuity. He will also get Rs. 940 crore as interest. He spends only Rs. 971 crore and earns over Rs. 2,043 crore. This is a profit margin of more than Rs. 1,000 crore without laying a single brick himself. (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: What is the Rule?

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, वेणुगोपाल जी हमारे सीनियर सांसद हैं, पीएसी के चेयरमैन हैं । (व्यवधान)

सर, रूल - 216 यह कहता है कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में जिन चीजों के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स आयी हैं, केवल और केवल उसी के लिए चर्चा हो सकती है, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की चर्चा नहीं हो सकती, न किसी पॉलिसी की चर्चा हो सकती है । (व्यवधान) ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं । (व्यवधान) इसलिए सर, इनको केवल डिमांड्स पर चर्चा के लिए कहिए । (व्यवधान)

यह रूल हमने नहीं बनाया है, यह आपने बनाया है । (व्यवधान) रूल मावलंकर साहब ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है । रूल -216 यही है । (व्यवधान)

सर, रूल यही है, इसीलिए उनको कन्फाइन कीजिए कि वे केवल और केवल सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर ही चर्चा करें । (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL: My colleague from the Treasury Benches, Shri Nishikant ji pointed out a point of order. (*Interruptions*) Sir, we are given Supplementary Demands for Grants. They are asking for National Highways also, Sir. I quoted that. They are asking for a Supplementary Demand for Grant for National Highways also. If we cannot discuss about National Highway projects, Sir, what else do we have to discuss? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It is clearly mentioned in Rule 216. You have to follow the Rule 216.

(*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, I am seriously talking about this. This is a concern of our State. Every day road is collapsing, Sir. People are very much in a fear.

HON. CHAIRPERSON: There is Rule 216. The debate on the Supplementary Grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original Grants nor policy underlying them, insofar as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion.

(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You are a senior Member of the House. You should follow the rules.

(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No, please be seated.

(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You are not allowed.

(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: He is capable to speak.

(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: He is a senior Member.

(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nishikant ji raised his concern under Rule 216. So, he should speak as per Rule 216.

(Interruptions)

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, kindly allow me to complete. *(Interruptions)* I am very much speaking on the issue of National Highways where the Ministry of Finance is demanding amount from the Parliament. The Finance Ministry is demanding from the Parliament that this much amount has to be given to the National Highways as a Supplementary Demands for Grants. Hence, I am speaking about it.

This is one of the major issues concerning Kerala. Every day, the road is collapsing. The bridge is collapsing. People are in a fear complex and people are dying. If we do not discuss it in the Parliament, then where will we discuss it? If we do not discuss it during the discussion on the Supplementary Demand for Grants, then where will we discuss it?

Sir, my point is about this corruption. I spoke about the Azhiyur-Vengalam Project that was for Rs. 45 crore per kilometre or Thalappady to Chengala. There were seven major bridges and 17 grade-separators. This road is plain whereas there were 17 bridges there and only Rs. 43 crore was given for them. Kappirikkad to

Thalikulam has similar geography, which cost only Rs. 35.1 crore. This is a clear legalized loot. (*Interruptions*)

Sir, we have to discuss it. The hon. Minister himself once told that everything is going wrong. My point is that this should be investigated. I am saying this because this is public money, and public money cannot be taken away by some individuals. There should be a quick investigation done for it. We are demanding for an investigation into it.

With these words, I am concluding my speech. Thank you.

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : धन्यवाद सभापति महोदय । मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे सप्लीमेन्ट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, फर्स्ट बैच ऑफ 2025-26 पर अपनी बात रखने का मौका दिया ।

महोदय, सप्लीमेन्ट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के माध्यम से लगभग 41,455 करोड़ रुपये नगद खर्च के लिए अनुमोदन मांगा गया है । यह राशि ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर 1,32,268 करोड़ रूपए का एक हिस्सा है । हालांकि 90,812 करोड़ रुपये की बड़ी राशि मंत्रालयों की आंतरिक बचत से एडजस्ट की जाएगी । शेष राशि 41,455 करोड़ रूपए के लिए पार्लियामेन्ट्री अप्रूवल आवश्यक है ।

महोदय, वर्ल्ड की इकोनॉमी में प्राइसेज के बढ़ने या घटने के कारण और जन कल्याण योजनाओं के बढ़ते खर्च की आवश्यकताओं को पूरा करने लिए यह सप्लीमेन्ट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स लाया गया है । वर्तमान सप्लीमेन्ट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का बड़ा हिस्सा सब्सिडी को पूरा करने के लिए दिया गया है । इसमें एलपीजी बिक्री पर नुकसान की भरपाई के लिए 9,473 करोड़ रूपए दिए गए हैं । केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए 2,500 करोड़ रूपए दिए गए हैं । होम मिनिस्ट्री के लिए 2,298 करोड़ रूपए एवं हायर एजुकेशन के लिए 1,303 करोड़ रूपए दिए गए हैं ।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा बिहार और देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है । यह कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि वर्ष 2025-26 के सेकेंड क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी में 8.2 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ हुई है । यह देश के लिए इम्प्रोसिव है । इसके साथ ही यह देश एवं राज्यों के लिए भी एन्करेजिंग है । यह सरकार की ग्रोथ पॉलिसी और रिफॉर्म के कारण सम्भव हुआ है ।

महोदय, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है । हम जल्द ही वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं । वर्ल्ड के विकास के लिए भारत का योगदान 20 परसेंट होने जा रहा है । आज हमारा फिस्कल डिफिसिट 4.4 परसेंट होने की उम्मीद है । देश में कंपनियां कैपिटल मार्केट से रेकॉर्ड फंड जुटा रही हैं । हमारे बैंक्स मजबूती के साथ योगदान दे रहे हैं । देश में इंफ्लेशन बहुत कम हुआ है । इंटररेस्ट रेट कम हुआ है । देश की करेंट एकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है । फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत मजबूत है । आज हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स करोड़ों रुपये मार्केट में लगा रहे हैं ।

महोदय, सरकार के सुधार का ही परिणाम है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने हाई रिकार्ड के करीब है । टेक्नोलॉजिकल विकास में भी देश काफी आगे बढ़ा है । 5 जी स्टैक देश में ही विकसित हुआ है और हमने 'मेड इन

इंडिया 5 जी' भी बनाया है और आज हम 'मेड इन इंडिया 6 जी' पर तेजी से काम कर रहे हैं। आज देश में पारदर्शी नीति के कारण सेमी कंडक्टर से जुड़ी फैक्टरीज़ भी लगनी शुरू हो चुकी हैं।

महोदय, अगर हम यूनाइटेड नेशन्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें और उसके लक्ष्यों को देखें तो हमने काफी हद तक अपने लक्ष्यों को समय से पहले पूरा कर लिया है। यह देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण है।

महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र हथुआ में सबैया एयर फ़िल्ड है, जो 471 एकड़ में फैली हुई है, जो वर्ष 2020 में उड़ान योजना में शामिल हो चुकी है और उसकी पिलरिंग यानी बाउंड्री हो चुकी है, लेकिन बीडिंग की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। अतः मेरा निवेदन है कि बीडिंग प्रक्रिया शुरू कर इसे जल्द से जल्द चालू करने की कृपा की जाए।

महोदय, मैं अपनी बात रखते हुए अनुरोध करूंगा कि राज्यों में वेतन एवं पेंशन पर हो रहे खर्च के लिए भी जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान की जाए, ताकि विकास सम्बन्धी जरूरतों के लिए अधिक रकम खर्च हो सके। राज्यों के बीच बढ़ती राजकोषीय असमानता को भी कम किया जा सके।

महोदय, सबसे अधिक पूंजीगत व्यय करने वाले सड़क एवं रेलवे मंत्रालयों में वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से अगस्त के दौरान बजट आवंटन के अनुपात में अधिक व्यय हुआ है। पिछले साल की तुलना में पूंजीगत व्यय में वृद्धि एवं राजस्व में आई कमी के कारण राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हुई है। सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त करने का भरोसा है। अपने देश में दूसरे देशों की तुलना में सरकारी खर्च कम है। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सरकारी खर्च का आंकड़ा देखें, तो यह जीडीपी का 28.62 प्रतिशत है, चीन का 33.4 प्रतिशत है, ब्राजील का 46.38 प्रतिशत है, अमेरिका का 36.2 प्रतिशत है और फ्रांस का 58.32 प्रतिशत है। मेरा इसमें सुझाव है कि आवश्यकता सरकारी खर्च को घटाने की नहीं, बल्कि उसे प्रभावी रूप से खर्च करने की है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि केन्द्रीय और राज्य स्तर पर लोक निर्माण के सभी कार्य गुणवत्ता से परिपूर्ण हों। सरकार ने विकास विरोधी बाधाओं को दूर करने और उन्हें सुसंगत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, जिससे कारोबारी लोगों की सुगमता बढ़ी है। बिजनेस रैंकिंग में भारत की ऊंची छलांग दिखती है। वैश्विक जटिलताओं के बावजूद सर्विस निर्यात बढ़ने से व्यापार में संतुलन बना हुआ है।

महोदय, दुनिया भर में जहाँ 2.3 अरब लोग अभी भी खाद्य असुरक्षा के शिकार हैं, वहीं भारत में ऐसे लोगों की संख्या 33.5 करोड़ से अधिक है। दुनिया की आधी आबादी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। इसमें भारत सरकार देश की ही नहीं, बल्कि दुनिया को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता प्रदान कर रही है।

महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस डिमांड फॉर ग्रांट्स का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

माननीय सभापति : धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बजरंग मनोहर सोनवणे जी।

SHRI BAJRANG MANOHAR SONWANE (BEED): Honourable Chairperson, I rise to speak on the Bill that has been presented in this House today. I would like to submit that India is known as an agrarian country... and it is necessary to pay attention to the demands of the farmers of this country. Through you, I request that you must introduce some good schemes for the welfare of farmers.

Along with this, additional funds should be provided for the Dharashiv-Beed-Sambhajinagar railway line, and the long-pending Junnar-Ashti railway line should also get sufficient funding. The Ahilyanagar-Beed railway line has been pending for the last 1415 years; I request that you must provide funds for that as well.

The Members of this House also have limited funds. The fund for MLAs in Maharashtra is ₹ 5 crore. So, I request that the Members of this House be given at least ₹ 30-35 crore annually.

In our country, post offices are a medium of communication, but there are fewer of them in my district. I demand that more post offices be opened there. Honourable Chairperson, we are in the age of mobile phones, and the entire world depends on them, but there are no mobile towers in some parts of my district. Therefore, I demand that mobile towers be installed in such areas.

Road and Transport Minister, Honourable Nitin Gadkari, has done a lot of work, but many projects are still pending in my district. I request that you should provide funds for the 4-lane and 6-lane projects for National Highway 548D and 548C.

Honourable Chairperson, Sir, Maharashtra's healthcare system has been deteriorated, and the Central Government should provide various schemes for healthcare. Furthermore, I request that a medical college be established in my district.

Regarding education, I request that additional funds be provided for the construction of Navodaya Vidyalayas, Sainik Schools, and Kendriya Vidyalayas, so that poor students can get quality education there.

Honourable Chairperson, my district is famous as a district of sugarcane cutters. I am requesting the Union Government, through you, that a school be provided at every sugar factory for the children of these sugarcane cutters. Our India is known as a rural dominated country. I am also requesting through you that adequate seating space and proper buildings be provided for the Gram Panchayat offices, and for that necessary funds be allocated for this purpose.

I also request that a minimum of 5 lakh rupees be allocated for the Pradhan Mantri Awas Yojana (Prime Minister's Housing Scheme). I also request that you should provide funds to ensure that every household receives drinking water. Schemes like MREGS have stopped functioning in Maharashtra; these schemes receive

Central Government funding, and I request that this funding be released in time so that poor labourers can get work and wages.

I also request that hostels must be constructed for Dalit students. My final request is that you must provide school and college facilities for children from minority and Muslim communities. Thank you.

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की न केवल रक्षा की है, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

महोदय, अब मैं सदन के पटल पर रखी गयी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आता हूँ। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 41,455 करोड़ रुपए के नेट एडीशनल स्पेंडिंग की मांग की है। मैं सदन का ध्यान 7 प्रमुख आबंटनों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उन्होंने पहला आबंटन, फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 18,528 करोड़ रुपए का किया है। कुल मांग का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी 18,528 करोड़ रुपए केवल उर्वरक विभाग के लिए आवंटित किए गए हैं। आज दुनिया में खाद की कीमतें आसमान छू रही हैं, युद्ध चल रहे हैं, सप्लाई चेन टूटी हुई है, लेकिन मोदी सरकार ने तय किया है कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों का बोझ हमारे किसानों के कंधों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। यह राशि यूरिया और 'पीएंडके' उर्वरक सब्सिडी के लिए है, ताकि हमारे अन्नदाता को खाद सस्ती दरों पर मिल जाए।

दूसरा आबंटन, पेट्रोलियम और एलपीजी के ऊपर लगभग 9,473 करोड़ रुपए का किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय को लगभग 9,500 करोड़ रुपए दिये जा रहे हैं। इसका उद्देश्य तेल कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई करना है, ताकि जनता को रसोई गैस और ईंधन उचित दामों पर मिलता रहे। साथ ही, 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना- के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन जारी रखने के लिए यह आबंटन किया गया है। यह बजट का कुशल प्रबंधन है।

तीसरा आबंटन, 3,028 करोड़ रुपए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का विकास करने के लिए किया गया है। उसमें से जम्मू-कश्मीर के लिए 340 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसमें लद्दाख में बिजली खरीदना, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। हम सीमावर्ती क्षेत्रों को देश की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं।

सभापति महोदय, विदेश मंत्रालय के लिए 1,226 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। भारत की ग्लोबल छवि और कूटनीतिक पहुंच को मजबूत करने के लिए 1,226 करोड़ रुपए की मांग है। इसमें हमारे पड़ोसी मित्र देशों, जैसे मॉरीशस और पैसिफिक आईलैंड देशों की सहायता और ईरान के 'चाबहार पोर्ट' के लिए योगदान शामिल है, जो रणनीति का रूप है। यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, उच्च शिक्षा के लिए 1,303 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि हमारे डीम्ड विश्वविद्यालयों और जैसा कि कई सदस्यों ने अभी कहा कि कॉलेजों में शोध होनी चाहिए। यह राशि डीम्ड विश्व

वविद्यालय और 'प्रधानमंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' जैसी क्रांतिकारी योजना के लिए है, जिससे हमारे छात्रों और शोधकर्ताओं को दुनिया के बेहतरीन रिसर्च पेपर्स मुफ्त में उपलब्ध होंगे ।

सभापति महोदय, आयकर और बुनियादी ढांचे यानी फाइनेंस एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,831 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं । इसका उद्देश्य कर व्यवस्था को सरल बनाना, आईटी विभाग के लिए आधुनिक कार्यालयों का निर्माण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, ताकि करदाताओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें ।

महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह राज्य देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है । वह महाराष्ट्र है, वह मेरी मुम्बई है । उसकी कुछ ज्वलंत समस्याओं और मांगों को मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ । मुम्बई देश को सबसे ज्यादा टैक्स देती है, लेकिन मुम्बई की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक केन्द्रीय सहयोग की आवश्यकता है । हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछली बार बजट में कहा था कि हम लोग देश के 'घरकुल' के लिए, पीएमएवाई के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की लागत कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ की लागत देंगे, तो उसी में जैसे कि मुम्बई केवल एक शहर नहीं है, बल्कि एक मेगा-रीजन, 'एमएमआर' बन गया है ।

महोदय, लोकल ट्रेन मुम्बई की लाइफलाइन है, लेकिन अब हमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में बदलने की सख्त जरूरत है । मेट्रो का काम चल रहा है, लेकिन लास्ट माइलेज कनेक्टिविटी अभी भी एक चुनौती है । मेरी मांग है कि मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (MUTP) के अगले चरणों के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जाए । हमें ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए और अधिक फ्लाईओवर और अंडरपास की आवश्यकता है ताकि आम आदमी का ट्रैफिक में बर्बाद होने वाला समय बच सके । मुंबई हमारी नॉर्थ-वेस्ट फैली हुई है । तीनों तरफ समुद्र है और एक तरफ हिमालय की पर्वत माला है । इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 493 स्क्वेयर किलोमीटर है । मुंबई के रोड 2005 किलोमीटर लंबे हैं । ट्रैफिक से बचने के लिए आर्थिक लागत की जरूरत है, केन्द्र शासन इस पर ध्यान दे ।

वर्सोवा जेटी का आधुनिकीकरण (Versova Jetty): मेरे संसदीय क्षेत्र में वर्सोवा एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कोलीवाड़ा (मछुआरों की बस्ती) है । यहाँ की जेटी (Jetty) की हालत बहुत जर्जर है । हमारे मछुआरे भाई-बहन, जो मुंबई के मूल निवासी हैं, उन्हें अपनी नावें खड़ी करने और मछली उतारने में भारी कठिनाई होती है ।

मैं मांग करता हूँ कि 'सागरमाला परियोजना' के तहत वर्सोवा जेटी के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए विशेष फंड जारी किया जाए । साथ ही, मुंबई में जल परिवहन (Water Transport) को बढ़ावा देने के लिए रो-रो (Ro-Ro) सेवाओं का विस्तार मुंबई में किया जाए ।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management): महोदय, मुंबई रोज लगभग 6,500 मीट्रिक टन कचरा पैदा करती है । देवनार और डंपिंग ग्राउंड्स अब कचरे के पहाड़ बन चुके हैं जो न केवल पर्यावरण के लिए खतरा हैं, बल्कि आसपास रहने वाले लाखों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है । बार-बार वहां आग लगती है और जहरीला धुआं फैलता है ।

मेरी मांग है कि केंद्र सरकार 'वेस्ट टू एनर्जी' (Waste to Energy) प्लांट्स लगाने के लिए मुंबई महानगर पालिका को विशेष तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करे । हमें कचरे के निस्तारण के लिए वैज्ञानिक तरीकों को जल्द से जल्द अपनाना होगा ।

जल निकायों का कायाकल्प (Rejuvenation of Water Bodies): कभी मुंबई नदियों और तालाबों का शहर था। आज मीठी नदी (Mithi River) नाले में तब्दील हो चुकी है। पवई झील और अन्य तालाब सिकुड़ रहे हैं। वहां सीवर का पानी डायरेक्ट जा रहा है।

मैं मांग करता हूँ कि 'नमामि गंगे' की तर्ज पर 'नमामि मीठी' या मुंबई के जल निकायों के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की जाए। जब तक हम अपने जल स्रोतों को पुनर्जीवित नहीं करेंगे, मुंबई बाढ़ और जल जमाव की समस्या से मुक्त नहीं हो सकती।

दमनगंगा-पिंजाल लिंक परियोजना (Damanganga-Pinjal Link Project): महोदय, जल ही जीवन है। मुंबई को अभी 4410 एमएलडी की आवश्यकता है और हम 3810 एमएलडी पानी देते हैं। आसपास के क्षेत्रों में 2041 तक पानी की मांग बहुत बढ़ जाएगी। 'दमनगंगा-पिंजाल नदी जोड़ो परियोजना' मुंबई की प्यास बुझाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

कोंकण रेलवे का दोहरीकरण (Konkan Railway Doubling): यह सिंगल ट्रैक पर चल रही है। हालांकि विद्युतीकरण (Electrification) का काम हुआ है, लेकिन जब तक पूरी लाइन का दोहरीकरण (Doubling) नहीं होगा, कोंकण का विकास अधूरा रहेगा। मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि रोहा से मडगांव तक के पैच के दोहरीकरण के लिए इस बजट में और तेजी लाई जाए।

अवैध घुसपैठ (Illegal Immigrants): महोदय, यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा और मुंबई के अस्तित्व से जुड़ा है। मुंबई और उसके उपनगरों में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। ये लोग न केवल झुग्गी-झोपड़ियों में अवैध कब्जा कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय नागरिकों के संसाधनों पानी, राशन और रोजगार पर डाका डाल रहे हैं।

यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन (Demographic Change) भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ कि मुंबई और महाराष्ट्र में NRC की तर्ज पर एक सघन अभियान चलाकर अवैध घुसपैठियों की पहचान की जाए और उन्हें निर्वासित (Deport) किया जाए।

मुंबई में एम्स (AIIMS) की स्थापना और कैंसर केयर: मुंबई में एम्स की स्थापना की जाए क्योंकि महाराष्ट्र के लोग कैंसर के इलाज के लिए मुंबई आते हैं। मेरी सरकार से पुरजोर मांग है कि मुंबई और एमएमआर (MMR) क्षेत्र की आबादी को देखते हुए यहाँ तत्काल एक नए 'एम्स' (AIIMS) की स्थापना की जाए। महोदय, किफायती यानी एफोर्डेबल घर और भाड़े के घर ज्यादा से ज्यादा पीएमवाई के माध्यम से मुंबई में लाने चाहिए। यह मेरी मांग है।

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि यह पूरक बजट भारत की विकास यात्रा को गति देने वाला बजट है। यह 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को चरितार्थ करता है।

मुंबई और महाराष्ट्र की इन मांगों, विशेषकर एम्स (AIIMS) की स्थापना पर सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी, इस विश्वास के साथ मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत पूरक अनुदान मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूँ। जय हिंद! जय महाराष्ट्र!"

श्री राव राजेन्द्र सिंह (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं आसन और सदन के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ कि अभिव्यक्ति के ये बहुमूल्य सूक्ष्म क्षण मुझे प्रदान किये गये। इस पूरी अभिलेखों के प्रति जो व्यापक

व्यवहार चिंतन के माध्यम से इस सदन में प्रस्तुत किया गया, उसमें गंभीरता के वे क्षण भी समाहित हैं, जहां वैश्विक दृष्टि से भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिपक्ष का उदासीन वक्तव्य इस बात को दृष्टिगोचर करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्थित छवि होनी चाहिए, उस पर कहीं आक्षेप हुआ है। अभिव्यक्ति के वे क्षण सदन की सत्यता के विषय को और सारगर्भित मर्यादा की व्यवस्था को सम्पादित होने चाहिए थे, लेकिन इस बात का अचरज होता है कि कैसे शब्द के व्याकरण की वर्णमाला प्रस्तुत करने में सच को व्यवस्थित तौर पर न प्रस्तुत कर एक ऐसा अंश प्रस्तुत किया जाए, जो सच का आधा हो और सच की संपूर्णता को परिभाषित करने में कहीं न कहीं कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता है।

महोदय, मैं इस बात के लिए बड़े आदर से आपसे विवेचन करता हूँ। सम्माननीय निशिकान्त दुबे जी ने यह बात बिल्कुल सही कही कि नियम 216 के माध्यम से जब आप अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं तो आपकी सीमा अनुपूरक मांगों तक होनी चाहिए। लेकिन, चूंकि व्यापक चर्चा भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को परिदृश्य करते हुए विवेचन के रूप में प्रतिपक्ष ने प्रस्तुत कर दी तो यहां मैं एक बात आपके बीच में, आपके समक्ष रखना चाहूंगा। भारत की स्थिति आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? पूरे संसार की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक व्यवस्था और इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सामने भारत की वर्तमान सरकार और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया हुआ वक्तव्य, आज आर्थिक विश्लेषण, सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्र की व्यवस्था को विमोचित करने का पारदर्शित मार्ग प्रस्तुत करता है। उसके उपरांत भी प्रतिपक्ष इस बात के लिए बार-बार अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है कि कहीं भी इसमें सफलता की चिंगारी हमें देखने को नहीं मिलती है।

सभापति महोदय, उसी अमेरिका, जिसके डॉलर के संबंध में इतनी चिंता व्यक्त की गई है कि मैं वहीं के एक प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा दिये गये विवेचन को प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि भारत एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है।

What do you do when the worlds largest democracy decides that it no longer needs your permission?, he said, referring to America. He further said, How the United States have to behave when India, the worlds largest democracy, feels it does not require anyones permission? You push back.

This is not just about tariffs; it is about control. Right now, India is breaking free. The United States of America knows this, and it is sitting nervous. The US President has threatened tariffs on Indian exports. The official reason cited is trade imbalance, but the real reason is that India is rising fast, and Washington does not like what it cannot control.

Why are they not in a position to accept this reality? Instead of targeting the Government of India and its interests, why can they not accept the fact that someone wants to control you? But with Shri Narendra Modi ji, that is not possible, हमें इस बात की व्यवस्था को अंजाम देना पड़ेगा। Please let me know, when my time is up. भारत की स्थिति क्या है?

हम अपने ही शास्त्र उच्च चरित्र की मर्यादा में जब वैश्विक व्यवस्था का परिलेख देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको भारत की स्थिति ठीक वैसी ही नजर आती है, जो महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अपनी मैत्रिक संधि के माध्यम से कुरु के राष्ट्र को मैत्रिक रूप में एक विवेचना प्रस्तुत की थी ।

आदरणीय सभापति जी, जब अहंकार परिस्थिति के परिदृश्य में सर्वोपरि हो जाता है, तो विनाश की शुरुआत होती है । इस महाबलि राष्ट्र, जिसको आप अमेरिका के नामचर, उसके डॉलर की इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं । जब अहंकार के अंगारे से वह अपनी बात को राष्ट्र में और संसार में प्रस्तुत करना चाहता है, तो भारत का शास्त्र, उच्च मर्यादा और चरित्र इस बात का आगाज करता है कि इसका प्रतिरोध होना चाहिए । यह सदन में भी होना चाहिए और संसार के पटल पर भी होना चाहिए ।

मैं आपके बजट की अभिलेखा तक आ जाऊंगा और उसके सूक्ष्मतम बिंदु तक आ जाऊंगा । आपने यह बात बड़े तर्क से कही है कि आर्थिक स्थिति के अंदर आंकड़े क्या कहते हैं? इसके लिए मैं निवेदन कर देता हूं और अगर आपको अनुचित न लगे, तो आप उन्हें नोट कर लीजिए और वापस देख लीजिएगा । While unprecedented geopolitical risk has surfaced, आज से पहले आपने स्थिति को नहीं देखा, इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती थी ।

The fundamentals of the Indian economy remain strong. The Foreign Direct Investment in India rose by 18 per cent from year to year to 35.18 billion dollars during April-September of this fiscal year. While the inflow from US more than doubled to 6.62 billion dollars during the period according to the latest Government data released on 1st December, investment from overseas during April-September period of the fiscal year stood at 29.79 billion dollars. During the preceding June-September quarter 2025-26, the inflow increased by over 21 per cent. I am not saying this, Sir. I have not conjectured this figure. Even if I wanted to, I could not have put it in this way.

The question is this. Why are we not in a position to accept the reality? आपने अनुपूरक मांगों के माध्यम से फर्टिलाइजर्स के लिए 11,000 करोड़ रुपये, फॉस्फेट और अन्य चीजों के लिए मांगे और यूरिया के लिए आपने तकरीबन 20,000 करोड़ रुपये मांगे हैं । हमें और आपको इस बात का हर्ष होना चाहिए कि जिस प्रकार का मानसून रहा, जिस प्रकार से बारिश हुआ, हमने संभावित रूप से बजट के समय आकलन किया था कि कितनी भूमि पर एग्री एक्टिविटी होगी। अच्छी बरसात के कारण ऐसी भूमि जो एरिड या बैरेन थी, आज वह भी कल्टिवेशन में आ गयी । जब कल्टिवेशन में आ गयी, तो आपको यूरिया, फॉस्फेट, एनपीके और डीएपी सबकी आवश्यकता पड़ी। आपने उसके लिए अनुपूरक मांगों के माध्यम से सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी, तो इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है, बल्कि चिंता का विषय यह होना चाहिए कि जब 50.62 लाख करोड़ रुपये के बजट के बाद अगर आप अनुपूरक मांग लेकर आ रहे हैं, तो क्या फिस्कल डेफिसिट पर, क्या रेवेन्यू डेफिसिट पर इसका असर पड़ेगा? आपने जो टारगेट लिए थे । क्या वह उससे बाहर चले जाएंगे और वे टारगेट पूरे नहीं होंगे?

माननीय सभापति जी, मैं आज आपसे निवेदन करता हूं कि 1.9 से 1.5 प्रतिशत हमारा रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट है और हम इस टारगेट पर रहेंगे । हमने फिस्कल डेफिसिट 4.8 से 4.4 करने का वादा किया है । मुझे पूरा विश्वास है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम टारगेट के अंदर रहेंगे और अपने डिसिप्लन को नहीं तोड़ेंगे ।

मैं आज वित्त मंत्री जी से इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपये के ऊपर का जो व्यय फर्टिलाइजर्स पर है, इस बात को माननीय प्रधान मंत्री जी भी कह चुके हैं और माननीय कृषि मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हमें अपने एग्रीकल्चरल पैटर्न को डायवर्ट करना पड़ेगा। अगर आप नेचुरल खेती की तरफ जाते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाते हैं, तो एक सबसे अच्छी चीज जो कहीं न कहीं इस परिदृश्य में नहीं आ रही है कि जिस कास्तकार को, जिस कृषक को, जिस अन्नदाता को उसके प्रोडक्शन में जो कमी आएगी, आप उसकी पूर्ति कैसे करेंगे?

16.00 hrs

इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने साइंटिफिक तरीके से यह बात कही है कि अगर आप आर्गेनिक खेती की तरफ जाते हैं, परम्परागत खेती की तरफ जाते हैं या नेचुरल खेती करते हैं, तो आपके प्रोड्यूस को सामान्य बाजार भाव से कुछ ज्यादा पैसे मिलते हैं। हमारे भारत मूल की ऐसी कंपनीज़ हैं, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। एक कंपनी ने सिंगापुर से 6.32 मिलियन मीट्रिक टन का एग्रीमेंट किया है। अफ्रीकन कांटीनेंट के कृषकों की अपनी कृषि की व्यवस्था से और उस खेती के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करके, उनको ट्रेड करके उन्हें उसका लाभ पहुंचाया। इस प्रकार की व्यवस्था में नीति आयोग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और एन्वायर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर भारत के अन्नदाता को यह बात सुनिश्चित कर दें कि पैदावार के अलावा, इस प्रकार गतिविधियों से जहां से प्रदूषण में कमी हो सकती है, वहां आपको वित्तीय व्यवस्था मिलेगी।

मैं राजस्थान के संबंध में एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे पास भूमिगत पानी नहीं है। हमारे पास नदी से पानी आता है या जहां कैनाल है, वहां कैनाल से पानी आता है। कैनाल का पानी प्रदूषित हो रहा है। आप राजस्थान में राम सेतु के माध्यम से नेशनल प्रोजेक्ट ला रहे हैं या यमुना वाला प्रोजेक्ट ला रहे हैं। अगर ये सारे हमारे यहां आएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था को इससे लाभ मिलेगा।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। आपने पेट्रोलियम के लिए यहां पैसे मांगे। मैं अगर स्टैस्टिक्स में जाऊं तो बात दोहराऊंगा, लेकिन मैं एक निवेदन वित्त मंत्री जी से करना चाहता हूँ, राजस्थान जैसे और भी कई प्रदेश हैं, जैसे असम है, महाराष्ट्र में मुंबई हाई है, जहां तेल निकलता है। वर्ष 2004 में आखिरी बार रॉयल्टी पर बात हुई। आज डॉलर की कीमत बढ़ गई है। इन राज्यों को रॉयल्टी डॉलर की तुलना में मिलती है। पिछले 15 वर्षों में रॉयल्टी रीविजिट नहीं की गई। अगर हम क्लेक्शन से इतना पैसा आपको दे रहे हैं तो आपके फॉरेन एक्सचेंज में उतनी ही कमी आती है। अगर हम इंडेजिनस इस चीज को दे रहे हैं तो एक राज्य के नाते, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य की रॉयल्टी को दोबारा तय करिए। हम क्यों न इसका दोबारा अवलोकन करें? (व्यवधान)

महोदय, आपने घंटी बजा दी है। अनुपूरक मांगों से भारत की अर्थव्यवस्था की व्यस्थित स्थिति में कहीं कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत अपने आप खड़ा होकर विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में भी अपना नाम करेगा। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद।

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मेरी पार्टी का पक्ष रखने की अनुमति दी। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी, लोक जन शक्ति पार्टी (रामविलास) और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की तरफ से सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 का समर्थन करती हूँ। मैं चर्चा शुरू करने के पहले अपने यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी

का आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी नीतियों और वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है कि आज लोग विश्व स्तर पर भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। यह उनकी नीतियों का परिणाम है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है।

पिछले क्वार्टर में जीडीपी में 8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसकी चर्चा विपक्ष कभी नहीं करेगा और न ही इसकी सराहना करेगा। अगर हम जीडीपी, विदेशी मुद्रा भंडार या प्रति मास जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो ये भी अर्थव्यवस्था में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। विपक्ष के युवा नेता, जो खटाखट और फटाफट पैसे देने की बात कह रहे थे, देश से ज्यादा विदेश में देखे जाते हैं।

सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, 2025-2026 की बात करें तो पहले बैच में 1 लाख 32 हजार 268 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की अनुमति मांगी गई है। विपक्ष के नेता बार-बार पूछ रहे थे कि सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की क्या आवश्यकता है, बजट तो पेश हुआ था? मुझे यह बोलते हुए गर्व होता है कि हमारा लोकतंत्र जीवंत लोकतंत्र है और हमारी सरकार गतिशील सरकार है जो न कभी रुकती है और न ही कभी विकास कार्यों से पीछे हटती है।

16.06 hrs (Dr. Kakoli Ghosh Dastidar *in the Chair*)

महोदया, मुझे यह बताते हुए गर्व होता है कि यह पैसा कहां जा रहा है? यह सारा पैसा गरीब, किसान, महिला, युवा, दलित, वंचित और शोषित वर्गों के विकास कार्य के लिए खर्च किया जा रहा है। आबंटित राशि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एलपीजी सप्लिडी की भरपाई के लिए खर्च की जा रही है, इसके लिए लगभग 12,500 करोड़ रुपये की भारी राशि दी गई है। गरीबों के लिए गैस कनेक्शन्स, एलपीजी कनेक्शन्स के प्रोग्राम कम्पोनेंट के तहत 3178 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। अनुसूचित जाति के लिए 302 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 156 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं।

अगर हम एलपीजी सप्लिडी की बात करें तो एससी और एसटी वर्ग हेतु क्रमशः 83 करोड़ और 43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्रालय में प्रधान मंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत लगभग 2023 करोड़ रुपये की बड़ी राशि आबंटित की गई है। इससे वंचित और गरीब वर्गों से आने वाले छात्रों को विश्व स्तर पर जनर्सल रिसर्च का मैटीरियल उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन्स की बात करें तो कुल मिलाकर 235 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए लगभग 45 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। यह राशि जिन पॉलिसियों और स्कीम्स के लिए आबंटित की गई है, वे हमारी अंत्योदय की आधारशिला और विचारधारा को और मजबूत करेंगी। इससे विकास का कार्य पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा।

एक सांसद महोदया ने इसी सदन में खड़े होकर चर्चा में एक बात उठाई थी और कहा था कि अगर कांग्रेस के राज में सेल नहीं होता, इसरो नहीं होता, एम्स नहीं होता और डीआरडीओ नहीं होता तो विकसित भारत का निर्माण कैसे होता? मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि विकसित भारत के निर्माण के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। शिलान्यास करने और काम पूरा करने में बहुत अंतर होता है, इमारत की नींव को रख देने से मकान नहीं बनता। 51 सालों में आपने मात्र एक एम्स का निर्माण किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब आई थी तब जाकर पांच नए एम्स की स्थापना हुई थी। हमने 23 एम्स बनाए। आपने आईआईएम की बात कही। आपने 60 सालों में सिर्फ 13 आईआईएम बनाए और हमने दस सालों में नौ नए आईआईएम बनाए। बिहार को भी नया आईआईएम मिला है।

महोदया, डीआरडीओ की बात हो रही थी, डिफेंस की बात हो रही थी । मेरे पास इसके भी कुछ आंकड़े हैं । India recorded its highest ever defence production of Rs. 1.54 lakh crore in the financial year 2024-2025. Defence exports reached a record of Rs. 23,622 crore. आज रक्षा के क्षेत्र में 16,000 एमएसएमईज़ काम कर रहे हैं । आपकी डिफेंस डील्स की बात होती है । आप डिफेंस के बारे में जो भी कहते हैं, तब हमें नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है कि डिफेंस डील्स में आप लोगों ने क्या किया था ।

अब हम अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की बात करते हैं, हम सिर्फ अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे हैं बल्कि चुनाव रिकॉर्ड में भी अपने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं । हम बिहार से आते हैं । हम बिहार की तमाम जनता को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी सरकार को चुना, एक ऐसे गठबंधन को चुना जो नफरत और झूठी राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करती है ।

अगर सबसे ज्यादा डबल इंजन की सरकार कहीं रही है, तो वह बिहार में रही है । 20 साल बाद भी माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई एंटी इन्कम्बैंसी देखने को नहीं मिली । यह एनडीए की ताकत है । यह हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत है । चुनाव के दौरान बहुत ड्रामा देखने को मिला । तालाब में कूद-कूदकर मछलियाँ पकड़ी जा रही थीं । बिहार ने पूरे देश को बताया है कि राजनीति ड्रामा से नहीं, राजनीति नीतियों से चलती है, विकास से चलती है, नेता से चलती है और नेतृत्व से चलती है । इसी नेता और नेतृत्व ने आज भारत की अर्थव्यवस्था को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है । कांग्रेस पार्टी का बिहार में इतना बुरा हाल था कि इनका जो चुनाव-चिह्न है हाथ छाप, उसमें जितनी उंगलियाँ हैं, बिहार में इनके उतने ही विधायक अब बचे हैं । बहुत ही जल्दी बिहार में भी कांग्रेस का वही पॉलिटिकल एक्सटिंक्शन होने वाला है, जैसे दिल्ली में हुआ और आंध्र-प्रदेश में हुआ । हम बिहार की बात कर रहे हैं । बिहार में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं ।

यह बात भी हाइलाइट करना जरूरी है कि इंडी अलाएंस के बारे में मैंने पिछले सत्र में कहा था Bihar elections will be the last nail in INDI Alliances coffin. आज यह देखने को मिलता है कि मकर द्वार पर साथ में प्रोटेस्ट तो करते हैं, लेकिन इतनी शर्मनाक हार के बाद ये दोनों अलाएंस वाले एक-दूसरे से आँख तक नहीं मिला पाते ।

जिस तरीके से इंडी अलाएंस वालों ने हमारे प्रधान मंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, लोक जनशक्ति पार्टी और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं । विपक्ष वाले पहले दिशाहीन थे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि ये संस्कारहीन भी हो चुके हैं । अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार ने एनडीए को बहुत बड़ी जीत दी है, बहुत मजबूती से सरकार को एक सशक्त सरकार चुना है, इसीलिए मेरी बिहार के लिए कुछ माँगें हैं, जिन्हें मैं सभा के पटल पर रखना चाहूँगी । मैं समस्तीपुर लोकसभा से आती हूँ । मेरी ये माँग है और विनम्र अनुरोध है कि समस्तीपुर लोक सभा में भी शिक्षा के बड़े-बड़े संस्थान खुलें, लॉ यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण हो, कृषि संस्थान का निर्माण हो ।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें ।

श्रीमती शांभवी : जी महोदया, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूँ ।

पटना, बिहार में बहुत से युवाओं में टेक्निकल इंडस्ट्री को स्थापित करने का पोर्टेंशियल है । पटना, समस्तीपुर, भागलपुर जैसे एरियाज़ को नोडल एरियाज़ बनाकर यहाँ पर आईटी हब्स का निर्माण हो । आर्टिफिशियल

इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पर संस्थान बनें । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर ट्रेनिंग हो । इन सभी संस्थानों का यहाँ पर निर्माण हो, ताकि हमारा स्टॉप माइग्रेशन थ्रू इनोवेशन का जो मुद्दा है, उसे हम पूरा कर सकें ।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें ।

श्रीमती शांभवी : जी महोदया, मैं कन्क्लूड कर रही हूँ । विपक्ष को आरोप और प्रत्यारोप से बचकर अपने अंदर भी झाँकना चाहिए । आप चार लाइंस लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए की तरफ से भी सुन लीजिए ।

नज़र नहीं, नज़ारों की बात करते हैं,

ज़मीं पर चाँद-सितारों की बात करते हैं ।

हाथ जोड़कर बस्ती लूटने वाले,

भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं ।

बड़ा हसीन है, उनकी ज़बान का जादू,

लगाकर आग, बहारों की बात करते हैं ।

मिली कमान, अटकी नज़र खजाने पे,

नदी सुखाकर, किनारों की बात करते हैं ।

बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिंद । जय बिहार ।

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदया, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों, 2025-26 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । यह पूर्णतः दिशाहीन और लक्ष्यविहीन है । यह आंकड़ों-अंकों के भ्रमजाल के सिवा कुछ भी नहीं है । सरकार फर्टिलाइजर पर सब्सिडी की भरपाई के लिए यह मांग कर रही है । बिहार जैसे राज्य में, जहां गेहूँ की बुआई चरम पर है । पूरे बाजार से यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट, पोटाश जैसे प्रोडक्ट्स बाजार से गायब हैं । महंगे और कालाबाजारी के जरिए बिहार में फर्टिलाइजर बेचा जा रहा है ।

महोदया, फर्टिलाइजर एक्ट, 1985 में साफ शब्दों में लिखा है कि अगर इसकी कालाबाजारी होगी, महंगे दर पर बिकेंगे, तो कम्पनियों को सब्सिडी का भुगतान नहीं किया जाएगा । लेकिन यहां कानून का राज नहीं है, न ही बिहार के भीतर और न ही देश के अन्दर । मनमाने तरीके से कम्पनियों को फर्टिलाइजर की सब्सिडी दी जा रही है । देश में, लम्बे समय से किसानों की मांग रही है कि सब्सिडी डायरेक्ट किसानों के खाते में आनी चाहिए, सब्सिडी कम्पनियों के खाते में नहीं जानी चाहिए । लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है । पूरा बिहार में धान की फसल खेतों में पटी है, 15 से 20 दिन हो गए हैं, वे खेतों से निकलकर खलिहानों में आ गई हैं, लेकिन बिहार में इसकी खरीद पूर्णतः बंद है । अगर थोड़ी-बहुत खरीद भी हो रही है, तो वह तीन-चार सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से अवैध उगाही बिहार में चल रही है । इसकी कोई चिन्ता नहीं है । बिहार में चुनाव बीत गया । एनडीए ने नारा दिया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी लाएंगे । केवल धान नहीं, बल्कि मक्का, गन्ना और गेहूँ पर भी एमएसपी की गारंटी दी जाएगी । लेकिन चुनाव के एक महीना बीतते ही देख लिया जाए क्या स्थिति है । बाकी फसलों के क्या मूल्य मिलेंगे, जो सामने है, उसके पैसे भी नहीं दिये जा रहे हैं ।

23 एम्स की चर्चा हो रही थी। माननीय सांसद बिहार से ही हैं। उनके क्षेत्र के निकट दरभंगा में वर्ष 2016 में एम्स का शिलान्यास हुआ था। ऑपरेशनल एम्स में से एक दरभंगा एम्स का भी नाम है, जिसमें आज तक पांच ईंटें भी नहीं रखी गई हैं। कम से कम सरकार के लोग माफी तो मांग लेते। कोई बात रखने से पहले, वे जमीन पर देख लेते कि दरभंगा एम्स कहां है।

वर्ष 2017 में, मोतिहारी में महात्मा गांधी जी के नाम पर सरकार ने एक विश्वविद्यालय दिया। आज तक उसमें पांच ईंटें भी नहीं रखी गई हैं। बिल्डिंग नहीं बनी, लेकिन बिहार के बारे में बात तो बहुत ऊँची-ऊँची की जाती है।

पिछले बजट सत्र में, बक्सर से भागलपुर तक एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की बात हुई थी। बाकायदा वित्त मंत्री जी ने उसके लिए 18 हजार करोड़ रुपए देने की बात कही थी। वह परियोजना बंद कर दी गई। बजट के दौरान चर्चा में कहा गया था कि बिहार को 58,800 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज देने का काम किया गया है, लेकिन उसमें से एक्सप्रेसवे के 18 हजार करोड़ रुपए हटा लिये गये।

इन लोगों ने पीरपैती में एक बिजली घर भी लगाने की बात कही थी। 21,600 करोड़ रुपए की लागत से पीरपैती बिजली घर भारत सरकार नहीं बनाएगी। अब उसे अडानी जी लगाएंगे। लेकिन बजट के दिये गये पैसे कहां गायब हो गये? यहां पर सरकार के बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि उनको सदन से माफी मांगनी चाहिए। जब बजट पर एक बार सदन का ठप्पा लग जाता है, तो वह बाइबल, गीता और महाभारत जैसे ग्रंथों से कम नहीं होता है। अगर आपको कुछ ड्रॉप करना है, तो उसे सदन के भीतर ड्रॉप करिए।

सरकारों के द्वारा नारे तो बहुत-से गढ़े गए। बिहार में भारतमाला परियोजना के तहत एक सड़क बन रही है, जो बनारस से कैमूर होते हुए कोलकाता जाएगी। उसमें सर्विस लेन नहीं है। किसानों की जमीनों से हाइवेज़ जाएंगे, लेकिन किसानों के चलने के लिए कोई सर्विस लेन नहीं होगा। कल मैं बिहार से उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली आ रहा था। आगरा एक्सप्रेसवे, जिसे अखिलेश जी ने बनाया है, पर किसानों के लिए सर्विस लेन भी बनाये गये हैं। यह विकास होता है। अगर विकास का दोहरा मापदण्ड सीखना हो, तो गुजरात के लिए नये मॉडल्स हैं और बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के लिए दूसरे तरह के मॉडल हैं।

बिहार को बिजली घर चाहिए। लेकिन बिहार को कोयला से बिजली पैदा करने वाला बिजली घर मिला। देश में हाइड्रोजन से बिजली पैदा होगी, परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा होगी, ग्रीन एनर्जी के प्लांट्स लगेंगे, लेकिन बिहार को प्रदूषण फैलाने वाला कोयला से बिजली बनाने वाली बिजली घर दी जाएगी।

कैमूर की पहाड़ियों में अपार संभावनाएं हैं। पम्प स्टोरेज के जरिए आप नयी तकनीक के जरिए हरित बिजली पैदा कर सकते हैं। Run-of-the-River Project के जरिए बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे बिहार ही नहीं, बल्कि देश के कई हिस्सों में आप बिजली सप्लाई कर सकते हैं।

अब मैं रेलवे की बात करता हूँ। बिहार के लोग दिल्ली-मुंबई क्यों जाते हैं? वे रोजगार की तलाश में, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के लिए एम्स, दिल्ली या उच्च संस्थानों में पढ़ने के लिए जाते हैं। बिहार तक जो रेल लाइन बिछी है, अब भी वह दो लेन की है। दिल्ली से कोलकाता तक की जो रेलवे लाइन्स हैं, वे दो लेन की हैं, लेकिन रेलवे को पैसा चाहिए। बिहार में दो लेन की जगह चार लेन की रेलवे लाइन बिछानी चाहिए। आज तक मुगलसराय से पटना तक के लिए रेलवे ट्रैक मात्र दो लेन की है, वहां इतनी संकुचित है, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। बिहार तक जाने के लिए जो ट्रेन्स चलती हैं, वे लगातार देरी से पहुंचती हैं। वहां के लिए नई ट्रेन्स नहीं चलाई जा रही हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर जगह नहीं है।

यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है। बिहार के बारे में लोग लगातार पलायन के विषय पर बहस करते हैं। बिहार में पलायन क्यों हो रहा है? कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं के बराबर है। हाइवे के क्षेत्र में निवेश नहीं के बराबर है। विद्युत के क्षेत्र में निवेश नहीं के बराबर है। बिहार की आबादी देश की आबादी का 10 प्रतिशत है। हर साल के बजट में साढ़े ग्यारह लाख करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का प्रावधान होता है। अगर बिहार की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत भी है, तो बिहार की हिस्सेदारी सवा लाख करोड़ रुपये की बनती है। बिहार को कितना फंड मिलत है? पिछली बार के बजट में 58,800 करोड़ रुपये मिले थे, जिसमें से दो परियोजनाओं का 40,000 करोड़ रुपये अलग कर दीजिए, तो बिहार को मात्र 18,000 करोड़ रुपये मिले हैं। इस बार के बजट में तो वह भी नहीं मिला है। इन्होंने मुश्किल से बिहार को 19,000 से 20,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं देने का काम किया है।

बिहार के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, यह केवल बिहार के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है, बल्कि यह उत्तर और पूर्वी भारत के साथ नाइंसाफी हो रही है। इस देश में सवा ग्यारह लाख करोड़ रुपये इन्फ्रास्क्चर पर खर्च किए जाते हैं, वे ज्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों के लिए खर्च किए जाते हैं। इसलिए बिहार लगातार विकास के पैमाने पर पिछड़ता जा रहा है और वहां पलायन बढ़ता जा रहा है।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपको विशेष धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

SHRI SACHITHANANTHAM R. (DINDIGUL): Thank you very much for giving me the opportunity. The First Batch of Supplementary Demands for Grants for the financial year 2025-2026 was presented by our hon. Finance Minister on December 1, 2025. She has demanded funds amounting to Rs.18,525 crore for the fertilizer subsidy, Rs. 9,500 crore for LPG subsidies, Rs.2,500 crore for the Ministry of Home Affairs, Rs.1,200 crore for the Ministry of External Affairs, and Rs.1,304 crore for Higher Education.

On behalf of CPI(M), we have some differences with these demands. I read in a newspaper published on December 9 that a 52-year-old man, Jamuna Kushwaha, collapsed and died while waiting in the line for three consecutive days to secure two bags of urea at a distribution centre in Tikamgarh district of Madhya Pradesh. Protests against looting and the farmer's death are going on as the fertilizer crisis continues.

Another news item that I read through a newspaper earlier in August was that the Fertilizers And Chemicals Travancore Limited (FACT), which is a Central Public Sector Undertaking, is selling private companys fertilizer in its own bags. The two companies that manufacture Single Superphosphate (SSP) fertilizer have signed an agreement in this regard. FACT is facing a major production crisis as a result of the Union Governments policy. It is purchasing fertilizer from private sector as a part of an effort to avoid a major decline.

There is a shortage, and black marketing of fertilizer is occurring all over India. However, the Finance Minister is seeking approval to release fertilizer subsidy. If the subsidy benefits go directly to farmers, they can buy fertilizers anywhere. Instead, we are giving subsidies to the companies. This will be useful for black-marketeers, and not for farmers. Therefore, suitable changes should be made in the policy.

Regarding LPG subsidies, a subsidy of Rs. 300 per 14.2 kg LPG cylinder is given only to the beneficiaries of the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana scheme. As of July 1, 2025, about 10.33 crore connections under the PMUY scheme have been provided. No other person is eligible for this subsidy. While acknowledging schemes like PMUY, concerns remain regarding the adequacy of the number of subsidised cylinders provided annually, which was nine, later increased to 12, and then reduced again to nine in some proposal for the financial year 20252026.

They have noted that high recurring cost of refills - even with the subsidy - can force poor households to revert to using traditional, less clean cooking fuels like firewood. In the Pahalgam attack on April 22nd in India administered Kashmir which killed 26 civilians, the terrorist organisation Lashkar-e-Taiba was involved. After Operation Sindoor, from May 7th to 10th, all terrorist camps were demolished by drone attacks by our defence team. We all supported it even after this attack was brought to an end by the American President. Why is a car bomb explosion still occurring in the capital Delhi, near the Red Fort? What action has been taken regarding this? Is this the failure of the intelligence agencies operating under the Union Home Ministry? Or should we ask the American President to investigate this as well?

Ensure internal security, focus on the citizens instead of just the temples. From April 2nd to November 23rd, our Prime Minister visited 18 countries. Today, he added his visit to three more countries. What work did he do domestically? The only things that happened were the hoisting of the flag at Ram temple and waving the flags to the trains. What happened to the promises made during the farmers protest? Enact a law, provide fair prices for agriculture produce, implement the healthcare plan for all, immediately release PMJVK scheme funds for minorities, start post-graduate Ayurveda course in Tamil Nadu colleges, and start a rope-car scheme from Pilgrimage Centre, Palani to Tourist Centre, Kodaikanal under PRASAD scheme.

We demand immediate fund release for MGNREGA to Tamil Nadu. Do not change its name from Mahatma Gandhi to *Pujya Bapu*. We condemn the Government for

proposing the name change. We demand to procure paddy with 22 per cent moisture in Tamil Nadu. We demand to reconsider the approval of Coimbatore and Madurai metro rail projects. We demand Rs.3000 pension per month for the disabled persons instead of Rs.300 per month.

Thank you very much, Madam.

SHRI P. V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Madam, for letting me participate in this discussion on Demands for Grants. In our State of Andhra Pradesh, the State debt is rising to an alarming level. The difference in the growth of revenue and the increase in debt is huge. There is a mismatch. If you see, after the new Government has been formed in the past 18 months, the debt of the State is Rs.2,66,000 crore. It is the highest in the country that any State has borrowed. If you see the previous Government's debt for the five years - that is the YSRCP Government's debt for the five years, from 2019 to 2024 - it is Rs.3,32,000 crore according to the Minister's answer in the Parliament. The debt is really alarming and if you see the growth of debt, it is growing at a CAGR of 22 per cent in Andhra Pradesh. Right now, it is the highest in the country. The previous Government, it was just 13.5 per cent.

Madam, the Government is borrowing desperately through any possible means. If you see, recently, Andhra Pradesh Mineral Development Corporation raised debt through NCDs, through private people. They borrowed at 9.3 per cent which is very, very high for a Government to borrow. They gave a commission of 1.5 per cent, which is coming to almost Rs.150 crore, to private people. The worst part is that a part of the conditions in these NCDs is that the private people get access to the Consolidated Fund of the State. Imagine, how can the private people draw money without the Governments permission or without any official people? Most recently, right now, the Andhra Pradesh Beverage Corporation Limited has again called for NCDs for Rs.5,950 crore or roughly below Rs.6,000 crore and again with an interest rate of 9 plus percentage and a commission of one-and-a-half per cent.

I would like to recall that in the previous term, 2019-24, the Finance Secretary wrote to all the States saying that any borrowing done through Government subsidiaries or corporations would fall under Article 293(3) of the Constitution. It was clearly stated that even indirect borrowings would form part of the Net Borrowing Ceiling (NBC). Further, on 22nd August, 2022, the Finance Secretary wrote to the Chief Secretary of Andhra Pradesh stating that when the then Government wanted to borrow through NCDs through the Beverage Corporation Limited, such borrowing

would be treated as part of the States borrowing limit. Therefore, even if borrowings are routed through corporations, they are to be counted within the borrowing limit of the State.

I would like to ask the Government that, at present, the current TDP Government has borrowed through APMDC and is now borrowing through the Beverage Corporation Limited. My question to the hon. Finance Minister, through you, is this. Have the rules changed between then and now? When the previous Government wanted to borrow, it was said to be part of the borrowing limits. Is it part of the borrowing limits now or not? That is the clarification we seek from the Government.

The second point is this. When Government banks are prepared to lend at interest rate of six per cent, why does the Government choose to borrow from private parties at 9.3 per cent? Why do you want to waste public money and why do you want to pay commissions of 1.5 per cent, running into hundreds of crores of rupees? Is this not a scam? This has to be taken seriously.

And the third part is that similarly, between 2014 and 2019, when TDP was in power as part of the NDA, there was over-borrowing, and this was again deducted during the subsequent YSRCP Government between 2019 and 2024. I want to ask the Government whether it is not a very bad precedent to allow private entities to have an access to the Consolidated Fund of the State. Imagine a situation where all lenders have an access to the Consolidated Fund of the State. Everyone will impose conditions for lending to the State. What will be the situation in the future? The State will lose control, and there would not be any access for the Government to control it. This is a very bad precedent, and the Centre has to step in to ensure that such conditions are not imposed by the States. We want the hon. Finance Minister, in her reply, to speak about these bonds being raised by the Andhra Pradesh Government, which go against the rules set by the Central Government itself and against the letters written by the Central Government to our State.

Coming to MGNREGS, for the past seven months, the labour component has been pending in our State. When we met the hon. Minister, the Centre stated that the funds are ready and that we have to talk to our State. The Act clearly says the labour component has to be paid within three days. How can labourers sustain for seven months? There are nearly 90 lakh active labourers registered in the State who are dependent on this scheme. How do they sustain and how do they survive? The worst part is, we have a Minister at the Centre handling rural development from the Telugu Desam Party itself. I do not know whether Mr. Chandrasekhar is

present here or not. I do not know what he is doing. Even in his own constituency, the MGNREGS payments have been pending for the past seven months. This is a shame for our State and it is really pathetic. We demand that MGNREGS payments be released immediately, and at least someone should put some sense into the Ministers head to ensure that at least his own State performs better, especially when neighbouring States like Telangana and Karnataka are far ahead of us in MGNREGS implementation.

We oppose the privatisation of the Visakhapatnam Steel Plant. Systematically, step by step, it is being privatised. Our Party demands that Visakhapatnam Steel Plant should not be privatised and that the Government should support it by allotting mines. Without mines being allotted to Visakhapatnam Steel Plant, it will not be viable, and selling it at dead cheap rate is not an option. We oppose the privatisation of Visakhapatnam Steel Plant. The current Government has already borrowed Rs. 2,66,000 crore in Andhra Pradesh, and it requires only Rs. 4,000 crore to complete all 17 medical colleges, which the previous Government had taken up. Now, this Government is planning to sell all these medical colleges to private players in the name of PPP, which we are opposing. We have asked the Central Government to step in. The Central Government had earlier provided funds for three colleges, and we now demand that the Central Government intervene in the case of the remaining colleges as well and stop this process.

Wherever we go in Andhra Pradesh in any private hospital or any Government hospital, we see thousands of people outside the Government hospital and we do not find people outside any private hospital because they are all driven by profit motives. So, health care should be in the hands of the Government and we demand that the privatisation of the medical college should not be there.

Madam, the last issue is regarding Kadapa-Bangalore Railway Line. Madam, recently, the hon. Railway Minister said, I am ready to do this project if your State provides the matching grant. Madam, TDP Government is part of the NDA Government. Through you, I demand the Government to provide the matching grant and the funds for the complete project has to be given by the Centre because TDP and BJP are functioning as one party in the State. So, we demand that Kadapa-Bangalore Railway Line, which is important, be taken up.

Thank you very much, Madam.

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सभापति महोदया, आपने अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर पार्टी की तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद । जब बजट के बारे में श्री जगदम्बिका पाल जी ने बात शुरू की थी, तब मैं सुन रहा था । बात कुछ इस कदर शुरू कर दी थी कि लग रहा था जैसे मोदी जी के राज में 11 साल के कार्यकाल में पता नहीं देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है । (व्यवधान) अरे, सुनते चलिए, अभी सुनाएंगे । समाजवादी पार्टी एवं माननीय श्री अखिलेश यादव जी की ओर से (व्यवधान) भगवान राम जी का पात्र लेकर, जिनके नाम से चुनाव जीता है, कम से कम उनको सीट तो आगे दे दीजिए । मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ । आप भगवान राम का सम्मान तो कर दीजिए । (व्यवधान)

सभापति महोदया जी, अनुपूरक बजट की जब चर्चा शुरू हुई, तो सबसे ज्यादा यूरिया सब्सिडी के नाम पर बजट मांगा गया और लगातार किसानों के लिए न जाने कितनी बड़ी-बड़ी बातें की गईं । कुछ सच्चाइयों को आपके माध्यम से मैं सदन के साथ-साथ देश के सामने रखना चाहता हूँ । जब वर्ष 2014 में यूपीए की सरकार थी, उस समय देश के किसानों पर केवल साढ़े सात लाख करोड़ रुपये का कर्ज था, जो 11 सालों में बढ़कर 28.5 लाख करोड़ हो चुका है । उस समय प्रति किसान केवल 37 हजार रुपये का कर्ज था, जो आज की तारीख में बढ़कर प्रति किसान 78 हजार रुपये प्रति किसान हो चुका है । यह सरकार चुनिंदा कॉरपोरेट लोगों के लिए काम कर रही है । कॉरपोरेट का 16.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज माफ किया गया, लेकिन पूरे कार्यकाल में किसानों हेतु एक भी कर्ज माफ नहीं हुआ ।

सभापति महोदया जी, प्रधान मंत्री जी से लेकर समस्त भारतीय जनता पार्टी व सत्तापक्ष के लोग वर्ष 2015 से लगातार ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे । हमारे पास डेटा है । पूरे 11 सालों में किसानों की आमदनी प्रति किसान केवल एक हजार रुपये बढ़ी है । स्वामीनाथन जी के बारे में वर्ष 2014, वर्ष 2017, वर्ष 2019 व वर्ष 2022 में कहा, लेकिन आज तक स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है । यह इनकी सच्चाई है ।

सभापति महोदया जी, दूसरी बात इन्होंने रोजगार के लिए कही है । जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, जैसे कोई पेट्रोल पंप पर काम कर रहा है, कोई सेल्समैन बना हुआ है, कोई खोमचे वाला है । उनके तमाम तरह के सर्वे कराकर, फर्जी आंकड़े पेश किए । अब तो विदेशी संस्थाएं भी यहां तक कहने लगीं कि भारत की तरफ से फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं । मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ । देश की हालत यह है कि सत्तापक्ष वाले बात करते हुए कहते हैं कि हमने जीडीपी बढ़ा दी। आप सोचिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश वर्ष 2014 में 55 वें नंबर पर था और आज वर्ष 2025 में यह 123 देशों में 102 वें स्थान पर पहुंच गया है । प्रति व्यक्ति आय घटी है, किसानों का रेट बढ़ा है । प्रधान मंत्री जब वर्ष 2014 के पहले बातें करते थे, तो उस समय के प्रधान मंत्री स्वर्गीय मनमोहन जी को अपमानित करते थे और उम्र की बातें करते थे । लेकिन जब तक उनका कार्यकाल था, तब तक डॉलर के मुकाबले रूपया केवल 60 रूपये था और आज आपके समय में 90 रूपये पार कर चुका है । आप सोचो इस बात को हम किस तौर पर परिभाषित करें? आपने नौजवानों के रोजगार की बहुत बातें की ।

सभापति महोदया जी, जब हम अपनी बात रख रहे हैं, तो आज ही उत्तर प्रदेश के अंदर जिस आयोग को आपने माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में बदनाम किया, आज उस आयोग का यह हाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 53 से ज्यादा पेपर लीक होकर परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं । पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर और 11 सालों में देश के अंदर कोई भी भर्ती पूर्ण नहीं हुई है । इस समय इलाहबाद के लोक सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवान अपनी बात रखने और वहां की अनियमितताओं को दूर करने के लिए खड़े हैं । सभापति

महोदया, आप महिला हैं, आप संवेदनशील हैं, आप विजुअल्स देखकर आश्चर्य करेंगी कि किस तरह से वहां के नौजवान युवक-युवतियों पर लाठीचार्ज करके, बाल पकड़कर घसीटा जा रहा है। आज प्रयागराज और इलाहबाद में अमानवीय व्यवहार हो रहा है।

सभापति महोदया जी, बेरोजगारी को दूर करने की बहुत बातें कीं। (व्यवधान) सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपने हर साल दो करोड़ रोजगार देने की बात की और साल दर साल मेरा पास डेटा है। आज की तारीख में आजादी से लेकर अब तक अगर हमारे देश में कभी बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा बढ़ी है, तो आठ फीसदी से ज्यादा बेरोजगारी की दर आज बढ़ी है। यह भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है।

सभापति महोदया जी, ये लोग जातीय जनगणना की बात करते हैं। मुझे याद है, इस सदन में मुझे भी सौभाग्य मिला था, श्रद्धेय नेता जी, श्रद्धेय शरद जी, आदरणीय लालू जी से लेकर पासवान जी तक सभी लोगों ने वर्ष 2010 में जातीय जनगणना की मांग रखी थी। कांग्रेस के साथियों ने यह गलती की कि उस समय जातीय जनगणना नहीं करायी। इस समय जब एनडीए की सरकार ने वादा किया है, लेकिन वादा तेरा वादा, अब किसी वादे पर भरोसा नहीं रहा। हालत यह हो गयी है कि एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है इसलिए जातीय जनगणना के वादे पर भी देश की जनता को अब आपके ऊपर भरोसा नहीं है। आपने बजट मांगा है, आप बजट ले जाइए, लेकिन इस बात का जवाब आना चाहिए कि जनगणना कब हो रही है और जनगणना हो रही है, तो उस जनगणना में आप जातीय जनगणना शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा।

सभापति महोदया जी, जहां तक यूरिया का सवाल है। सबसे ज्यादा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। यूरिया के लिए अनुपूरक मांग की गयी है, लेकिन यूरिया की हालत क्या है? बिहार के साथी यहां चर्चा कर रहे थे। बिहार के बारे में आप जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में हम यह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूरिया के वितरण के लिए पूरी कोतवाली, पूरी तहसील में किलोमीटर तक लाईन लगकर, लाठीचार्ज खाकर, गर्मी, सर्दी और बरसात में किसान अपना पूरा परिवार लाईन में लगाता है, तब जाकर उसको एक या दो बोरी यूरिया मिलता है। उसमें जो यूरिया की सब्सिडी आ रही है, वह अगर किसानों तक जाए तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन यह यूरिया की सब्सिडी किसानों के पास न जाकर सत्ता पक्ष के दलालों और अधिकारियों की जेब में जा रही है। इसलिए जो इन्होंने किया है हम इस बात से सहमत नहीं हैं।

सभापति महोदया जी, चूंकि मेरे और भी साथी बोलने वाले हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि नौजवानों को रोजगार मिले। किसानों को हक और अधिकार मिले। उनको अपनी उपज का वाजिब मूल्य मिले। उनको सुविधाएं मिलें। किसानों के लिए खाद, बीज, बिजली, पानी की व्यवस्था हो। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं, बंगाल के बारे में आप जानें, बिहार के बारे में आप जानें, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पूरी तरह से बर्बादी है।

सभापति महोदया जी, एक बात और कहूंगा कि एमएसपी की बात की गयी थी, वह एमएसपी आज तक लागू नहीं हुआ है। और तो और पहले भी इस सदन में उठाया हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं कि बच्चों को दवाएं भी मिलावटी दी जा रही हैं, जहर बेचा जा रहा है। सभापति जी, अंत में मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार जहरीली दवा, कफ सिरप बेचने वालों को बचाने में लगी हुई है।

आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपका इनकम टैक्स केवल विपक्षी नेताओं के लिए है, लेकिन जो लोग डकैती डाल रहे हैं, उनके लिए आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको अहसास है कि अगर आपने ढंग से कार्रवाई कर दी तो लखनऊ वाले रूठ जाएंगे। (व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात कनक्लूड कर रहा हूं। (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री शशांक मणि जी ।

श्री शशांक मणि (देवरिया) : सभापति महोदया, आज सरकार के (व्यवधान)

माननीय सभापति : शशांक जी, आप एक मिनट रुकिये । धर्मेन्द्र जी, आप अपनी बात कनक्लूड कीजिए ।

श्री धर्मेन्द्र यादव : सभापति महोदया जी, लखनऊ वाले बचाने में लगे हैं, दिल्ली वाले कुछ कर नहीं रहे हैं । दिल्ली वाले डर रहे हैं कि लखनऊ वाले कहीं रूठ न जाए । चाहे कोई रूठे, चाहे कोई माने हमारी इस मौके पर मांग है कि जो बच्चे जहरीली दवाओं से मरे हैं, उन पर कठोरतम कार्रवाई करके उनको सजा मिलनी चाहिए । ये नए-नए अध्यक्ष बने हैं, बधाई लेते हुए कम से कम यही नेक काम कर दीजिए । उत्तर प्रदेश में जो बच्चे मरे हैं, उनके परिवार वालों के दिलों को कहीं न कहीं सुकून इस बात से मिलेगा कि आपने कार्रवाई कर दी ।

सभापति महोदया जी, आपने मुझे बोलने के लिए टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री शशांक मणि (देवरिया) : सभापति महोदया, मैं आज सरकार के वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । यह हमारी सरकार की लचीली अर्थव्यवस्था का एक तरह से अनुमोदन करता है और आदरणीय प्रधान मंत्री जी के विकसित भारत के नारे को बुलंद करता है । आने वाले समय में सब के प्रयास से इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपने देश को आगे ले जाएगी । इस बार सरकार ने 1.32 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान मांगा है, जिसमें महज 40 हजार करोड़ रुपये ही अतिरिक्त है, अन्यथा हम लोगों ने रीएलोकेट करके उस बजट में अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए पूरा सहयोग किया है । यह हमारी सरकार की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में जो एक संतुलित व्यवस्था है, उसको दर्शाता है ।

अगर आप किसी भी तंत्र का अवलोकन करें तो उसके तीन विषय होते हैं । पहला, आर्थिक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़त, दूसरा, हमारा महंगाई पर कंट्रोल और तीसरा, वित्तीय अर्थव्यवस्था में कमी । अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो पिछले एक साल में कई ऐसी चीजें हुई हैं, जो बहुत चुनौतीपूर्ण थीं । यह पूरा सदन जानता है कि पूरे विश्व में इस बार आर्थिक अव्यवस्था हो रही है । उसी के साथ-साथ इसी वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी टेररिज्म को ध्वस्त करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है । इस परिस्थिति में भी, आज की तारीख में हमारी अर्थव्यवस्था 8.2 प्रतिशत से आगे बढ़ रही है । हमारी जो इनफ्लेशन की दर है, वह 2.7 प्रतिशत है, जो पूरे विश्व की सबसे कम इनफ्लेशन दर में से है । हमारा जो वित्तीय घटक है, वह भी बहुत कम है । मेरे हिसाब से वह 4.5 प्रतिशत तक थम जाएगा । आपको जानकार खुशी होगी कि पूरे विश्व में, अगर आप आज की तारीख में ब्राजील की अर्थव्यवस्था देखें तो करीब 1.3 प्रतिशत के हिसाब से उनका जो वित्तीय अनुपात है, वह हमसे ज्यादा है । उसी के साथ-साथ युनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील और अन्य देश भी मेरे हिसाब से अनुशासित रूप से नहीं चल रहे हैं ।

महोदया, इसमें कई ऐसे अनुदान दिए गए हैं, जो आदरणीय प्रधान मंत्री जी के मोदी इकोनॉमिक्स को दर्शाते हैं और उसमें पांच सिद्धांतों के माध्यम से उन मांगों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ । पहला सिद्धांत है सबका प्रयास । दूसरा सिद्धांत है स्वावलंबन । तीसरा सिद्धांत है स्वदेशी । चौथा सिद्धांत है कि हमारा जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें दूरगामी प्रवेश । पांचवां सिद्धांत है हम लोग विकास की राजनीति को कैसे आगे बढ़ाएंगे? सर्वप्रथम, हम लोग सब के प्रयास से अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं और उसमें जीएसटी 2.0 का रिफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है । जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म से हमारी सरकार ने नागरिकों में विश्वास किया है

और उनकी जेब में करीब 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा दिए हैं। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सरकार ने अपने लोगों पर विश्वास किया है। इसके कारणवश आज की तारीख में इनफ्लेशन की दर घटी है। इसके कारणवश कई जगह बहुत बढ़त हुई है। उदाहरण के तौर पर आज की तारीख में लगभग 40 लाख गाड़ियां बिकी हैं।

उसी के साथ-साथ दो करोड़ दुपहिया वाहन बिके हैं। इस प्रकार की प्रगति तभी हो पाती है, जब सरकार अपने नागरिकों में विश्वास करती है। इस प्रकार जीएसटी बढ़त होती है। इसी के साथ-साथ इस अनुदान में आप देखेंगी कि अटल पेंशन योजना में और प्रधान मंत्री वन विजन योजना में 230 करोड़ रुपए का अनुदान मांगा गया है। उसी के साथ-साथ नाबार्ड में समावेशित फंड में 270 करोड़ रुपए का अनुदान मांगा गया है। इससे समान नागरिकों को बढ़त मिलेगी और इन्क्लूजन में फायदा होगा। उसी के साथ-साथ पशुपालन में, दुग्ध विकास में और राष्ट्रीय गोकुल विकास मिशन में यह मांग 30 करोड़ रुपए है। यह छोटी मांग है, लेकिन मेरे हिसाब से पूरे देश के किसानों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि देवरिया जैसे क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होगा और आने वाले समय में आप देखेंगी कि हम लोग सबके प्रयास से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

दूसरा विषय स्वावलंबन है। आज की तारीख में हमारे प्रधान मंत्री जी, जिनके इकॉनोमिक्स को मैं मोदी इकॉनोमिक्स कहता हूं, उनके सौजन्य से हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश आ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, मूलभूत सुधार आ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर में बहुत रिफॉर्म आया है। कई अन्य चीजों में हम लोगों ने ईज ऑफ बिजनेस किया है। आपने देखा होगा कि आए दिन हम लोगों ने लेबर रिफॉर्म किए हैं। हम लोगों ने इस प्रकार की परियोजनाएं बनाई हैं। ऐसी बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, जिसमें हमने प्रयास किया है कि प्रोसेस रिफॉर्म किया जाए। इन सब चीजों के कारण स्वावलंबी भारत अभियान आगे बढ़ रहा है। इस अनुदान में दो महत्वपूर्ण अनुदान मांगें हैं। एक वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन, जो 2,000 करोड़ रुपए का है। उसी के साथ-साथ इसमें आप देखेंगे कि ऐसे अनुसंधान, जहां पर मूलभूत रक्षा और अन्य चीजों में हम अनुसंधान करें, इसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण विजन आया है। उसी के साथ-साथ स्वावलंबन के लिए हम रक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे काम कर रहे हैं।

तीसरा, स्वदेशी। आप जानते हैं कि वोकल फॉर लोकल के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी बहुत दिनों से कह रहे हैं। आज की तारीख में, आज के परिवेश में लोकल फॉर वोकल के लिए स्वदेशी का बहुत बड़ा नारा लगाया गया है। उसके लिए देवरिया में भी मैं अमृत प्रयास के माध्यम से बहुत प्रयास कर रहा हूं, ताकि हम स्थानीय रोजगार के लिए, स्थानीय विकास के लिए काम करें।

सभापति महोदया, इसके लिए इसमें दो-तीन प्रमुख अनुदान दिए गए हैं, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। यहां पर रक्षा, पूंजीगत व्यय में नौसेना के लिए, आधुनिकीकरण के लिए 17 हजार करोड़ रुपए का अनुदान है। इस परियोजना में बाहर से 540 करोड़ रुपए का योगदान है, जिससे मैं समझता हूं कि चाबहार पोर्ट पर वैश्विक स्तर पर आजकल जो प्रतिद्वंद्व चल रहा है, उसके विरोध में हमारी नौसेना खड़ी रहेगी और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इससे लाभान्वित होगी।

चौथा, जो लगभग सबसे महत्वपूर्ण है, वह यह है कि बुनियादी ढांचों में हमने किस प्रकार से निवेश किया है। आपको जानकर खुशी होगी कि जब वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनी थी, तो कुल मिलाकर लगभग एक लाख किलोमीटर की हमारी सड़कें थीं। आज की तारीख में, सिर्फ 11 साल में उससे डेढ़ गुना, यानी एक लाख पचास

हजार किलोमीटर की हमारी सड़कें हैं। इसमें यह एक बहुत बड़ा निवेश है। उसी के साथ-साथ इनविट राष्ट्रीय राजमार्ग में 18 हजार करोड़ रुपए का अनुदान मांगा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण अनुदान है।

अंत में विकास की राजनीति के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसका पूरा-पूरा अंजाम हमें बिहार में दिखा है। बिहार की जनता ने उस प्रकार की राजनीति पर अपनी मुहर लगाई है, जिसमें एक तरह की शालीन राजनीति हो। पैसा फेंक, तमाशा देख वाली राजनीति या फिर जातिगत राजनीति पर हम अपनी राजनीति नहीं करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि बंगाली जनता भी इस प्रकार की राजनीति का चयन करेगी। रही बात उत्तर प्रदेश की, अभी सपा के लोग बैठे हुए थे। वे चले गए हैं। अखिलेश जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यहां से पंकज जी जा रहे हैं। वह हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं। वहां पर हमारी सरकार ही नहीं, हमारे कार्यकर्ता भी विकसित उत्तर प्रदेश के लिए आगे बढ़ेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे।

सभापति महोदया, मैं अंत में क्रांतिकारी क्षेत्र के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूं, उस पूर्वांचल में, जहां मंगल पांडे उठे, जहां लक्ष्मीबाई उठीं, जहां सोना स्वर्णकार उठे, जहां पर रामचंद्र प्रजापति उठे, ऐसे महापुरुषों ने हमें आज की तारीख में आजादी दी और उसकी 150 वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह होगा कि क्रांतिकारी क्षेत्र के लिए कुछ अनुदान दे। इन क्रांतिकारी क्षेत्रों में अंग्रेजी सरकार और उसके बाद पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत कम काम किया है। इन क्रांतिकारी क्षेत्रों के लिए आज की तारीख में हम लोगों को कुछ अनुदान देना चाहिए। मैं आग्रह करता हूं कि आने वाले बजट में इसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाए।

अंत में, हमने हमारी सरकार, मोदी इकोनॉमिक्स के जो पांच बिंदु आपके समक्ष रखे हैं, उनके समक्ष उद्यमिता को विकास देना है। सबके प्रयास से विकसित भारत का लक्ष्य हम लोग पूर्व प्राप्त करेंगे और उसमें उद्यमिता के लिए एक बहुत सुंदर सा संस्कृत का दोहा आपके समझ प्रस्तुत करना चाहता हूं :-

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ।

न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः

सभापति महोदया, पूर्ववर्ती सरकारों में हमारा आर्थिक सिंह सो रहा था। आज की तारीख में हमारा आर्थिक सिंह जाग गया है। हमारा आर्थिक सिंह विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है और इस पूरक अनुदानों की अनुपूरक मांगों से उस आर्थिक सिंह को और अधिक ऊर्जा मिलेगी।

जय हिंद। वंदे मातरम धन्यवाद।

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर) : सभापति महोदया, आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगे-प्रथम बैच पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इंक्रीमेंटल कैश बजट, कैश आउट गो करीब 41,455 करोड़ रुपए है, जबकि रिवाइज्ड बजट 1,32,269 करोड़ रुपए का है। इनमें जो की-मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें से केमिकल एंड फर्टिलाइजर के लिए 11 प्रतिशत इंक्रीमेंटल कैश आउट गोइंग मांगा गया है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए 48 प्रतिशत, होम अफेयर्स के लिए तीन प्रतिशत, एजुकेशन के लिए एक प्रतिशत, एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए 6 प्रतिशत मांगा गया है।

सभापति महोदया, देश जिस परिस्थिति में जा रहा है, जब मैं सत्ता पक्ष की चर्चा सुनता हूं तो उसमें डॉ. मनमोहन सिंह जी गायब रहते हैं। अनुपूरक अनुदानों की मांग की बात हो या बजट की बात हो स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह

जी की चर्चा होनी बहुत जरूरी है। ये उसमें बहुत पीछे चले जाते हैं लेकिन इन्होंने वर्ष 2014 से यह सरकार शुरू की है। मैं इन्हें थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ कि स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह जी को आपने राजघाट में जगह नहीं दी है। आप उनका अच्छा स्टैच्यू बना कर पार्लियामेंट में लगा दीजिए। वह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक रहेगा।

वे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेकर आए। डॉ. मनमोहन सिंह जी गरीबों के लिए मनरेगा जैसी स्कीम लेकर आए। डॉ. मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार के समय में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। उनके द्वारा इंडो-यूएस जैसी न्युक्लियर डील वर्ष 2008 में सक्सेसफुली पास की गई, जब कि वर्ष 2008 में ग्लोबल रिसेशन चल रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आज भी लोग याद करते हैं। यूपीए के समय में सिलेंडर का मूल्य 350 रुपए था, आज वह 1200 रुपए से ज्यादा है। यूरिया खाद का मूल्य 400 रुपए था, आज वह 1200 रुपए से अधिक है। पेट्रोल का मूल्य 60 रुपए प्रति लीटर था, आज वह 95 रुपए प्रति लीटर है। डीजल का मूल्य 55 रुपए प्रति लीटर था, आज वह 85 रुपए प्रति लीटर है। उस समय बाइक का मूल्य 50 हजार रुपए था, लेकिन आज वह 90 हजार रुपए की है। कॉमन बंदे के लिए मोबाइल रिचार्ज 150 रुपए का था, आज वह 500 रुपए हो गया है। ड्राइविंग लाइसेंस 250 रुपए में बनता था, लेकिन आज वह 5000 रुपए में बनता है। उस समय 55 लाख रुपए का कर्ज था आज वह बढ़ कर करीब ढाई लाख करोड़ रुपए हो गया है।

मैडम, आज लोग हर जगह डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार, यूपीए की चर्चा करते हैं। हमें अनुपूरक अनुदानों की मांगों में ज्यादा एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। आज हमारा एजुकेशन पर खर्च जीडीपी का तीन से 4.6 प्रतिशत है। हम चीन का मुकाबला कर रहे हैं। जिसको ये कभी मित्र बताते हैं। जब वे बात करते हैं, तो इनके पास उनका जवाब नहीं होता है। जापान जैसे देश इस पर जीडीपी का पांच से सात प्रतिशत, यूएसए जीडीपी का छः प्रतिशत, चाइना जीडीपी का 6.13 प्रतिशत, जर्मनी जीडीपी का 4.6 प्रतिशत और यूके जीडीपी का 5.3 प्रतिशत खर्च करते हैं। आप एजुकेशन का बजट बढ़ाएं। बजट पास हो गया, लेकिन उसके बाद अनुदान की अनुपूरक मांगों में एजुकेशन के लिए ज्यादा डिमांड करनी चाहिए थी। इसमें रिसर्च के लिए डिमांड होनी चाहिए थी। यहां बच्चों का ड्रॉप आउट रेट बहुत बढ़ रहा है। उसके ऊपर कोई चिंता नहीं है। सेकेंड्री लेवल एजुकेशन में यह 8.2 प्रतिशत है, मिडल लेवल एजुकेशन में यह 3.5 प्रतिशत, प्राइमरी लेवल एजुकेशन में यह 2.3 प्रतिशत है। जो ड्रॉप आउट कर रहे हैं, वे हमारी आने वाली अगली जेनरेशन हैं। पिछले पांच सालों में 65 लाख, 70 हजार बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। यह चिंता का विषय है। इनमें से 30 लाख बच्चियां हैं। इस बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि वह कैसे सही होगा?

17.00 hrs

उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वह नहीं है। सेनिटेशन की प्रॉब्लम है, टीचर्स कम हैं। हमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए समय-समय पर गवर्नमेंट स्कूल में पॉलिसी लेकर आनी होगी, तभी जाकर सिस्टम ठीक हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के लिए 4947 करोड़ रुपये मांगे हैं, पी एंड के फर्टिलाइजर-4, डीएपी के लिए पैसे मांगे हैं। अपने देश में यूरिया उत्पादन क्यों नहीं होता? यूरिया का प्रोडक्शन अपने देश में कम हो रहा है। 2023-24 में 307 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ, 33 ऑपरेशनल यूनिट्स में 25 यूनिट्स 27 साल पुराने हैं, सात से ज्यादा यूनिट 50 साल पुराने हैं। इन यूनिटों के लिए सब्सिडी देकर इनकी टेक्नोलॉजी विकसित करके यूरिया अपने देश में बनानी चाहिए। दूसरे देश से सब्सिडाइज्ड यूरिया मंगाने के लिए पैसे मांग रहे हैं, फायदा उनको हो रहा है, अपने देश को फायदा नहीं हो रहा है।

उसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एलॉटेड बजट का केवल 7 परसेंट स्पेंड किया है। पंजाब में फ्लड आया, पंजाब में फ्लड्स की वजह से बहुत बड़ी आपदा आयी, फ्लड की वजह से लोगों के घर खत्म हो गए, एग्रीकल्चरल लैंड खत्म हो गए।

प्रधानमंत्री वैसे ही पंजाब से नाराज हैं। जब से कृषि कानून वापस लिया गया है, उसके बाद पंजाब के साथ कोई न कोई ऐसी छेड़छाड़ होती रहती है। उनके पार्टी के लोगों को भी नहीं पता होता, फिर यू-टर्न भी लेते हैं। इन्होंने कहा कि हम 1600 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, केन्द्र की स्कीम है, जबकि 1600 करोड़ रुपये कैश में चाहिए था। जैसे इन्होंने मणिपुर और लद्दाख के लिए अलग से बजट रखा तो पंजाब के लिए क्यों नहीं? अब कहते हैं कि सरकार के पास 12 हजार करोड़ रुपये पड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि इसे खर्च करने की इजाज़त नहीं है। उसका नुकसान वहां के लोगों, किसानों और मजदूरों को हो रहा है, जिनके घर गिर गए हैं। आज सर्दी का मौसम है, -2 डिग्री पर टेम्परेचर चला गया है, उनको सहायता कौन देगा? उनके घर नहीं बन रहे हैं।

जल शक्ति मंत्रालय को पांच किलोमीटर एरिया को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इसमें कुछ एरिया रावी का है, कुछ एरिया गुरुदासपुर और अमृतसर का है। जल शक्ति मिनिस्ट्री नोट करें, जो भी बांध बने, वह पूरा कंक्रीट का अच्छा बांध बनना चाहिए। ये मिट्टी का बांध बनाते हैं, वहां गोलमाल हो जाता है। हर बार फ्लड आता है और बह जाता है, उसकी इनक्वायरी भी नहीं होती है।

महोदया, चाहे रावी, ब्यास या सतलुज में बाढ़ आती है, तो इनके दोनों तरफ पक्के कंक्रीट के बांध बनाने का सरकार प्रावधान करे क्योंकि जल शक्ति मंत्री जी ने महज 7 परसेंट बजट यूज किया है। फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर मंत्रालय के बारे में कहना चाहता हूं। किसानों को छह हजार रुपया साल का दिया जाता है और यह राशि वर्ष 2019 में देनी शुरू की गई थी लेकिन आज के समय महंगाई बढ़ गई है। इस राशि को बढ़ाना चाहिए। बार्डर पर खेती करने वाले किसानों के बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है क्योंकि जब गोली चलती है तो वह वहीं मौजूद होता है। उन्हें तो जॉब भी नहीं मिलती है। हर समय लड़ाई के लिए वह तैयार रहता है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ड्रग्स की भी बहुत बड़ी समस्या है। कभी मुद्रा पोर्ट से ड्रग आ रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि किसी की कार में से शराब की एक नाजायज तौर पर रखी बोतल पकड़ी जाती है तो कार के मालिक पर पर्चा हो जाता है तो टनों के हिसाब से मुद्रा पोर्ट अडाणी के पोर्ट पर ड्रग पकड़ा जाता है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। एंट्री डॉट सिस्टम होना चाहिए था। यह बार्डर स्टेट का मुद्दा है। इस मुद्दे को आतंकवाद की तरह लेना चाहिए। टनों के हिसाब से ड्रग्स, वैपन्स पाकिस्तान भेज रहा है। दो लाख लोग पहले आतंकवाद के कारण मारे गए और अब ड्रग्स की भेंट लोग चढ़ रहे हैं। एक भी पैसा सप्लीमेंट्री डिमांड में इस विषय के लिए नहीं मांगा गया है तो आप बार्डर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। 50 किलोमीटर बार्डर बीएसएफ के पास है। जब हम इतनी आपदा झेलते हैं तो क्यों नहीं बजट बढ़ाया जाता है।

महोदया, पंजाब देश के साथ खड़ा रहता है। मेट्रो सिटीज से आने वाले लोग अपनी तरक्की कर लेते हैं, लेकिन बार्डर एरियाज में तरक्की नहीं होती है। पंजाब बीएमबी के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की। यूनिवर्सिटी का मसला इन्होंने खड़ा कर दिया। चंडीगढ़ का मसला इन्होंने खड़ा किया। क्यों बार-बार पंजाब को छेड़ा जाता है? हरियाणा हमारा छोटा भाई है। हरियाणा में नई राजधानी बना दो। इसके लिए कोई चिंता नहीं की गई है, सिर्फ राजनीति करने की चिंता है। अमृतसर एक ऐसा शहर है जो ट्रेन और एयरपोर्ट दोनों से कनेक्टेड है। इस सिटी को डेवलप करना चाहिए। वहां आईटी हब होना चाहिए। वहां के नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। हमारे लिए सेना में कोटा फिक्स कर दिया है। जब हम लड़ने वाले लोग हैं, हम शुरू से दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ते हैं तो हमारा कोटा आर्मी में कम क्यों करते हैं। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि कभी बांटा गया, कभी लूटा गया पंजाब जितनी

बार उठा धोखा करके गिराया गया । अभी अणख वाले पंजाबी जिंदा हैं और पंजाब बचाने की हिम्मत रखते हैं, आप चाहे कुछ करो या न करो लेकिन हम अपने जिंदा रहने की गवाही देंगे ।

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Thank you, Madam. A Supplementary Demand for Rs.1,30,000 crore has been sought for different Departments and Ministries. I feel that serious introspection is very much necessary, especially with regard to the financial management of our country. It is high time to recast our financial management system. Considering the limited time available to me, I will pinpoint only a few suggestions relating to financial management.

Let us have a critical analysis of the causes of delay in budget work implementation. That is my first point. These delays stem from financial, administrative and procedural bottlenecks across different levels of Government - the Centre, the States and the implementing agencies.

Similarly, financial and fund flow issues are very important. There are delayed and unpredictable fund releases, and exorbitant delays in the transfer of the Central share of funds to State Governments or programme implementation agencies. This is also a major cause of delay.

Likewise, the late release of the State share is another issue. Often, there is a delay in releasing the matching share, which is mandatory for the schemes. There are also cash management problems, such as parking of funds by implementing agencies outside Government accounts, leading to incorrect reporting of the financial position.

Another hurdle causing delays is unrealistic estimates. Planning and administrative deficiencies, including inadequate project planning, poor forecasting, unrealistic timelines and insufficient preliminary work, for example, the lack of thorough feasibility reports etc. Such kind of things are adversely affecting implementation.

There is also a slow decision-making process, with lengthy and multi-layered approval mechanisms, slow sanctioning of annual action plans and bureaucratic delays. Unless these issues are addressed, we will not be able to tide over this crisis.

Capacity constraints are another important concern. It is also an important issue. There is a shortage of quality human resources and

inadequate technical capacity in Government departments for effective planning and execution. This obstacle also needs to be addressed properly.

Finally, clearance delays are a major issue. The time-consuming process for obtaining environmental, forest and other statutory clearances cause significant delays. This aspect also kindly be addressed.

Let us examine this. Where are we now? What is our position now? We claim India as the fastest developing economy. Is it a ground reality or should we re-examine it? It is the need of the hour to streamline our methodologies in accordance with the speed changes are taking place worldwide. We have to realize that. Our old slogan was there. What is that old slogan? That is, survival of the fittest. Now, that has been changed. This era is survival of the fastest. We have to take that also into consideration.

Now, I come to the financial reforms. There are many recommendations. In our country, there are many useful recommendations. But unfortunately, we are going in the reverse. It is a fact. The financial reforms are going on in the Indian style. I would like to say about Indias Foreign Direct Investment. We want money. We are having our own difficulties. But at the same time, for Indias Foreign Direct Investment, privatisation is paving the way for the multi-nationals at the very existence of our Public Sector. We have to realise this. A lot of discussions are going on in different parts of the world on globalisation, liberalisation and privatisation but India really wants Indianization of globalisation. We must think in that way and a kind of broadmindedness should be there.

Examine India then and now. What was Nehruvian Economic Philosophy? Nehru Ji had a vision. Our Government also had a vision. We were doing it that way. But what is the contemporary situation? This is very important. We have this kind of vast experience. That also may kindly be examined.

The next issue is importance of multi-national companies. India is having its own difficulties. We are facing difficulties. At the same time, the multi-nationals are coming in a big way and spoiling the entire situation.

I want to tell about the challenges. In the various parts of the country, alarming situation is there. This is pertaining to a very important thing. In a country, whatever may be the reforms, the most important thing is harmony and peace. What is happening in this country? We know that the economy is moving in a different way. Peaceful atmosphere is not there. My learned friend was saying

about the UP and other things. In a country like ours, if there is an issue of safety of property and life, it is something very sad.

In the end, I would like to say one thing. India is a country of peacefulness. We have adopted a glorious tradition. We have to keep it up. I would like to say that the marginalized section in this country is going from bad to worse.

I hope that the Government will address that. I wish that the wisdom may prevail on the Government.

With these few words, I conclude, Madam. Thank you, Madam.

SHRI GURMEET SINGH MEET HAYER (SANGRUR): Thanks, Honble Chairperson Madam, I would like to speak about 2-3 ministries. Time and again, Vikasit Bharat is being discussed here but it is a fact that the parameters on which the developed countries are assessed dont find a mention therein. These parameters consist the factors from human happiness index to per capital income index also and accordingly, we dont stand even in top 100 countries.

One such important factor of hunger index is linked to our Anganwari workers where we stand at 102nd place amongst 123 nations. Starting from birth of a child, their education and health, and making the Anganwari workers aware, the workforce working in major institutions is doing the maximum work but to their misfortune, the Anganwari workers are being exploited and not even being considered as employees. In our country, the basic pay or the minimum wage is 9 to 10 thousand rupees. Is it not exploitation when we extract work from them by giving Rs.4500/- only and their helpers are paid only Rs.2250/-. In a country where 32% of the children are facing malnutrition, should we not increase their wages.

So, I demand that they should be made permanent and their incentives should be increased. Apart from this, lacs of people are below poverty line in our country and under PDF system when National Food Security Act came in force in 2013 and after that ceiling was done in 2015 on the basis of 2011 census and 51% of population of Punjab was under the poverty line which came as 1,4145000 and as on date, even after more than 10 years of the Act and 14 years after the census, the number remains sthe same. After that, the population increased drastically and also Covid pandemic erupted, still lacs of poor people have to be provided ration cards. Still it is not clear when the census will be conducted in next 2-3 years. So I demand that the lacs of such poor people should be issued ration cards.

Honble Chairperson Madam, my next point is that the Commonwealth games are expected to be assigned to India in 2030 but the matter of sports has not been discussed in the supplementary demands. A few days ago, I met the Minister for Sports and made a demand that substantial amount should be given to Punjab under Khelo India programme but he advised that current they didnt have funds but it will be made part of additional demands.

Kindly see that I have perused the entire list but nowhere the funds have been demanded. I have to humbly state that the state of Punjab has contributed a lot in sports and you will see that not a penny has been given to Punjab in the last one year but the state of Gujrat which has never earned a single Olympic medal in history has been given Rs.426 crore. Therefore, I demand from the Government that the ratio for allotment of funds under Khelo India programme should be followed according to the performance of the concerned state. Medals are being wown by Haryana and Punjab but the funds to the tune of Rs.426 crore are going to Gujrat. We are not seeking the similar funds but our right must be given.

In the last Olympics, our medals were 8 and Haryana got 7 medals but Gujrat never earned a single medal for India in the history of Olympics. In a village named Sansarpur of Punjab, has 7 medals to its credit and single rupee is not being given to us. So, I demand from the government that in order to promote the sports in the country, the states contributing to the medal tally must be given their due. Mr Ola has highlighted the issue in the last few days and Mr Kang also raised the issue.

Recently huge floods created havoc in Punjab. It was such a big calamity that Ravi river got 14 lac Cusecs water this time as compared to 11 lac Cusecs water in 1988 floods resulting into damage of thousands of

crores to Punjab. Public infrastructure, schools, colleges and roads got damaged and this damage was estimated at least Rs 20000 crores.

Just 30 seconds, Madam.

Central ministers made frequent visits to the state and Prime Minister sahib also came. We expected that Punjab which was discriminated in the past would be compensated this time. Rs 1600 crore was declared but we were not given even a paisa. So, I request that the Central government must compensate at least Rs.20000 cr for the damage to Punjab.

SHRI SUBBARAYAN K. (TIRUPPUR): Madam Chairperson Vanakkam. On behalf of Communist Party of India, I wish to present my views on the Supplementary Demands for Grants for Rs 1,32,000 Crore. The Government of the Day claims that India as the fourth largest economy of the world and a 4 trillion dollar economy. But if you see the reality, there is a big difference between what they say and what actually is. What is the view of International Monetary Fund, IMF? It has given C Grade to our economy. Mr Trump is very close to our Prime Minister Shri Narendra Modi, What is he saying? He calls our economy as a dead economy. What the practical experience tells us? As many as 80 Crore people are living by getting free ration of wheat in our country as per the statistics of the Government. Crores of Indians are unable to earn for themselves and purchase goods to suit the needs of their families. Purchasing power has come down. Is this an ordinary issue? Is it not a serious issue to say 80 Crore people live by getting wheat through free ration? Hiding all these facts they continue to say that we have become a bigger economy. They claim that they have brought the inflation down. Crores of Indians do not have houses to live. The Schemes announced by the Government are insufficient while we think of our huge population. They are useless. People are unable to earn to look after their monthly expenses. They speak more but nothing is concrete or visible in their actions. The way they handle naxalism is also not good. The Communist Party of India does not accept any form of terrorism. Whether it is right wing extremism or other forms of extremism. We oppose everything.

17.21 hrs (Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

But in the name of taking action against the Maoists, Home Affairs Ministry is engaging in excesses. Even after their statement for coming to dialogue, this Government is trying to attack and destroy them. This is not good. In a democratic set-up, dialogue and discussion are ways for finding solutions.

When these people are ready to cooperate in having dialogue, Government is not agreeing to their proposal. Tribal people living in the entire stretch of Dandakaranya Forests are being attacked by the Forces. They are attacked in the name of being terrorists and Maoists. This is strongly condemnable. Vedanta Company and other Companies providing FDI are allowed by this Government to exploit the natural resources of this region. The natural resources of this region are exploited and taken away by these companies. When the tribal peoples try to stop this exploitation of natural resources, they are targeted and attacked in the name of Maoists which is unacceptable. This is strongly condemnable.

I want to say only relevant issues. There are 23 Mills in India run by National Textile Corporation, NTC. There are 7 NTC Mills in Tamil Nadu. There are thousands of labourers working in these Mills. I want to highlight the fact that how irresponsible this Union Government is. If these NTC Mills are made operational, it would benefit thousands of labourers of our country. Cotton fabric and textile production will increase. But all these mills are closed. Is this right? No it is not at all right. There are 7 NTC mills in Tamil Nadu. The workers are not even given half the wages. These are all violations of law. The NTC mill are to be revived and all 23 mills should be made functional so as to provide employment to these workers. You claim to have provided employment to 2 Crore people. But this Government has not given any employment. We give suggestions to make all these 23 NTC mills to be made operational so that employment may be generated. I Urge that this should be immediately done by this Government.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI SUBBARAYAN K.: Within one minute I will conclude Sir. I will conclude by saying this issue. When we criticize the Government, you say that the Opposition parties are into criticism. But even the top economic experts of our country say that there is manipulation in the data provided by the Union Government. With all this manipulated data, you claim to say that India is a developed economy and that is not good. Only the Opposition parties have to expose this to the general public. Vanakkam. Thank you.

SHRI RAHUL KASWAN (CHURU): Sir, thank you for allowing me to speak on the Supplementary Demands for Grants, 2025-26. सर, दो-तीन मंत्रालय की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर ही मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड समय है ।

सर, जो मुख्य महत्वपूर्ण इश्यू है, वह डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर की डिमांड है, जो 31,063 करोड़ रुपये की एडिशनल डिमांड्स रखी गयी है । इस देश में फर्टिलाइजर्स की जरूरत दिन-प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है कि राजस्थान के एक रिकॉर्ड के अनुसार पिछले साल 18 प्रतिशत की वृद्धि प्रति हेक्टेयर हो चुकी है । आईसीएआर के द्वारा एनपीके का 4:2:1 का जो अनुपात है, वह बढ़ते हुए आज 23:6:1 तक पहुंच गया है । हालात यह है कि जब भी सोइंग का टाइमिंग आएगा, उस समय किसान यूरिया, डीएपी के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है । आज हमारे राजस्थान के अंदर यह हालत हो गयी है कि लोगों ने अपने आधार कार्ड्स को लाइन में खड़ा करके छोड़ दिया है और एक आम आदमी यह देखता रहता है कि कब नम्बर आएगा । राजस्थान सरकार का आलम यह रहा कि जब किसान यूरिया की डिमांड के लिए लाइन में खड़ा होने गया और जब वहां पर भगदड़ मची तो राजस्थान की सरकार की पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करने का काम किया । फर्टिलाइजर्स की इतनी किल्लत हो रही है तो हमें इसे समझना पड़ेगा कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही है, पर वह डिमांड एक्चुअल डिमांड में नहीं दिख रही है । केन्द्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार ने जो डिमांड्स रखी, उसे हमने पूरी कर दी और राज्य सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही है ।

सर, एकचुअल सोइंग एरिया में जो यूरिया और डीएपी की एकचुअल रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में सही डेटा कभी भी जिले से जाता ही नहीं है। हर साल जब भी सोइंग का टाइम आता है, उस समय किसान उसके लिए लाइनों में खड़ा हो जाता है। उस समय यूरिया, डीएपी की ब्लैक मार्केटिंग होती है। अनेक रिपोर्ट्स हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ब्लैक मार्केटिंग के कारण गुजरात, केरल, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक के अन्दर डायवर्जन हुआ है। 70,000 बैग्स अकेले गुजरात में पकड़े गए, जब यूरिया की सप्लाई ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू इंडस्ट्रीज़ को की गयी।

सर, मेरा सरकार से यह कहना है कि आपको इस प्रॉब्लम को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप फर्टिलाइजर्स की एकचुअल डिमांड को कंस्टीट्युन्सी से डायरेक्ट उठाएं। किसान को परेशान करने का सबब यह सरकार बनाती जा रही है।

सर, वर्ष 2023-24 में जो 314 लाख मीट्रिक टन की हमारी डिमांड्स थी, उसमें हम आज भी डेफिसिट में हैं। हम आयात पर निर्भर हैं। दूसरी तरफ सरकार ने तीन अलग-अलग बातें कहीं - ज़ीरो बजट फार्मिंग, नैचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका कोई पैरामीटर ही नहीं है। अगर आज कोई किसान इन तीनों कॉन्सेप्ट पर, जैसे नैचुरल फार्मिंग के ऊपर चला भी गया तो वह अपनी प्रोड्यूस को किसको बेचेगा? उसको कौन खरीदने वाला है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, नैचुरल फार्मिंग या ज़ीरो बजट फार्मिंग की जो प्रोड्यूस है, क्या हमने उसके लिए कोई एमएसपी निर्धारित की है? हमारे पास ऐसी कौन-सी टेक्नोलॉजी है, जो मंडी में यह डिसाइड कर दे कि यह ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है या नॉर्मल प्रोड्यूस है? उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है।

सर, मैं चुरू, राजस्थान से आता हूँ। वहां 13.5-14 लाख हेक्टेयर लैंड है, जो कल्टीवेबल है। उसके अंदर आज की तारीख में भी हम 80 प्रतिशत रेन-फेड इर्रीगेशन पर निर्भर हैं। उसके बाद लोगों ने नैचुरली ही हमेशा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया, पर सरकार की हैंडहोल्डिंग ही नहीं थी और यह हैंडहोल्डिंग नहीं होने के कारण धीरे-धीरे वह भी फर्टिलाइजर की तरफ बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आपने फर्टिलाइजर्स की जो डिमांड्स रखी है और आप जो अलग-अलग स्कीम्स को लेकर चल रहे हैं, उसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूँ कि आज हमारे 93 प्रतिशत लैंड में ऑर्गेनिक कॉन्टेंट (ओ.सी.) गिरते हुए इतना नीचे तक आ गया है कि without DAP and urea, you cannot even think of doing agriculture in the country right now.

सर, मेरा सरकार से यह निवेदन रहेगा कि आप इन तीनों चीजों को को-ऑर्डिनेट कीजिए। एक तरफ ज़ीरो बजट, ऑर्गेनिक, और नैचुरल फार्मिंग की बात है और दूसरी तरफ यूरिया और फर्टिलाइजर्स की डिमांड्स बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि दोनों विभागों के बीच को-ऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है।

सर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 18,837 करोड़ रुपये की एडिशनल रिक्वायरमेंट मांगी गयी है। आज की तारीख में, इस सरकार ने क्लेम किया, कि वर्ष 2014-2024 के बीच 90,000 किलोमीटर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग इस देश में था, वह आज बढ़ कर 1,48,000 किलोमीटर हो गया है। यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पर क्या आपको यह पता है कि आज भी हिन्दुस्तान में 1,48,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का 70 प्रतिशत 4-लेन से कम का है। 2-लेन भी पेव्ड शोल्डर का रह गया है। हालत यह है कि हमारे ज्यादातर राजमार्ग, जो 30-40 प्रतिशत राजमार्ग 4-लेनिंग के हैं, वे इस देश में ओवरस्ट्रेड हैं।

सर, आपने गाइडलाइंस दी हैं कि 10,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) के ऊपर जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा, उसे हम 4-लेनिंग करेंगे, 25,000 पीसीयू से ऊपर है तो उसको हम 6-लेनिंग करेंगे और अगर 50,000 पीसीयू से ऊपर है तो फिर हम नया हाईवे बनाएंगे। राजस्थान में जयपुर से निकलने वाला हर राष्ट्रीय राजमार्ग डबल ऑक्चूपेसी पर चल रहा है। जयपुर से किशनगढ़ का राष्ट्रीय राजमार्ग, आज की तारीख में 50,000 पीसीयू के लिए डिजाइंड हाईवे के ऊपर 1,18,000 पीसीयू का ट्रैफिक है। (व्यवधान) वहां एक साथ हाईवे पर 100 लोगों ने जान दी, उसको कोई संभालने वाला नहीं है।

सर, इस मिनिस्ट्री के ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए। आज भी हमारी लॉजिस्टिकल कॉस्ट 16 परसेंट है, जो अभी भी वर्ल्ड में हाइएस्ट है। (व्यवधान)

सर, मैं आपसे दो मिनट का समय चाहूंगा। इरीगेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके ऊपर सरकार ने बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया। इस बजट में कहीं पर भी इस बारे में चर्चा नहीं है। राजस्थान में हरिके बैराज है। इसमें तीन नदियों का पानी आता है। इस बैराज का पानी हमें मिलता है। इन तीनों नदियों का पानी हरिके बैराज में इकट्ठा होता है। 75 हजार हेक्टेयर लैंड में यह बैराज है। उसकी डिस्ट्रिंग पिछले कई सालों से नहीं हुई है। हर साल 2 एमएएफ पानी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में पीने का पानी भी कम है। वहां खेती के लिए पानी नहीं है। इरीगेशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस कहीं भी नजर नहीं आता है, जिससे किसानों को पैसा मिले। (व्यवधान)

सर, आपने मुझे बहुत ही कम समय दिया है। चूंकि मुझे बहुत से इश्यूज उठाने थे। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिवेस्ट करना चाहूंगा। उन्होंने डबल इंजन के नाम पर वोट मांगे हैं। एक इंजन दिल्ली का और दूसरा इंजन जयपुर का है। ये दोनों इंजन ट्रेन के अपोजिट साइड में जुड़ गए हैं और ट्रेन चल नहीं पा रही है। ट्रेन वहीं पर खड़ी हो गई है।

सर, भागीरथ का नाम दिया, लेकिन यमुना लिंक के पानी का नाम कहीं भी चर्चा में नहीं है। उसके लिए कब फंडिंग अलाऊ होगी, ताकि चुरू जिले की एक लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो सके? मैं सरकार से मांग करूंगा कि आप यमुना लिंक के रिवर के पानी के लिए जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का काम करें।

DR. C. N. MANJUNATH (BANGALORE RURAL): Thank you very much, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants First Batch for 20252026.

Despite global challenges and adversities, Indias economy stands firm-footed with a very low inflation rate, and GDP is still growing at 6.4 per cent. Although it was 8.2 per cent in the last quarter, on an average, it remains around 6.4 per cent.

India has done very well in the sky, on the ground, as well as at sea. In the sky, we can see BrahMos missiles, drones, and jet fighters which are all indigenously made. On the ground, we see an excellent infrastructure, including world-class highways, railway stations, and airports. In fact, the airports of tier 2 and tier 3 cities are crowded, indicating that the economy is booming. People now have a lot of money in their hands because income tax is exempted up to Rs. 12 lakh, which results in

Rs. one lakh crore being put into the hands of the people. Recently, due to GST exemption, people are also having a lot of money in their hands. So, this is one of the important aspects.

Yes, the hon. Prime Minister is working on the noble concept of Vocal for Local. It is not just Vocal for Local; it is also Local for Global as every fourth generic tablet sold in the world comes from India, and every fourth mobile phone used in the United States is also from India.

If we look at the defence sector, last year, defence exports stood at Rs. 30,000 crore, and the total defence production is Rs. 1.2 lakh crore. We particularly consider semiconductors to be digital pearls. India is spending more than Rs. one lakh crore on semiconductors and is also providing a lot of subsidies on fertilizers as well as electric vehicles. A massive subsidy is extended to the semiconductor zone.

Sir, coming back to health, Ayushman Bharat is one of the worlds largest health insurance schemes, under which more than 50 crore beneficiaries have been enrolled and about nine crore procedures have been carried out. We truly appreciate the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister because now people above 70 years of age, irrespective of their financial status, income or background, are included under Ayushman Bharat. The coverage is up to Rs. 5 lakh for the entire family. Since people above 70 years generally suffer from multiple co-morbidities such as diabetes, hypertension, malignancies, prostate issues and joint problems, I urge the Government to extend this coverage from Rs.5 lakh to at least Rs.7.5 lakh per family so that adequate treatment can be ensured.

Further, there has been more than a doubling of medical colleges in the country. Today, there are about 820 medical colleges, with a total capacity of around 1,23,000 MBBS seats. We have nearly 19 lakh allopathic doctors and about five lakh AYUSH doctors. Yet, we continue to see that many doctors are not willing to work in village hospitals, semi-urban areas and rural hospitals. This shows that the issue is not a shortage of doctors, but maldistribution. More doctors are concentrated in cities, while fewer are available in rural areas. Therefore, I strongly urge the Government to enhance the salaries of doctors working in rural and semi-urban hospitals.

Secondly, we must incentivise MBBS doctors to serve in rural hospitals. One measure that can be considered is granting additional marks in the NEET PG examination to motivate them to work in rural hospitals.

We also have CGHS hospitals in Bengaluru city. There are more than 250 Government of India establishments, employing about four lakh Central Government employees. However, while cities like Chennai and Hyderabad have around 15 CGHS wellness centres for a similar number of beneficiaries, Bengaluru city currently has only about 11 CGHS wellness centres. Therefore, I request the Government to set up at least five additional CGHS wellness centres in Bengaluru.

We also have Jan Aushadhi centres. Nearly 16,000 Jan Aushadhi centres are functioning across the country, and in our State alone, there are about 1,480 Jan Aushadhi centres. It is because of Jan Aushadhi centres, nearly Rs.30,000 crore to Rs.40,000 crore has been saved for patients. On the same lines, we should also consider introducing the Jan Aushadhalays for animal and plant so that feed and nutrients meant for animal and plants can also be made available to farmers at subsidised rates.

Sir, Karnataka is known as the land of sandalwood, and is often called the Sandalwood State. Nearly 65 per cent of the countrys sandalwood comes from Karnataka. At present, each State has its own regulations regarding the cultivation, transportation and trade of sandalwood. Under the NITI Aayog, the Central Vista Oversight Committee has appointed a Central Sandalwood Development Board to give recommendations under the concept of One Nation, One Sandalwood Policy. They have recommended the establishment of an All-India Sandalwood Board on the lines of the Coffee Board and the Spices Board, to be located in Bengaluru under the Ministry of Commerce and Industry.

Finally, I am very happy that ragi has been given a very good Minimum Support Price of Rs.4,886. However, I request the Ministry to consider providing a better price for paddy, and also to ensure procurement of jowar and maize in our State. Thank you, Sir.

SHRI OMPRAKASH BHUPALSINH ALIAS PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD):

Today, I rise here to speak on supplementary demands forof grants. I keep listening in the house that, India is becoming 5 trillion dollars economy. I am not an economist, but I understand one thing that, 60-70 % people in this country depending on agriculture. Irrigation, facility electricity, and production cost based

MSP stated by Swaminathan Commission are main components of farming. Farming will not be beneficial till a good amount of MSP is offered to farmers, and till then 5 trillion dollars dream will not be possible.

I keep listening that highways and metros are building in the country. Atal Bihari Vajpayee had dreamt of river linking. I wanted to ask question to government why we cant allocate the funds in the budget for river linking projects?

Honble Chairperson, you will notice that, when there is favorable monsoon season for farmers, crops produce good amount of wealth. It is also helpful for grocery, jewelry and auto sectors and they earn well. When natural condition are harmful and out of the control of farmers or doesnt get the expected MSP the said sectors dont perform well. Thats why government needs to change the point of view when it makes policies for the farmers. Government should also think for positive policies for profitable farming sector.

I wanted to raise question regarding my state Maharashtra. The rivers flowing from west like Vaitarana, Ulhas flow into a sea at the end. Government of Maharashtra gave permission on September 2025 to divert this water. It was decided to bring 55 TMC water from these rivers to Marathwada region.

The DPR should complete by December 2025. This project needs 70 thousand crore rupees. If this fund gets allocated, 70 TMC water will be available to Marathwada area.

Please understand the importance of this project for Maharashtra. If we able to divert the extra water from Nar, Par, Damanganga, Waitarna, Ulhas rivers to Godavari river then that will be a great benefit to the farmers of the Marathwada. Farmers will prosper by getting water for farming and irrigation.

From the June to September 2025, there was a flood like situation in my Dharashiv constituency. Farmers are affected very much due to heavy rains. Around 5,77, 544 hectares area is badly affected due to flood. Government of Maharashtra declared package of 31,628 cores for affected farmers, but only 14,000 cores rupees have been received till date to farmers. Still 17,628 cores rupees needs to be received.

I asked the question in the question hour that, what kind of help given to the state government to fight this situation. Government replied me that, the proposal is yet to be received from the state government. I request government to speed up the process and relief should be given to the farmers.

I want to inform this house the total count of farmers suicide in my region from 1st January to 30th October 2025. In Chhatrapati Sambhaji Nagar: 112, Jalna:32, Parbhani:45, Hingoli:33, Nanded:90, Beed:108, Latur:47. This number is very disappointing for all of us.

There is a GST imposition on fertilizers & pesticides used for farming. But, farmers dont know how to get the paid GST. Farmers are last consumers in this chain. That is why, I request government to cancel the GST on seeds, fertilizers & pesticides purchased by farmers.

The railway project was declared in 2014 for the route Solapur - Tuljapur-Dharashiv. Around 3200 crore rupees was the total costing for

the said project. State government guarantees for half the payment, but till date not a single rupee is given to the project. Tuljapur to Dharashiv work has began but not even a tender has been floated for Solapur- Tuljapur route. The dream of Tuljabhavani devotees to travel from Solapur to Tuljabhavani is still incomplete.

There are two things that I wanted to mention here about my constituency for the consideration of the central government. The logistic park should be built at Dharashiv MIDC area. The alignment for Dharashiv city in the context of Surat - Chennai is pending. I demand, a road should be built from Vizag to Dharashiv city which needs funds worth Rs. 1365 crores.Thank you.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, on behalf of All India Trinamool Congress, I rise to speak on the Supplementary Demands for Grants, 2025-26 with a sense of *déjà vu*.

Every year we pass the Budget with grand claims and booming confidence. And every year, without fail, the Government returns quietly with a tray full of supplementary demands, as if the original Budget was just a polite suggestion, not a financial plan for the worlds largest democracy. This year, the Government needs Rs. 1.32 lakh crore more. At this point, I feel the Budget is just the trailer. The real movie is the Supplementary Demands for Grants. This is not unforeseen volatility. This is systemic failure masquerading as normalcy. Take, for example, fertilizers. The estimate is Rs. 1.67 lakh crore; the revision is Rs. 1.92 lakh crore; and the new demand is Rs. 18,525 crore more. Fertilizer consumption grew by 16 per cent and subsidy jumped to 130 per cent. Somewhere between these numbers lies a forecasting model that has completely given up. Farmers plan their cropping cycles better than the Government plans its subsidies. And that extra Rs. 18,525 crore

could have directly supported nearly 10 crore farmers. But instead, we are told to pay for a system that leaks more than it delivers.

For LPG and petroleum subsidies, there is a provision for another Rs. 9,500 crore. When States ask for resources, they are told to tighten their belts. But when subsidies need topping up, suddenly that belt becomes elastic.

Sir, now, I want to speak with seriousness about something that cannot be brushed aside. The Election Commission gets Rs. 58 crore. It is fine, but we still have no clarity on support for the families of BLOs who died by suicide. In West Bengal alone, 39 people including eight BLOs lost their lives due to unbearable pressure. Sir, these were ordinary citizens who served quietly and honestly. Their families deserve acknowledgement, dignity and compensation, not silence. Strengthening democracy cannot mean uploading institutions while ignoring the people who carry the weight of those institutions.

Sir, on youth, the concerns deepen. Only four per cent joined the PM Internship Scheme. Only 1.4 per cent Schedule Caste and Schedule Tribe youth are participating and one-third of our young population is not in education, employment or training. These are young Indians, ready to work, ready to learn and ready to contribute, yet they are left standing outside the gates of opportunity. The gap is not in talent, the gap is in implementation. The Government promised a fiscal deficit of 4.5 per cent of GDP when it presented the Budget, but the commitment was always hollow. These repeated supplementary demands make a mockery of fiscal targets, which are quietly altered mid-year without public scrutiny. Where is the fiscal discipline? Where is the credibility?

Sir, now, regarding aviation sector, another crisis is waiting patiently for attention. One operator cancelled more than 5,000 flights. DGCA has 50 per cent vacancies, AAI has 37 per cent vacancies and BCAS has 38 per cent vacancies. With so many vacancies, aviation is not flying, it is floating. Yet in this entire supplementary demand, there is zero rupees for civil aviation.

Kolkata, despite being one of India's cultural and economic hubs, still has no direct flight to the United States or Europe. Other metros enjoy 456 flights a week. Kolkata gets none. Even tourists can see the bias while planning their itinerary. Why cannot the Union Government do so? All of this ties directly into the collapse of cooperative federalism. States like Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and West Bengal rely on stable subsidy flows. But the Centres unpredictable spending

patterns throw State planning into chaos. States are expected to act as shock absorbers for decisions they did not make. This is not cooperative federalism, Sir. This is federalism where the Centre drives the car and the States are told to pay for the fuel.

Sir, suddenly an additional Rs. 2,198 crore appears in the Supplementary Demands for Manipurs development. Sir, I truly welcome development of Manipur. Every part of India deserves growth, dignity and peace. But Sir, at what timing? When Manipur was burning for months and so, the Government could not find urgency. But now that elections are coming, funds have magically appeared. When the State was pleading for help, we were told, We are looking into it. Now, suddenly the path opens wide. Sir, I appreciate the Governments efficiency. If only this speed had been shown when people were running for their lives, not when people are running for votes. The message seems to be in a crisis, wait and in an election, celebrate. That is not governance, that is selective attention, Sir.

Womens safety presents another distressing picture. The womens helpline budget was cut by 85 per cent. Cybercrime protection for women and children received zero amount last year and zero amount again this year. Sir, slogans do not protect women, budgets do. Right now, the budget for womens safety is practically on a fast.

Sir, now I am coming into the climate sector. Despite escalating climate risk, the Supplementary Demands are silent on environmental protections. There is no meaningful enhancement for climate adaptation, pollution control, biodiversity conservation or disaster preparedness. Sir, the absence of fresh allocation signals that environmental concerns remain expendable, treated as peripheral rather than integral to growth, livelihoods and public welfare.

Now, the broader issue is the silence around these demands. There is no explanation for failed estimates, no clarity on what changed mid-year and no accountability for the additional money requested. We are simply told: Please approve. Parliament is not a cashiers counter. The rupee has been weakening due to trade deficit, capital outflows, global interest rate pressures, and weak exports. Yet, the Supplementary Demands offer no funds or policy support to address these issues. By ignoring the falling rupee, the Government avoids acknowledging rising input costs, inflation, and the growing burden on ordinary citizens. I would like to request the hon. Finance Minister to clarify this. Why did Donald Trump call the Indian economy as a dead economy?

The Home Ministry has been allocated Rs. 10 crore for advertisement and publication and Rs. 5 crore for printing. I would like the hon. Finance Minister to explain this. Why such a huge amount was allocated to the Home Ministry only for advertisement purposes? The affront goes deeper. These 72 Supplementary Demands will be bulldozed through this House *via* the guillotine procedure. The Government has engineered a system where meaningful parliamentary scrutiny is rendered impossible. The Modi Government has progressively weakened every institution designed to check Executive excess -- the C&AG, the RBI, the Election Commission, the judiciary, and now the Parliament itself. Through Supplementary Demands, made immune to scrutiny, it perfects a system where accountability evaporates.

The Union Cabinet has approved a Bill to rename the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act as Pujya Bapuji Gramin Rozgar Yojana. Changing the name of a nearly 20-year-old widely recognized welfare scheme is an unnecessary and costly process. Rebranding and all the related materials -- from office signature to official documentation and job cards -- would be a significant expense of public resources. Our people are living souls and not mere lifeless soil. If we truly honour our beloved countrymen, then our Bapu ji will be literally worshipped. West Bengal is being deprived of getting MGNREGA funds. West Bengal is being deprived of getting funds under the Jal Jeevan Mission. West Bengal is being deprived of getting funds under the National Rural Health Mission. West Bengal is being deprived of getting funds under the Pradhan Mantri Awas Yojana.

The note is now ringing in the voice of the underprivileged people of West Bengal.

"Aami bhoy korbo na bhoy korbo na/Du bela morar aage morbo na bhaai, morbo na/Torikhana baaite gele maajhe maajhe tuphan mele/Taai bole haal chhere diye dhorbo na, kaannakaati dhorbo na" which means I won't be scared/ I will not die every day before death beckons/when I sail, I might encounter wind and hail/neither I will be dejected, nor will I wail".

I shall not be afraid. I shall not die every now and then before death.

The people of West Bengal will fight for their protector, none other than Mamata Banerjee. People of West Bengal will fight for their young leader, Abhishek Banerjee. People of West Bengal will protect our Party symbol once again, in 2026.

Lastly, I call this House to demand accountability. I call on the Parliament to reassert its constitutional authority. I demand that the large supplementary

allocations face mandatory Standing Committee review. I demand transparency in subsidy distribution. I demand that fiscal targets mean something. I demand that this Government immediately undertake a comprehensive fiscal and administrative reform.

The nation is watching. History will judge. Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Thank you very much.

Now, I take the sense of the House whether the House will be extended till 8 o'clock. If the House is agreeable, then we will extend the House up to 8 o'clock.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Yes, the House is extended up to 8 o'clock.

Now, the next speaker is Dr. Rani Srikumar.

DR. RANI SRIKUMAR (TENKASI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

I am going to speak about the Supplementary Demands for Grants at a time when India is facing growing economic uncertainty, rising inequality, and an alarming gap between Government claims and the live reality of ordinary citizens.

The figures placed before this House are not just budgetary numbers. They reveal the mindset and priorities. An additional expenditure of Rs. 1.32 lakh crore is being sought, out of which Rs. 41,200 crore is a direct cash outgo while the remaining Rs. 90,800 crore is expected to be managed through alleged savings and recoveries.

18.00 hrs

Out of this, Rs. 1.32 lakh crore, Rs. 62,446 crore is revenue expenditure and Rs. 69,822 crore is capital expenditure. The Government claims that this reflects an infrastructure-driven approach, but the reality is that this so-called capital expenditure is not strengthening public hospitals, educational institutions or welfare system. Instead, it is largely facilitating corporate expansion.

The neglect of Tamil Nadu under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana exposes the Union Government's discriminatory approach. While the Department of Animal Husbandry has sought additional funding, the Department of Fisheries has asked for nothing because it has effectively abandoned its commitments, particularly towards the Tamil Nadu fishing community. This is not an

administrative lapse. This is deliberate denial of funds. Tamil Nadu contributes immensely to India's economy, yet its fishing community is being punished for political reasons.

The situation of AIIMS, Madurai is an embarrassment to this nation. It was announced in 2018. The project remains incomplete even today. Students were admitted without a campus and classes were conducted out of a borrowed medical college building. While six other AIIMS institutions were fully funded by the Union Government, Tamil Nadu alone was asked to take a foreign loan from JICA for most of the cost. Only after repeated pressure, visit of the delegation of Japan and years of delay did construction finally begin. This treatment of Tamil Nadu reflects not administrative failure, but political vindictiveness.

India's public health spending paints an even darker picture. While developed nations spend around eight per cent of GDP on healthcare, India struggles to spend even one per cent. The recent claim that out-of-pocket expenditure has declined is misleading, Actually, it has fallen not due to expanded Government services, but because citizens are postponing treatment, avoiding hospitals and absorbing healthcare costs through silent sufferings.

*Hon. Chairperson Sir, hon. Prime Minister always claimed with pride that they have good friendly relationship with the USA. But the USA has imposed additional tariffs for exporting Indian goods to the USA. A penalty was also levied on Indian goods by the US Administration. Therefore, friendly relations of Indian Prime Minister with the USA will not provide any benefit to India.

States are being financially strangled. GST dues are withheld. Hon. Chairman sir, due to the sincere efforts of our Hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Tamil Nadu remains a pioneering and progressive State in the field of education in our country. Number of students who pursue higher education is highest in Tamil Nadu in comparison to other States of the country. You have kept a target of reaching 52 per cent higher education by the year 2034 under the New Education Policy. But this target has already been achieved by the State of Tamil Nadu. Why do we need the New Education Policy for us? In the name of three language policy, you are imposing Hindi on Tamil Nadu to which we are opposing.

That's why you have denied release of Rs. 2,548 crore that is due under Samagra Shiksha Abhiyan (SSA) to Tamil Nadu. How fair is this? Is it not Tamil Nadu part of our country? Is it in some other country? You have not released the funds that are

due under MGNREGA to Tamil Nadu. You want to change the name of MGNREGA scheme as it is in the name of father of our nation Mahatma Gandhi. It shows how much enmity you have towards the leaders who participated in the Indian freedom struggle. You have not released funds under Jal Jeevan Mission and Disaster Relief for Tamil Nadu. After our Chief Minister assumed charge in Tamil Nadu although several cyclones, heavy floods of Chennai and Corona have played havoc in our lives, through his effective administrative skills our hon. Chief Minister of Tamil Nadu have managed it very well. I want to say that you should emulate our system of administration at the Centre. Our Chief Minister will say that health and education are two eyes. He is also working tirelessly for the welfare of women. Pudhumaipenn Scheme for educating our young women, Thozhi hostels for working women are some of his schemes for education and health. But the Union government's contribution to these schemes is very less. Our State government has been giving these many schemes for education, health and development of women. Why can't the Union government implement several such schemes.*

The story buried inside these Supplementary Demands is not about welfare; it is a story of misplaced priorities, corporate comfort, confusion and political revenge against Opposition-ruled States. It reflects that the Union Government protects monopolies, neglects commerce and abandons fishermen.

SHRIMATI PRATIBHA SURESH DHANORKAR (CHANDRAPUR): Hon. Chairperson, I rise to submit today regarding the supplementary demands for the year 2025-2026, and I wish to draw your attention to a very important matter.

Under the agriculture sector, the government has imposed strict restrictions on the cotton procurement process by the CCI (Cotton Corporation of India). While the actual cotton productivity is 13 to 20 quintals per hectare, the government is considering 25 to 45 quintals per hectare, and a limit of 2.50 to 7.50 quintals per hectare has been imposed. This is causing significant losses to the cotton growing farmers. Therefore, I demand that the limit of 30 quintals per hectare be increased to 40 quintals per hectare. Along with this, the rules regarding cotton sales through the slot booking system should be relaxed.

Maharashtra experienced heavy rainfall, resulting in significant losses to the farmers. Hon. Speaker, Before the BJP government came to power in Maharashtra, they had promised to waive off farmers' loans, but this has not yet happened.

The Supreme Court has ordered that teachers appointed before 2005 must pass the TET (Teacher Eligibility Test) examination, and if they fail to do so within two years, they will be dismissed from service. I request that the educational qualifications that were considered valid for teachers who joined before 2010 be maintained, so that they do not suffer any family hardship.

Around 1,219,516 farmers have committed suicide in the country, out of which 8,38,815 are from Maharashtra. Many farmers have outstanding loans in various banks that they have not yet been able to repay. The crop insurance scheme launched for Rs. 1 has remained only a scheme on paper. In reality, farmers have to pay Rs. 1700 to Rs. 1800 to get crop insurance. Regarding rural development, we have seen that work has been done across the country through the Jal Jeevan Mission, but the payments due from the central government have not yet been received. In my district, payments of ₹40 crore for the Jal Jeevan Mission are still pending. The condition of the roads is very bad, and many proposals regarding road repairs have been pending with the Rural Development Ministry for the last four years.

There are many coal mines in my constituency, and some farmers' lands, amounting to 10 per cent to 20 per cent of their total land, have been left out of the acquisition process. These farmers should be given the benefits under the Coal Mines Act.

When Prithviraj Singh Chavan was the Chief Minister of Maharashtra, farmers benefited greatly. At that time, he provided ₹6 lakh for barren land, ₹8 lakh for dry land, and ₹10 lakh for irrigated land. The rates have not been increased in the last 20 years. Therefore, I am demand that the compensation for the acquired land should be increased to ₹18-20-22 lakh per acre.

The issue of old pension for teachers who were appointed before 2005 is still pending. I have been demanding it since I was an MLA. Through you, I request that you must focus on this matter. The issue of OBC reservation is also pending. I am demanding through you that a separate ministry should be created for them, and the reservation limit should be increased and from the 50% cap be removed. OBC reservation is important for us and plays a major role in local self-government elections. Until the reservation issue is resolved, the work related to these elections will not go smoothly.

The central government appointed many people through the Sarva Shiksha Abhiyan in 2007, but they have not yet been taken into service. Many such works are still pending, and I am requesting you to ensure that these are resolved through the central government intervention. Honorable speaker, I also request that you instruct the state government to implement farmer loan waiver scheme. Thank you.

डॉ. विनोद कुमार बिंद (भदोही) : महोदय, आज आपने मुझे सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, 2025-26 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ ।

मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं स्वास्थ्य की ही बात करूंगा । यूपीए सरकार के समय में स्वास्थ्य के लिए बजट 20,000 करोड़ रुपये था और जब एनडीए सरकार बनी तब से यह बजट 90,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है । पहले की तुलना में चार-पांच गुना ज्यादा बजट हो गया है । इस देश पर सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज किया है । मैं वर्ष 2014 का आंकड़ा पेश करना चाहता हूँ, उस वक्त पूरे देश में एमबीबीएस की सीटें 51318 थीं, लेकिन माननीय नरेन्द्र मोदी सरकार जी की सरकार बनने से देश में एमबीबीएस की सीटें 1 लाख 32 हजार तक पहुंच गईं । उस समय पीजी की सीटें करीब 31,000 थीं लेकिन अब 82,000 तक पहुंच गई हैं ।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ । पहले प्रदेश में आठ मेडिकल कॉलेज थे और 650 सीटें थीं । हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने से 78 मेडिकल कॉलेज हो गए और 12,325 सीटें हो गईं । आज माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व बहुत गति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है । मैं ऑर्थोपेडिक्स सर्जन हूँ । माननीय प्रधान मंत्री जी ने आयुष्मान योजना लागू की है, जो गरीब 10-15 सालों से चलने में कूल्हा, घुटना या स्पाइन खराब होने के कारण असमर्थ हो जाते थे, अब हम उनका इलाज कर देते हैं, घुटना बदल देते हैं, कूल्हा बदल देते हैं और जब वे चलते हैं तो कहते हैं - डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । तब मैं कहता हूँ - हमें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दीजिए, जिनकी वजह से आप चलने लायक हो गए हैं, हम तो केवल माध्यम हैं ।

महोदय, पहले गरीब आदमी बीमारी में मर जाता था, लेकिन अब माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच और नई दिशा के कारण गरीबों के पास पांच लाख रुपये तक इलाज का कार्ड मिल जाता है, जो उनके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है ।

महोदय, जब कोई मरीज हम लोगों के पास आता है, तो बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि आपके पास मोदी जी का कार्ड है या नहीं है? वह बोलता है कि मेरे पास मोदी जी का कार्ड है । तब मैं बोलता हूँ कि आपको गरीब बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी 140 करोड़ लोगों के आँसू पोंछने का काम करते हैं । अब इस कार्ड को निकालिए और सम्मान के साथ बोलिए कि डॉक्टर साहब यह पाँच लाख का कार्ड है, हमारे इलाज का जितना खर्च लगता है, उतना आप ले लीजिए और बचा हुआ दूसरी बीमारी के लिए छोड़ दीजिए, यह हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी की सोच है ।

महोदय, अगर हम प्रदेश में डायलिसिस की बात करें, तो पहले वहाँ जो मेडिकल कॉलेज थे, वहीं पर डायलिसिस हुआ करता था । आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि सभी 75 जिलों में डायलिसिस की सुविधा है । इससे

गरीबों के लिए एक आधार बन गया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले सब नारे लगाते थे, लेकिन फर्क तो नीयत और नीति से पड़ता है।

महोदय, यूपीए सरकार की नीयत और नीति में बहुत फर्क है। आज हमारे पास गरीबों के लिए चाहे राशन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवास योजना हो, इनसे सभी गरीबों के लिए एक आधार बन गया है। हर आदमी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल गया है। हमारे जन औषधि केंद्रों के बनने से 33 हजार करोड़ लोगों को फायदा हुआ। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस गति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए हमें आयुष्मान योजना में थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। उन्हें छः यूनिट्स पर ही आयुष्मान कार्ड मिलता है।

मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि यह सभी गरीबों के लिए लागू हो, क्योंकि जिनके पास छः यूनिट्स नहीं होती हैं, उन्हें आयुष्मान कार्ड नहीं मिलता है, जिस कारण उनका इलाज नहीं हो पाता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI TANGELLA UDAY SRINIVAS (KAKINADA): Hon. Chairperson, Sir, I rise to speak on the Supplementary Demands for Grants for 2025-26 through which the Government is seeking an approval for an additional expenditure of Rs. 1.32 lakh crore, of which the actual cash outgo will be about Rs. 41,455 crore. These allocations reflect important national priorities, but they also highlight areas where urgent constituency-level needs deserve attention.

Sir, I would first like to speak on the Ministry of Education. The Supplementary Demands include Rs. 1,303 crore of an additional support for higher education, including capital assets for Central institutes and the PMs One Nation One Subscription initiative. This enhanced spending is welcome and will strengthen learning and research across the country.

In my constituency, however, a basic requirement remains unresolved. At Rangaraya Medical College, Kakinada, the construction of students hostels has stalled completely. Only 35 per cent of the PG ladies hostel and 15 per cent of the PG mens hostel have been completed, while both UG hostels remain stuck at the basement level and require financial sanction of Rs. 22 crore for a full G+4 structure. These hostels are essential for medical students accommodation and for expanding PG seats. With fresh capital allocations now available, I request the Ministry to kindly support RMC in completing these long-pending works.

Hon. Chairperson, Sir, I now turn to the Ministry of Communications. The Supplementary Demands seek additional Rs. 37,014 crore for the telecom sector, covering infrastructure, digital monitoring systems, and major national digital projects. This significant investment will strengthen India's digital backbone. At the

same time, Sir, I have already submitted a detailed representation requesting 10 new 4G towers in critical uncovered pockets of Kakinada District. These include rural, tribal, and coastal areas such as Yeleswaram, Korukonda, Gandepalli, Kottapalli, Peddapuram rural belt, and the Uppada coast - all of which continue to face serious connectivity gaps. With such a large capital outlay being sought, I urge the Government to also address these constituency-level issues so that the digital access reaches every household in these regions.

Hon. Chairperson, Sir, these supplementary demands strengthen national capacity, but they can also help resolve long-standing needs at the ground level. I humbly request the Government to consider these two specific demands from my constituency. Thank you, Sir. Jai Hind.

माननीय सभापति : श्री राजा राम सिंह - उपस्थित नहीं ।

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे ।

SUSHRI PRANITI SUSHILKUMAR SHINDE (SOLAPUR): Hon. Chairperson Sir, thank you for giving me an opportunity to speak me on the Supplementary Demands for Grants, 2025-26.

मैं यह कहकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहती हूँ कि जो सत्ता पक्ष में हैं, वे 24x7 इलेक्शन मोड में रहते हैं । इसका हर्जाना देश को भुगतना पड़ रहा है । हर इलेक्शन के पहले लोगों को रिझाने की खातिर अन-प्लान्ड पॉपुलर स्कीम्स के तहत पैसे बांटे जाते हैं, जिससे देश और राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है । आज देश में पैदा होने वाला हरेक बच्चे के सिर के ऊपर पैदा होते ही लगभग सवा लाख रुपये का कर्ज हो जाता है । यह है बीजेपी सरकार की देन ।

महाराष्ट्र में जो बाढ़ आई, उसके बारे में मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ । शर्मनाक बात यह है कि अभी तक हमें पता नहीं है कि केन्द्र शासन ने महाराष्ट्र के लिए पैकेज डिक्लेयर किया है या नहीं । जब बारिश के कारण बाढ़ आई, तो उसके बाद सेन्ट्रल गवर्नमेंट से महाराष्ट्र में एक टीम भेजी गई, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कहते हैं कि उनको अभी तक पैकेज नहीं मिला है । सेन्ट्रल गवर्नमेंट कहती है कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक प्रपोजल नहीं भेजा है । क्या महाराष्ट्र सरकार केन्द्र सरकार को प्रपोजल भेजना नहीं चाहती है या सेन्ट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र के किसानों के साथ अन्याय करके उनको पैसे नहीं देना चाहती है? इसके बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट से हमें एक स्टेटमेंट अपेक्षित है कि एग्जैक्टली कितने पैसे महाराष्ट्र के किसानों को मिलने वाले हैं । आज महाराष्ट्र के किसान स्यूसाइड कर रहे हैं, वे आत्महत्या कर रहे हैं । उनके सिर पर कर्ज का बोझ चढ़ रहा है । हमने मांग की थी कि हरेक किसान को 50 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मिले, लेकिन जिस तरह से सीएम ने पैकेज एनाउंस किया, उससे लगता है कि महाराष्ट्र के किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है ।

महोदय, एक किसान के खाते में सिर्फ छः रुपए जमा हुए । ऐसी शर्मनाक रूप से, महाराष्ट्र के किसानों के साथ सेन्ट्रल और महाराष्ट्र की सरकारें मजाक कर रही हैं । हमने किसानों के लिए 50 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मांगे

थे, लेकिन वह तो नहीं मिला। उसके बाद हमने मांग की थी कि नदी के किनारे जो गांव हैं, उनका पुनर्वसन होना चाहिए, वे रिहैबिलिटेड होने चाहिए क्योंकि जब बाढ़ आती है, तो उनका पूरा संसार उनकी आँखों के सामने बह जाता है। जब उनकी आँखों के सामने उनके खेत बह जाते हैं, तो इस पीड़ा से उबरने में और पुनः खेत में फसल लगाने में उनको तीन-चार साल लग जाते हैं। इसके लिए इसके क्राइटरिया अलग होने चाहिए। जो खेत बह गये हैं या जो जमीन इरोड हो गई है, इसकी क्राइटरिया अलग होनी चाहिए। हमने तब मांग की थी कि वेट-ड्राउट डिक्लेयर हो, लेकिन वेट-ड्राउट डिक्लेयर नहीं हुआ। अगर वेट-ड्राउट डिक्लेयर होता, तो किसानों के कर्ज माफ हो जाते।

बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिले हैं, जिन बच्चों को एजुकेशनल लोन्स मिले हैं, वे तो माफ हो जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह नहीं किया, क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एड नहीं दी थी। जब एकाउंट में पैसे जमा होते हैं, तो उसके लिए किसानों को केवाईसी करना पड़ रहा है। किसानों को साल में चार बार केवाईसी करना पड़ रहा है। किसानों को साल में चार बार यह साबित करना पड़ रहा है कि वे मर गए हैं या जिंदा हैं। यह बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए मैं मांग कर रही हूँ कि केवाईसी और आधार लिंक का जो क्राइटरिया है, वह रद्द होना चाहिए। इसके साथ ही, साल में चार बार केवाईसी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि हरेक मंडल में जो सैटेलाइट होता है, उसमें रेनफॉल रिकॉर्ड होता है। लेकिन पेड़ के नीचे सैटेलाइट लगाये जाते हैं। पूरे मंडल में 65 मिलीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होता है, लेकिन सैटेलाइट को पेड़ के नीचे लगाये जाने के कारण वह रेनफॉल को रिकॉर्ड ही नहीं करती है और कहा जाता है कि ज़ीरो रेनफॉल हुआ है, इसलिए उस मंडल को पैकेज के तहत शामिल नहीं किया जाता है। उस मंडल में जितने भी गांव आते हैं, उन गांवों के सारे किसान इससे वंचित हो जाते हैं। महाराष्ट्र में यह बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है।

महोदय, सबसे शर्मनाक बात यह हुई है कि जो मुख्यमंत्री राहत कोष होता है, उसमें कोई अपनी पेंशन या वेतन की राशि डालता है। हाल ही में मुख्यमंत्री राहत कोष में महाराष्ट्र के किसानों के लिए 100 करोड़ रुपये एकत्रित हुए थे, लेकिन 100 करोड़ रुपये में से महाराष्ट्र के किसानों को सिर्फ 75,000 रुपये दिए गए हैं। बाकी का पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष से कहां चला गया?

महोदय, मैं सिर्फ तीन तथ्यों के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त 15,000 रुपये की है, वे उस राशि से रेत भी नहीं खरीद सकते हैं। मैं यह मांग करती हूँ कि जो 15,000 रुपये की किश्त दी जाती है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। कागजों में लिखा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने घर मंजूर किए गए हैं, लेकिन गांव में गौठान जमीन न होने के कारण अभी तक एक भी घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं दिए गए हैं। ये सिर्फ फिगर्स हैं, जो कागजों में लिखे होते हैं।

महोदय, दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 1,00,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, मैं चाहती हूँ कि उस धनराशि को बढ़ाया जाए, क्योंकि कोई 1,00,000 रुपये में जमीन भी नहीं खरीद सकता है। मैं कहना चाहती हूँ कि वह रेडी रेकनर रेट के हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। पिछले दो वर्षों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत महाराष्ट्र में एक भी रास्ता नहीं बना है। वे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार काम कर रहे हैं। उसके

अनुसार दो गांव कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। बड़े-बड़े हाइवेज़ बनाने से अच्छा है कि दो गांवों के रास्तों को जोड़िए। (व्यवधान)

महोदय, मैं यह मांग करती हूँ कि महाराष्ट्र में जितने भी रास्ते बाढ़ में बह गए हैं, उनके लिए ऑडिट किया जाए और फंड्स की घोषणा करनी चाहिए। (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे : महोदय, जल जीवन मिशन के तहत एक कमेटी का गठन किया गया था। (व्यवधान) जल जीवन मिशन के तहत महाराष्ट्र में बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी वजह से उस कमेटी ने केन्द्र सरकार का 46 प्रतिशत कट का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं सैनितेशन वर्कर्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप अपनी अंतिम बात कहिए।

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे : महोदय, सैनितेशन वर्कर्स को पहचाना नहीं जाता है। नमस्ते स्कीम के अंतर्गत शून्य प्रावधान रखा गया है। मैं गुजारिश करती हूँ कि हमें सैनितेशन वर्कर्स के लिए कुछ करना चाहिए। डीएलसीसी में जिलाधिकारी को अथॉरिटी मिलनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, हम सांसदों और संसद की जो ड्यूटी है, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम बजटिंग करना, इसकी चर्चा में हिस्सा लेना व कुछ समझना और सीखना भी है। मुझे पहली बार बजट पर कुछ बोलने का मौका मिला है। अगर हम वर्ष 2014 से पहले और बाद की तस्वीर देखें, तो जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, उन्होंने बजटिंग के सिस्टम को इतना सुंदर और तंदुरुस्त किया है कि इसमें रेवेन्यू बढ़ने के साथ-साथ खर्च भी बहुत पारदर्शी तरीके से हो रहा है।

महोदय, मैं 16 वीं लोक सभा का सदस्य था। शायद उस समय का बजट 16,00,000 करोड़ रुपये के आसपास था। पिछले 11 सालों में वह बढ़कर 50,65,345 करोड़ रुपये का बजट हो गया है। जैसे बजट आने के बाद अनुपूरक बजट की व्यवस्था रही है। पिछली सरकार के समय हर एक सेशन में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करने और उसे पास करने की व्यवस्था थी। उससे क्या होता है? पहले न तो कोई साफ तरीका था कि क्या करना है या किस विषय पर खर्च करना है, लेकिन मोदी जी ने उसको बदलकर एक साल में दो बार अनुदानों की अनुपूरक मांगें लेकर आए हैं, जिस पर चर्चा होती है और वह पास होता है। ऐसा मानूसन सत्र और बजट सत्र में होता है।

पहले बजट में फंड्स एलोकेट करने का जो तरीका था, करीब 60,000 खातों में पैसा भेजा जाता था। केन्द्र सरकार के खाते और राज्य सरकार के खाते में कितनी धनराशि जाएगी, कुछ पता नहीं चलता था। इसलिए केन्द्र सरकार को उसकी मॉनिटरिंग करने में थोड़ी दिक्कत आती थी। मोदी जी ने पीएफएमएस और ई-कुबेर इंटरफेस के माध्यम से जो सिस्टम बनाया है, 60,000 करोड़ खातों के स्थान पर आज की तारीख में सिर्फ 894

करोड़ खातों में ही पैसे का ट्रांजेक्शन किया जाता है, जो रियल टाइम में होता है। पहले की बजटिंग में पैसा ट्रांजेक्शन का जो सिस्टम था, उसमें जाने पर पैसा जमा रहता था और वह पैसा बेकार हो जाता था। इस बजटिंग सिस्टम में रियल टाइम फंड ट्रांसफर के चलते गवर्नमेंट को करीब 15 हजार करोड़ रुपए का फायदा हुआ है।

महोदय, मुझे याद है, मैं उस समय सांसद नहीं था, जब मनमोहन जी की सरकार थी। उस समय हमारे ओड़िशा से कुछ सांसद ओड़िशा के लिए कुछ विशेष मांग करने के लिए आए थे। उन्होंने यह जबाब दिया था कि पैसा क्या पेड़ पर फलता है? वह आज मोदी जी पेड़ पर उगाते हैं या कहां से उगाते हैं, पता नहीं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से कभी कोई स्कीम नहीं रुकी है। मुझे याद है कि वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक हमारे एरिया में प्रधानमंत्री सड़क योजना और बिजली योजना, जो ग्रामीण एरिया के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, वे ठप पड़ी हुई थीं।

महोदय, बजट के जिस आंकड़े के बारे में मैंने बताया है, आज के दिनों में वह तो बढ़ा ही है, लेकिन यदि आप व्यक्तिगत रूप से मेरे एरिया को देखेंगे, तो मेरे एरिया में बीते 11 सालों में करीब 4,000 किलोमीटर का रास्ता तैयार हुआ है। भारतमाला परियोजना के तहत एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो विशाखापत्तनम से रायपुर को कनेक्ट कर रहा है। उस पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि वह आने वाले अप्रैल-मई तक खत्म हो जाएगा। जो ट्रेवल टाइम अभी 14 घंटे का है, वह घटकर 6 घंटे हो जाएगा। अब हम लोग उस 600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी को 6 घंटों में कवर कर लेंगे। यह तभी संभव हो पा रहा है, जब बजट में इतने सारे सुधार लाए गए हैं। विरोधी पक्ष के लोग तरह-तरह की बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जान रही है कि ग्रामीण और जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। मेरे एरिया जैसे पिछड़े एरिया में, जहां रेलवे लाइन नहीं के बराबर थी, यानी मेरे पूरे एरिया में 40 से 50 किलोमीटर की रेलवे लाइन के अलावा, दो जिलों मलकानगिरी और नबरंगपुर में कुछ भी नहीं रहा है।

महोदय, आप देखिए कि बीते 11 सालों में, वर्ष 2016-17 में यह पहली बार सैंक्शन किया गया और हाल में यह वर्ष 2024 में सैंक्शन किया गया है। भद्राचलम से मलकानगिरी, जैपोर, नबरंगपुर और जूनागढ़ के लिए कुल मिलाकर 460 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन सैंक्शन हुई है। यह स्वाधीन भारत में सेकेंड लॉंगेस्ट न्यू रेलवे प्रोजेक्ट है। अगर हम पहले लॉन्गोस्ट प्रोजेक्ट की बात करेंगे, तो वह मैंगलौर से मुंबई तक का 750 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट था। मेरे एरिया जैसे पिछड़े एरिया में इतनी लंबी लाइन के रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सैंक्शन होगा। यह कैसे संभव हो रहा है? यह इसलिए संभव हो रहा है, क्योंकि मोदी जी की सरकार सभी क्षेत्रों, जैसे, बजटिंग, एक्सपेंडीचर, प्लानिंग और रेवेन्यू क्षेत्र में कार्यरत है।

महोदय, आप देखिए कि इनकम टैक्स की लिमिट 12 लाख रुपए तक बढ़ा देने के बाद भी जीएसटी में रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात को समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री बलभद्र माझी : महोदय, रेवेन्यू का रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। इसलिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। समय बहुत कम है, लेकिन माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि वे सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चर्चा लेकर आई हैं। इसे बिना किसी दुविधा के, बिना कोई बहसबाजी किए और विरोधी

पक्ष की बात सुने बिना पास कर दिया जाए । मैं अपनी बात कन्क्लूड करते हुए बोलूंगा कि इसमें विशेषकर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर एडिशनल मांग की गई है । इसमें करीब जो 1 लाख 32 हजार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मांगे गए हैं (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप यह सब बोल चुके हैं ।

श्री बलभद्र माझी : महोदय, उसमें से 90 हजार करोड़ रुपए तो सेविंग्स और री-एडजस्टमेंट्स ही हैं । अदरवाइज़, यह डिसिप्लिन नहीं होता, तो यह पैसा पड़ा रहता और ऐसे ही खर्च नहीं होता, जो कि अभी होने वाला है । करीब एक्स्ट्रा 41 हजार करोड़ रुपए की जरूरत पड़ रही है । उसमें जो मोटा-मोटा खर्चा होने वाला है, वह केमिकल्स में, फर्टिलाइजर्स में, पेट्रोलियम में, होम अफेयर्स में, फाइनेंस में और एजुकेशन में होगा । (व्यवधान)

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : सभापति महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांग, वर्ष 2024-25 के विरोध में अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी, अपने नेता पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदान तब लाए जाते हैं, जब कोई असाधारण परिस्थिति हो । लेकिन, जब यह प्रक्रिया हर वर्ष नियमित अभ्यास बन जाए, तो यह साफ संकेत है कि बजट अनुमान कमजोर है और योजना निर्माण में गंभीर कमी है । इतने बजट आवंटन के बाद भी किसान, मजदूर, शोषित और पीड़ित वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए भी उससे दो-चार होना पड़ता है । अच्छी शिक्षा चाहिए, तो प्राइवेट संस्थानों की तरफ जाना पड़ता है, इलाज चाहिए, तो प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है और शुद्ध पानी चाहिए, तो जल जीवन मिशन से पानी नहीं मिलेगा, बोतल बंद पानी खरीदना पड़ेगा ।

सभापति महोदय, हमने इस सदन में भोर के तीन बजे तक भी चर्चा होती देखी है । आखिर वह दिन कब आएगा, जब किसानों की समस्याओं पर, बेरोजगारों की समस्याओं पर और नौजवानों की समस्याओं पर भी भोर के तीन बजे तक यह सदन चले? आज सबसे ज्यादा कोई संकट में है, तो वह इस देश का किसान - अन्नदाता संकट में है । अव्वल, उसे उपज का वास्तविक मूल्य नहीं मिलता । इसी सदन में उर्वरक मंत्री ने हमारे सवाल के जवाब में कहा था कि यूरिया का कोई संकट नहीं होने दिया जाएगा । उत्तर प्रदेश के बारे में इसी सदन में उन्होंने पिछले सत्र में आश्वस्त किया था, लेकिन, इस सत्र में भी किसानों को यूरिया नहीं मिला है, उन्हें लाठियां खानी पड़ी हैं ।

सभापति जी, चाहे केले का किसान हो, इस बार हमारे क्षेत्र धौरहरा का किसान 100-200 रुपए में केला बेचने पर मजबूर हुआ है । अजब बात तो यह है कि फसल बीमा योजना में भी केला नहीं आता है । चाहे धान के किसान हों, उनका धान नहीं लिया गया । एफआरके के नाम पर, कि एफआरके चावल मिल मालिकों को उपलब्ध नहीं हुआ, तो वे चावल के लिए धान नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए, मंडियों में धान नहीं बिक पाया ।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसान अगर पराली जला दे, तो सैटलाइट से देखकर उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है । उसका बहुत शोषण होता है, उससे जुर्माना वसूला जाता है । जब फसल चौपट होती है, जब आंधी, तूफान और बाढ़ आती है, तब सरकार की सैटलाइट कहां चली जाती है? तब तो लेखपाल जाता है, एसडीएम जाते हैं और जो जितना सुविधा शुल्क दे देता है, उस हिसाब से काम होता है । पता नहीं सैटलाइट उस समय कहां चली जाती है?

सभापति जी, पराली नष्ट करने के लिए किसी यंत्र का प्रावधान नहीं किया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जब तक पराली नष्ट करने का कोई इंतजाम सरकार न करे, तब तक कम से कम दो हजार रुपए प्रति एकड़ किसानों को देने का काम किया जाए।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, तब हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किसान दुर्घटना बीमा की राशि को पांच लाख रुपए किया था। आज उत्तर प्रदेश में किसी किसान की यदि दुर्घटना में मौत हो जाए, तो केवल किसान बीमा दुर्घटना योजना ही उसका सहारा है। गन्ना किसानों को उनकी कीमत नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, जब पर्ची शुरू होती है, तो चाहे अर्ली फसल हो, चाहे तेहरी हो, उन सबकी एक साथ पर्ची नहीं आती, जिससे गेहूँ बोनो के लिए किसान परेशान रहता है। इसलिए, पर्चियां एक साथ ली जाएं।

सभापति महोदय, आज करोड़ों नौजवानों के हाथ खाली हैं। जब तक रोजगार नहीं दे सकते, तब तक कम से कम 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया जाए। नौजवान जब रोजगार मांगने जाता है, तो उसे लाठी खानी पड़ती है, पेपर लीक हो जाता है। मैं एक बात दिव्यांग साथियों के बारे में भी कहना चाहता हूँ। यह सरकार नाम बदलने में बहुत माहिर है। विक्लांगों का नाम बदलकर इन्होंने दिव्यांग कर दिया। लेकिन, उनके लिए सुविधा बढ़ाने के नाम पर क्या किया? मैं उनके लिए तीन गुना पेंशन की मांग करता हूँ। दिव्यांग विभाग का बजट बढ़ाइए, मंत्री जी भी परेशान हैं। 80 परसेंट की वैधता हटाइए, सबको मोटराइज़्ड साइकिल दीजिए, तब आपका इन लोगों का नाम दिव्यांग रखना सफल होगा।

सभापति जी, एक और बात है। यदि दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है, तो पोस्ट-मॉर्टम हाउस जिले में केवल जिला मुख्यालय पर एक ही होता है। आप इसके लिए बजट दीजिए। मैं मांग करता हूँ कि हर एक तहसील में पीएम हाउस बनाया जाए। पोस्ट-मॉर्टम हाउस नहीं बनाते हैं, जिसके साथ दुर्घटना हो जाती है, रात-रात भर वह पड़ा रहता है।

सभापति महोदय, मैं आखिरी बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। मेरी आखिरी बात हम लोगों की सांसद निधि के बारे में है। आप विकास करना चाहते ही नहीं हैं। आपने सांसद निधि नहीं बढ़ाई, बल्कि आपने सांसद निधि कम कर दी। कैसे कम कर दी? वर्ष 2010 में यह पांच करोड़ रुपए थी, उस पर जीएसटी लगा दी। अब एक करोड़ जीएसटी कंटेनर्जेंसी काटकर वह चार करोड़ रुपए बची। वर्ष 2010 में पांच लाख रुपए में 100 मीटर्स सीसी बनती थी, अब दस लाख रुपए में 100 मीटर्स बन रही है। यानी, हमारे पास सांसद निधि घटकर दो करोड़ रुपए रह गई।

सभापति जी, आखिर हम सांसद विकास के लिए क्या करें? जनता विकास के लिए कह रही है। पीएमजीएसवाई एक सहारा था। ज़रा पता लगा लेना, हम तो अपने जिलों - सीतापुर, लखीमपुर की स्थिति जानते हैं। एक सड़क भी पीएमजीएसवाई के नए मानक और मैं यह आरोप लगाता हूँ कि सरकार ने जानबूझकर पीएमजीएसवाई के ऐसे मानक बना दिए कि एक भी सड़क पीएमजीएसवाई में नहीं आ सकती।

सभापति महोदय, इसलिए, सांसद निधि को बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए किया जाए। इसके साथ ही साथ पीएमजीएसवाई में कम से कम 100 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का अधिकार सांसदों के प्रस्ताव पर दिया जाए।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, the Ministry of Chemicals and Fertilizers is the single largest driver of the Supplementary Demands for Grants, seeking additional Rs. 31,066 crore, a staggering 16.39 per cent jump in the original allocation.

In the last fiscal year also, Parliament approved Rs. 20,000 crore through two batches of Supplementary Grants. In the Budget Estimates of financial year 2025-26, the fertiliser subsidy was budgeted to be Rs. 1.67 lakh crore. Now, they are seeking additional Rs. 31,000 crore in allocations through SDG. In my opinion, it is not budgeting; it is firefighting.

Despite all the rhetoric of Atmanirbhar Bharat, India still imports over 2530 per cent of urea, 5060 per cent of DAP, and 100 per cent of potash. This is a dangerous overreliance that leaves Indian farmers at the mercy of global suppliers. A glaring example of this dependency came last year, when China imposed restrictions on fertiliser exports, severely impacting India's DAP and urea supply. Now, these restrictions by China led to a 70 per cent drop in DAP imports from China in the first half of the financial year 2025. Nearly 30 per cent of India's urea imports in 2023-24 came from China, making our country vulnerable to China's trade policies. India imports key raw materials, like phosphoric acid and ammonia, from China, which means that even domestic fertiliser production is affected by Chinese policy decisions.

My question to the Government is, how did the Government allow such a critical sector to be held hostage by China? The urea imports are regulated by the Government. In the financial year 2025, it stood at 43.16 lakh tonnes. Now, in 2023, the Union Minister of Chemicals and Fertilisers said, it is an attempt to end import dependence on urea by 2025. Where is this promise? Is it also another classic BJP promise, which will never be fulfilled?

I am quoting from the latest media report: Public sector banks have written off Rs. 6.15 lakh crore in five and a half years. The Finance Ministry insists that this is not a waiver and that recovery mechanisms, like SARFAESI, DRT, civil courts, and IBC, will recoup the dues. If you see the actual figures, they tell a different story of the public sector banks. They have recouped only Rs. 1.6 lakh crore of the write-off, barely a quarter of what has been written off. If the objective was to improve the health of our banking system, we must ask how effective this recovery mechanism has truly been. Reducing NPAs on paper through write-offs cannot be counted as a

substantive recovery. The public deserves clarity on real recoveries and accountability for loan origination and monetary failures.

Sir, from 2015-24, Indian commercial banks wrote off around Rs. 12.3 lakh crore, with Rs. 9.9 lakh crore in the past five years. What is happening over here?

Fake notes of Rs. 500 denomination rose by 37 per cent in the financial year 2025. Counterfeit notes of Rs. 500 denomination detected in the banking system jumped to 1,17,722 in the financial year 2024-25 from 85,711. The counterfeit notes of Rs. 200 denomination were 32,600 in the financial year 2025, which were 28,672 in the financial year 2024. What is this Government doing? Due to all these counterfeit notes, the Pahalgam incident happened and the Delhi incident happened. Is this your nationalism, that you cannot control it? Counterfeit notes of Rs. 500 and Rs. 200 denominations have increased.

Lastly, regarding minorities, in the financial year 2023-24, Rs. 3,000 crore was the B.E. This Ministry surrendered Rs. 2,000 crore, barely utilising the funds. The same playbook is followed in the financial year 2024-25, where the allocation was Rs. 3,183 crore. It has been slashed to Rs. 1,681 crore. In the financial year 2025-26, the budget for the Ministry of Minority Affairs was Rs. 3,350 crore, which was Rs. 166 crore more than Rs. 3,183 crore last year. Again, you have cut the budget. Under pre-matric scholarship, there is a sharp decline from Rs. 433 crore in the financial year 2023-24 to Rs. 326.16 crore in the financial year 2024-25. Now, it is Rs. 195.70 crore. Under pre-matric, the highest dropout rate in India is among Muslims.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI ASADUDDIN OWAISI: I am concluding, Sir. The actual spending is even lower. In the financial year 2023-24, only Rs. 95.83 crore was utilised, and Rs. 90 crore was released in the financial year 2024-25. Similar is the case with the allocation for merit-cum-means scholarship.

This PMJVK scheme was specifically targeted for minorities. The Government has made it a universal scheme. Now, this whole fund is being spent on areas where minorities are not there. This money has been restricted, too. So, I demand that the funds allocated to the Ministry of Minority Affairs for pre-matric, post-matric, and merit-cum-means scholarships should be released immediately. The unit cost has also not been increased.

On the PM POSHAN Scheme, the budgetary allocation of Rs. 12,500 crore remains the same as in the financial year 2024-25. The honorarium for cook-cum-helpers is Rs. 1,000 a month. For the last 10 years, it has not been increased. I demand that it be increased. Thank you.

श्री राजेश रंजन (पूर्णिमा) : सभापति महोदय, सरकार कहती है कि रुपया गिर नहीं रहा है, बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि अमेरिका इनके अच्छे दोस्त हैं, ट्रंप भी इनके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। वैश्विक तौर पर पिछले तीन से चार दिनों के अंदर 15-16 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। फॉरेन रिजर्व जो घटा है, वह कंपलीट रूप से घटा है। विदेशी मुद्रा 703 बिलियन से घटकर 687 बिलियन हो गया है। आरबीआई को रुपया बचाने के लिए डॉलर बेचने पड़ रहे हैं। इसलिए हम यह बात कह रहे हैं कि इनको पता नहीं है कि मुद्रा प्रबंधन विफलता सबसे क्रूर आर्थिक नीति होती है, जो भारत के लिए और आम आदमी के लिए सबसे बड़ा बोझ है। इसका खामियाजा सबसे ज्यादा गरीब को भुगतना पड़ता है। दूसरी तरफ ये सीधे टैक्स नहीं लगाते हैं, बल्कि ये महंगाई के द्वारा टोटल पैसा ले लेते हैं। ये टैक्स की बात करते हैं कि मैं टैक्स नहीं लगा रहा हूं। 140 करोड़ लोगों में से 120 करोड़ लोग, जो मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं, उनसे महंगाई के द्वारा पैसे ले लेते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि महंगाई के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? ये इसके बारे में पहले बता दें।

दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, एआई की रफ्तार सबसे ज्यादा है और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। कुछ पॉइंट हैं, जो बाकी देशों में सफल हुए हैं, मैं उनके बारे में यहां बताना चाहता हूं। हमारे संसदीय क्षेत्र पूर्णिमा और पूरे बिहार में पैसा सीधे नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट के लिए मिले। यूरोपियन यूनियन कहता है कि वह सीधे पैसे नहीं देते हैं, बल्कि वह स्थानीय संस्थाओं को अच्छे और पक्के एआई ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रांट या अनुदान देते हैं। वहीं से वह सीखेगा और सिखाएगा। आम आदमी और गांव के बच्चों में हुनर बढ़े। हर एरिया में एआई ट्रेनिंग सेंटर, रीजनल एआई हब बने। कनाडा की तरह हर एरिया के स्थानीय कॉलेज या स्कूल को अपग्रेड करके एक एआई ट्रेनिंग हब बनाना चाहिए। एआई कंप्यूटर और डिवाइस सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव, कस्बे के बच्चों को मिले। इससे सबको बराबर का मौका मिलेगा। आप वह चीज सिखाओ, जो इलाके में काम आए। प्रिंसिजन एग्रीकल्चर सिखाने की बात कई बार एआई के द्वारा हुई है। यूनेस्को कहता है कि स्थानीय जरूरतों के हिसाब से सिखाना चाहिए। इससे ट्रेनिंग काम आएगी और बच्चों को जल्दी नौकरी मिलेगी। आप पहले टीचरों को पक्का करो। एआई ट्रेनिंग कौन देगा? हमारे पास एक्सपर्ट टीचर्स नहीं हैं। इसलिए स्थानीय शिक्षकों को एआई एक्सपर्ट बनाने के लिए उन पर खर्च होना चाहिए। एशियन देशों ने भी यही किया है। सरकार को यह शर्त रखनी चाहिए कि स्थानीय उद्योग या कंपनी को भी उसमें थोड़ा पैसा लगाना होगा और बच्चों को सीधे मेंटरशिप देनी होगी। इसलिए मेरी डिमांड इसमें यह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एआई और डिजिटल स्किल सेंटर्स स्थापित किए जाएं। किसानों को एआई टूल्स से फसल प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, एसएमई को डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और एआई आधारित बिजनेस टूल्स का प्रशिक्षण मिले। महिलाओं और बच्चों को बेसिक एआई, कोडिंग और डिजिटल साक्षरता सिखाई जाए। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में मैंने पहले बोला है।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राजेश रंजन : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। प्रदूषण और पानी पर कोई बजट नहीं होता है। जल मिशन योजना के बारे में हमारे मित्र ने कह दिया है। दिल्ली के एक बच्चे ने प्रदूषण के बारे में हमसे कहा कि मेरी पढ़ाई ऑनलाइन करवा दीजिए, ताकि हमें स्कूल न जाने पड़े, नहीं तो सारे बच्चे मर जाएंगे।

प्रदूषण पर कोई चर्चा नहीं होती है। 90 प्रतिशत बीमारियां पानी की वजह से हो रही हैं। इनके लिए साफ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज, मनरेगा जब प्रभावित हो रही थी, तब ये मजाक बना रहे थे। ये नाम बदलने में माहिर हैं, लेकिन बिहार में मनरेगा का बजट घटाते जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि गरीबों को जो पांच डिसमिल जमीन देने की बात थी, उसके लिए सरकार बजट दिलाए।

माननीय सभापति : आप 30 सेकेण्ड में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राजेश रंजन : सर, छात्रों के साथ यह होता है कि एग्जाम कराने के लिए 500 रुपये लेते हैं और उसके ऊपर 100 रुपये टैक्स लगा देते हैं, जीएसटी लगा देते हैं। मैं चाहता हूँ कि छात्रों से फॉर्म भरने के लिए मात्र 100 रुपये लिए जाएं।

सर, अंत में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोसी सीमांचल के लिए विशेष पैकेज हो और मक्का और मखाना के ऊपर कम-से-कम 10-10 फैक्ट्री लगाई जाएं, यह मेरी मांग है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर मुझे बोलने का समय दिया। हम मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि सरकार ने कई घोषणाएं कीं। जिन राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं, वहां अतिरिक्त बजट की घोषणा भी होती है। दुर्भाग्य से वर्ष 2014, 2019 और 2024 के अंदर जिस राजस्थान ने आपकी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस राजस्थान को जुमलों के सिवाय कुछ भी नहीं मिल रहा है। विशेष राज्य का दर्जा देने की हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। हम ऐसे प्रांत से आते हैं, जहां आप पुराने किस्से-कहानी भी सुनोगे कि लोग 20-25 किलोमीटर तक तालाबों से किसी तरह सर पर रखकर पानी लेकर आते थे। वे परिस्थितियां भी राजस्थान ने देखीं।

सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि जब वित्त मंत्री जी जवाब दें, तो इन बातों का ध्यान रखें। देश के नागरिक दो जून की रोटी को तरस रहे हैं। यह स्थिति तब है, जब सरकार कई जन-कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को लाभान्वित करने की बात करती है। मुझे विशेष रूप से यह भी कहना है कि विगत पांच वर्षों में गरीबों की स्थिति वैसी ही है। आप सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर आरोप लगाकर जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, मगर यह देश समझता है। पहले कार्यकाल में तो आपने विपक्ष पर आरोप लगा दिए, लेकिन अब लोग आपसे कुछ काम चाहते हैं। देश का जवान आपसे काम चाहता है, देश का किसान, देश का प्रत्येक वर्ग, मोदी जी जो घोषणाएं कर रहे हैं, वे धरातल पर कैसे आएँ, यह देश की जनता जानना चाहती है। मैं वित्त मंत्री जी को सदन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान में सदन में और सदन के बाहर भाषण तो बहुत दिए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बेरोजगारी को रोकने के ठोस समाधान आपने नहीं किए हैं। केंद्र या राज्य के खाली पद आप देख लीजिए। मैं जिस राजस्थान से आता हूँ, वहां की नौकरी में पांच लाख पद खाली हैं। सबसे बड़ी बात आप किसान की जमीन लेकर उद्योग लगा रहे हो, वहां तो रूल बना दीजिए कि कम से कम 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ताकि लोगों को कमाने के लिए बाहर न जाना पड़े। यह बेरोजगारी की ऐसी समस्या है कि यदि आपने इसका इलाज नहीं किया, तो वह दिन दूर नहीं, जब बेरोजगार खुद अपना हक मांगने के लिए राजधानी को घेर लेगा और आप देखते रह जाएंगे, जैसा कि दूसरे राज्यों के अंदर हो रहा है। नौजवान का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि नौजवानों ने ही आपको तीसरी बार सत्ता सौंपी है, नहीं तो आप विपक्ष पर आरोप लगाते-लगाते खुद विपक्ष में न बैठ जाओ।

उर्वरकों की कमी से इस समय किसान जूझ रहा है। सभापति महोदय, मैं अक्टूबर माह के अंत का एक समाचार पत्र पढ़ रहा था। रबी के सीजन के लिए भारत सरकार ने फॉस्फोरस और सल्फर उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ा दी। किसानों को मूल्य वृद्धि से राहत देने के लिए 377,952 करोड़ रुपये आबंटित किए, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे रबी की फसल हो या खरीफ की, किसानों को समय पर डीएपी और यूरिया समय पर नहीं मिलता है। मांग के क्रम में आपूर्ति नहीं आती है। मेरे राजस्थान में तो सरकार ने खाद की खरीद के लिए लाइन में खड़े किसानों पर लाठीचार्ज करवा दिया। हमारे वहाँ के कृषि मंत्री जी जरूर अखबारों में छपने के लिए वहाँ दौरा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से किसान को यूरिया और डीएपी के लिए भी लाठियाँ खानी पड़ रही हैं।

सभापति महोदय, मेरे राजस्थान के अंदर सरकार से मैं मांग करूँगा कि करौली सवाई माधोपुर की सीमा पर प्रस्तावित डूंगरी बांध निर्माण के विरोध में आंदोलन चल रहा है। चार-पांच बड़ी महापंचायतों से हजारों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हुए। ग्रामीणों के अनुसार, इस बांध से उनकी उपजाऊ कृषि भूमि, प्राकृतिक जल स्रोत और सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो जाएंगी। साथ ही रणथम्बोर टाइगट रिजर्व, केला देवी वन्य जीव अभयारण्य का 22 से 37 वर्ग किलोमीटर हिस्सा भी डूब क्षेत्र में आ सकता है। इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। पहले चरण में सिंचर गांव के करीब 50 हजार दलित-आदिवासी, मीणा, गुर्जर और किसानों के परिवारों पर विस्थापन का भी खतरा है। सरकार इस पर पुनर्विचार करे। (व्यवधान)

सभापति महोदय, हम वे लोग हैं, जो लास्ट तक सदन के कोरम को पूरा रखते हैं। आप हमारे साथ इस तरह से न करें। आप खुद सिंगल मैम्बर पार्टी से चुन कर वहाँ आए हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं एमएसपी को कानून के दायरे में लाकर किसानों की कर्ज माफी की बात कर रहा हूँ। किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए। उनकी फसल की खरीद एमएसपी पर हो। आपने राइडर हटा दिया है। पहले आप उनसे 25 विंटल खरीदते थे, अब वह 40 कर दिया गया है लेकिन आपका टोकन नहीं हो रहा है। मैं राजस्थान का एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ जिसमें 2,81,350 मीट्रिक टन मूंग हुआ, 42,777 मीट्रिक टन मुंगफली का अनुमानित उत्पादन हुआ है। (व्यवधान) आप कहते हैं कि एमएसपी पर कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत जिंस खरीदते हैं, लेकिन 10 प्रतिशत (व्यवधान)

माननीय सभापति : कंकलूडिंग रिमाक्स। आप एक वाक्य में अपनी बात कंकलूड कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल : महंगाई के नियंत्रण के अनुसार, तेल, गैस किस तरह बढ़ रही है? किसानों के खनन पट्टे उनके खातेदारी के अंदर दिए जाएं। नागौर में जो पान-मैथी हो रही है, उसको जीआई टैग दिया जाए। मैं इसके लिए पीयूष गोयल जी से मिला था, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि पान-मैथी को जीआई टैग मिलेगा, जिससे किसानों को फायदा होगा। (व्यवधान)

सर, लास्ट है। स्टेट की डीएलसी बहुत कम है। जमीन का बाजार मूल्य 25 लाख रुपए है लेकिन आप डीएलएसी से पांच गुना मूल्य दे रहे हैं। मेरे वहाँ 35 हजार रुपए डीएलसी है। अगर 20 हजार रुपए डीएलसी है तो उन्हें एक लाख रुपए मिलेंगे। (व्यवधान)

माननीय सभापति : धन्यवाद। आप अपनी स्पीच समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। मैं यह बोल देता हूँ। (व्यवधान)

माननीय सभापति : हनुमान बेनीवाल जी अपनी बात समाप्त नहीं करेंगे । चंद्रशेखर जी, आप बोलिए ।

(व्यवधान)

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : धन्यवाद, सभापति जी । सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को (व्यवधान)

माननीय सभापति : हनुमान बेनीवाल जी, आप एक वाक्य में अपनी बात कंकलूड करिए । चंद्रशेखर जी, आप एक सेकेंड के लिए रुक जाइए ।

(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, मेरी मांग है कि मैं नागौर में मेड़ता से पुष्कर रेलवे लाइन की बात करूं या नागौर के निकट भदवासी, मकोड़ी, बालासर, गंठीलासर, पिलनवासी आदि गांवों में आरएसएमएमएल ने भूमि अवाप्ति के लिए गजट निकाला है । किसानों की मंशा के खिलाफ ऐसे सैंकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे । वहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है । इथेनॉल फैक्ट्री के समय भी लाठी चार्ज हुआ है । यह ठीक नहीं है । यह मेरी मांग है कि आप थोड़ा-सा सुधार करें ।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : धन्यवाद, सभापति जी । सदन के सभी सम्मानित सदस्यों और भारत के 140 करोड़ से ज्यादा मेहनतकश भाइयों-बहनों को मेरा जय हिंद । जिनके खून-पसीने की कमाई से सरकार चलती है । यह वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैच सरकार की घोर नाकामी जीता-जागता सबूत । कुल सकल अतिरिक्त व्यय 1.32 लाख करोड़ रुपए का, लेकिन वास्तविक नगद खर्च सिर्फ 41,455 करोड़ रुपए, बाकी 90,812 हजार करोड़ रुपए कथित बजट के नाम पर छिपा कर हिसाब चुकता करने का खेल । फरवरी को मुख्य बजट असत्य और खोखला साबित हो गया । बड़े-बड़े वादे किए गए थे और इमरजेंसी में अतिरिक्त पैसे मांग रहे हैं, यह कोई मामूली गलती नहीं है, बल्कि सुनियोजित लूट और जनता के साथ विश्वासघात है । हम जोरदार मांग करते हैं कि शून्य आधारित बजटिंग तुरंत लागू की जाए । सीएजी से स्वतंत्र और सख्त जांच करवाई जाए, सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने इन कार्यों पर लज्जा आनी चाहिए ।

सभापति महोदय, वैसे तो सरकार एससी, एसटी और ओबीसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाई तो निजीकरण का एक बहुत बड़ा खेल किया गया । इंडिगो ने क्या किया? आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी कि आप अपनी जनता, पैसेंजर्स को कोई आवश्यक सुविधा उपलब्ध करा पाते । निजीकरण की आड़ में एससी, एसटी और ओबीसी को नुकसान करने के चक्कर में बहुत नुकसान किया । सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स एवं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एससी, एसटी और ओबीसी के बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं ।

रक्षा के लिए 41 हजार करोड़ रुपए की मांग - ये विमान, हथियार, मशीनरी के नाम पर मनचाहा धन उड़ा रहे हैं । एचएएल में देरी के बावजूद काल्पनिक बचत दिखा कर हिसाब बराबर कर रहे हैं, यह पारदर्शिता है या धोखा है । गृह मंत्रालय का खर्च फट पड़ा है । जनगणना, आईजीटी और क्षेत्रीय बैक्स के नाम पर लेकिन आज भी मणिपुर में सैंकड़ों लोग बेघर भटक रहे हैं । वहां सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन शांति और पुनर्वास कहां है? यह दिखावा है या वास्तविक लोकाशाह । आप मानवीय संकटों को नजरअंदाज नहीं कीजिए । दिव्यांगों को मजबूत करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई, भ्रष्टाचार चरम पर है और टेलीकॉम में बड़ी कंपनियों को जीवन रेखा दे कर, जब 1.2 करोड़ नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं, युवाओं के साथ छल क्यों कर रहे हैं?

19.00 hrs

आपने युवाओं को किसके भरोसे छोड़ रखा है, युवाओं ने आपका क्या बिगाड़ा है? यह जनता का खुला अपमान है, सफाई कर्मचारी आज भी सीवर में मर रहा है और हम चांद पर चले गए हैं। विदेश मंत्रालय विदेशी प्रोजेक्ट पर फिजूलखर्ची कर रहा है जबकि घर के बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। 65 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, यह सरकार का डाटा है, मंत्री जी ने जवाब दिया है। इस मामले में यूपी दूसरे नम्बर पर है जबकि पहले नम्बर पर गुजरात है। स्वास्थ्य सेवाएं लाचार है, विकलांगों को मामूली मदद, संस्कृति और विरासत सड़ रही है।

सभापति जी, क्षेत्रीय असमानता बढ़ रही है। कुछ यूटीज को फोकस करके गांव और कस्बों को भूला रहे हैं जबकि भारत गांवों में निवास करता है। यह दस्तावेज देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा आघात है, हम इसको पूरी ताकत से खारिज करते हैं या तो तुरंत सुधार हो या शून्य आधारित बजट बने। सी एंड एजी की गहन जांच और हर रुपये का परिणाम आधारित ऑडिट होना चाहिए।

उर्वरक विभाग के लिए 18 हजार 525 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग, विदेश से आयातित उर्वरकों को प्राथमिकता देकर हमारे किसानों का खून निचोड़ रही है। आप आत्मनिर्भर भारत का ढोंग रचते हो, लेकिन आयात पर निर्भरता बढ़ाकर मिट्टी को बंजर बना रहे हो। हर साल हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एमएसपी की गुहार अनसुनी पड़ रही है। यह सब्सिडी किसानों के लिए है या विदेशी कंपनियों के लिए है। यूरिया नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है। आयात माफियाओं के लिए तुरंत इस लूट को बंद हो और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए।

पेट्रोलियम मंत्रालय पर 9 हजार 500 करोड़ रुपये का बोझ है। एलपीजी सब्सिडी के नाम पर तेल कंपनियों को मुआवजा देकर आम आदमी की जेब सरकार काट रही है। जब ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं तो महंगाई जनता को मार रही है, तब क्रोनी कैपिटलिज्म का नंगा नाच हो रहा है, कॉर्पोरेट मुनाफा रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज युवा आंदोलन कर रहा है, आज इलाहाबाद में आंदोलन चल रहा है। दो-तीन दिन पहले मैं एक विषय पर बोल रहा था, समय कम था तो अपनी बात पूरी नहीं रख पाया।

सभापति जी, हम लोग अपमान से हारे नहीं हैं। आप भी सिंगल पार्टी के मेंबर हैं, खुद इस बात को समझते हैं। मेरे साथियों ने कहा कि आपको कम समय दिया। मैंने कहा कि समय संख्या आधारित होता है, हम लोग अपनी संख्या बढ़ाएंगे। हम लोग मेहनत करेंगे और संख्या बढ़ाएंगे।

मैं फाइनेंस मिनिस्टर से आग्रह करता हूं कि एमपी लैड स्कीम की राशि बढ़ायी जाए, पांच करोड़ रुपये में क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। जब तक नगीना का विकास नहीं होगा तो देश कैसे विकसित हो जाएगा? नगीना के लोगों के बारे में सोचिए, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। जय भीम, जय भारत। जय संविधान। जय मंडल। किसानों की जय और जवानों की जय।

श्री मोहम्मद हनीफ़ा (लद्दाख): सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री और गृह मंत्री जी का शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने लद्दाख के लिए रिवाइज्ड बजट में 148 करोड़ रुपये एलॉट किए हैं, इससे किसी हद तक दोनों ही डेवलपमेंट्स काउन्सिल के लिए 180 करोड़ रुपये की कटौती पूरा करने में मदद मिलेगी। जिससे लोकल डेवलपमेंट में राहत मिलेगी। इस साल यूटी लद्दाख के बजट ऐस्टिमेंट वर्ष 2024-25 के मुकाबले में तकरीबन 834 करोड़ रुपये की कैपिटल एक्सपेंडिचर कट का सामना करना पड़ा था, लेकिन लद्दाख के ओवरऑल बजट में कोई काबिल कट इज़ाफा नहीं हुआ, 834 करोड़ रुपये की बड़ी कटौती में से सिर्फ 148 करोड़ रुपये बहाल किए गए हैं, यही असली कन्सर्न है।

میں ماننیی ویئت منتری اور ماننیی گڑھ منتری جی کآ ڈھآن اک بههء اھل ٲءمینسٹریٹو ڈشؤ کی اور دلالنا کآھتا ہوں؁ جو سیڈھ لءءآخ کو ٲلوکےٹ کیٲ گٲ ٲنڈس کو خببب کرنے کی سھللیت متآسیر کرتے ہوں ۔ ٲمٲٲ لءءآخ کی ٲروکےٹ اور سکیوں کی منجوری اور ٲءمینسٹریٹو ٲٲوول کے لیٲ ٲاڈنہنشیل ٲاवर ڈیلیگےٹ کرتی ہے؁ یہ ڈیلیگےٹ ٲاवर जरوری تھی؁ ڈیلیگےٹ ٲاवर ٲورے یوٹی کے ڈےولٲمےنٹ میں اھل کیردار اءا کرتی ہے ۔ خآسآور ٲر لءءآخ کے ٹوٲوگرافیکل کھلےنچ اور ڈیفیکلٹ ٲکسسبیلٹیڈ میں ڈس ڈمٲاؤر سسٹم مکآبھی آور ٲر ٲسلا کرنے اور مچبوت بنآاا ۔ آاوامی کاموں میں سموث ٲکجیویوشن کو مومکین بنآاا ۔ هال ہی میں ٲمٲٲ نے لءءآخ کے ٲءمینسٹریٹو دیٲ گٲ ٲاڈنہنشیل ٲاवर وآٲس لے لیٲ تھے ۔ بآء میں مؤخلالیٲ لوگوں کے کنسرن کے بآء اخلیآار آو وآٲس دے دیٲ مگر انٲاؤنٹے بآء یہ ہے کی کھوٹ سے لےکر بڈے ٲروکےٹ کے ٲٲوول اور اٲرئجل کی اھل ٲاवर ٲمٲٲ کے ٲآس ہی ہے ۔

مھوءء؁ میں خآس آور ٲر کھنا کآھتا ہوں کی لءءآخ ٲءمینسٹریٹو اور جؤوگرافیکل سےٹ-آٲ بگور اسةمبلھی والے یونین ڈرٹریٹریج ہوں؁ اسة بیلکول مؤکھتالیٲ ہے ۔ لءءآخ کی جؤوگرافی اور سدیوں کی وچھ سے سال میں سآت-آآٹ مھینے کام کرنے کآ مویا میلآا ہے ۔ ديسمببر سے مڈ تک یہاں سڈکے بء رہتی ہے؁ لیهاچا اكر سآرے ٲروکےٹس کے ٲٲوول اور اٲرئجل کے لیٲ ٲمٲٲ کو بھچنا؁ جو چمیني هالآآ سے ڈور ہے ن سیرٲ مؤشکل هوگا بلکي بھوآ وکآ بھی لآوگی ۔ چيسے لءءآخ کے ٲورا کام سچن کآ چآا هو چآوگا؁ کام کی مؤءآ ٲوری نہيں هوگی ۔ کھوٹے مگر اھل ڈےولٲمےنٹل مکآمی لوگوں کے لیٲ जरوری ہے؁ وھ ڈری کآ شیکآر هوگا ۔ سهاٲتی مھوءء؁ میں آآٲکے چریٲ هوم مینسٹر اور ٲاڈننس مینسٹر سے گؤآریش کرتآ ہوں کی ڈےولٲمےنٹل ٲروکےٹس کی بههآر مچبوت منسوبابندی اور وکآ ٲر ڈمٲلیمےنٹیشن کے لیٲ जरوری ہے کی ٲروکےٹس کے ٲٲوول اور اٲرئجل کے اخلیآار چيس آرھ ٲهله لٲٹرینٹ گورنر؁ کامیشنر اور ڈٲٹی کامیشنر کے ٲآس تھے؁ اسة ڈوبآا بھال کیآا چآٲ ۔

میں آآٲکے چریٲ آؤنرےبل ٲاڈننس مینسٹر کی آوچؤو بچآری ٲرےمورک سے هآکر کولھ اھم ٲنڈنگ لآببیلٹیڈ کی آرف دلالنا کآھتا ہوں ۔ یوٹی ٲءمینسٹریٹو نے لےھ اور کآرگیل میں ٲورے هو چوکے کاموں کے خببب کے لیٲ 28 کروز روٲے کی جو ڈرکھآسآ کی ہے؁ یہ ٲوری هو چوکی ہے لےکین جو ٲنڈنگ ہے؁ اسة کی اءآآیگی میں ڈری کام میں بھوآ چآآآا خلل ٲءآ کر رہی ہے اور ڈسکے سآھ ہی ڈکےداروں کے یکین کو بھی کمچور کر رہی ہے ۔ ڈسکے الالآا یوٹی ٲءمینسٹریٹو نے لےھ اور کآرگیل میں کاموں کے لیٲ چمین اور ٲلانٹیشن کے کم ٲنسیشن کے لیٲ 130 کروز روٲے کی لآببیلٹی ٲڈی ہے ۔ ڈن ٲنڈس کو چلڈ سے چلڈ ریلیچ کیآا چآٲ ۔ لءءآخ میں ڈچی نیئرنگ کآلےچ کڈ سالوں سے منچور هو چوکآ ہے اور ڈسکے کآرگیل چیلے میں چمین بھی ٲلآوٹ هو چوکی ہے ۔ چلڈ سے چلڈ ڈسکے لیٲ ٲنڈس ٲلآوٹ کرکے شورو کیآا چآٲ ۔ ڈسکے سآھ ہی ڈیگری کآلےچ جو کلر آر کآرگیل ڈیگری کآلےچ چل رہآ ہے؁ ڈسے بھی ٲنڈس کی وچھ سے ڈری ن کرکے چلڈ ٲورا کیآا چآٲ ۔

چنآ محمد حنیفه (لڈآ): چیرمین صآب؁ آٲ نے مچھ سپلیمنٹری ڈیمانڈس فور گرانٹس ٲر بولنے کآ موقع دیا؁ آٲ کو شکریه۔ سب سے ٲهله میں مؤآرم ٲائننس منسٹر اور ٲوم منسٹر صآب کآ شکر گزار هوں کہ انھوں نے لڈآ کے لئے ریواؤرڈ بچٹ میں 148 کروز روٲے ایلوٹ کئے ٲس؁ اس سے کسی آء تک دونوں ٲی ڈیولپمنٹس کآؤنسل کے لئے 180 کروز روٲے کی کٹوٹی ٲورا کرنے میں مدد ملے گی۔ جس سے لوکل ڈیولپمنٹ میں رآآ ملے گی۔ اس سال یوٹی۔ لڈآ کے بچٹ ايسٹی میٹ سال 2024-25 کے مقابلے میں تقریبآً 834 کروز روٲے کی کیٹل ایکسپنڈیچر کٹ کآ سامنا کرنا ٲڑآ تها؁ لیکن لڈآ کے اور آل بچٹ میں کوئی قابلِ ٲدر آصافه نہیں هوآ؁ 834 کروز روٲے کی بڑی کٹوٹی میں سے صرف 148 کروز روٲے بحال کئے گئے ٲس؁ یہ اصلی کنسرن ہے۔

میں مؤآرم ٲائننس منسٹر صآبھ اور ٲوم منسٹر صآب کآ ڈھبان ایک بے آء اٲم ایڈ منسٹریٹو ایشیو کی ٲرف دلانا چآھتا هوں؁ جو سیدھے لڈآ کو ایلوکیٹ کئے گئے ٲنڈس کو خرچ کرنے کی سولیات متآئر کرتآ ہے۔ ايم.اچ.اے۔ لڈآ کی ٲروچیکٹ اور اسکیموں کی منظروری اور ایڈ

منسٹریٹیو ایپروول فائنن شیل پاور ڈیلیگیٹ کرتی ہے، یہی ڈیلیگیٹ پاور ضروری تھی۔ ڈیلیگیٹ پاور پوری ہوئی۔ کے ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خاص طور سے لڈاخ کے ٹوپوگرافیکل چیلنج اور ڈیفی کلٹ ایکسیس بلیٹیز میں اس ایمپاورسٹم مقامی طور پر فیصلہ کرنے اور مضبوط بنایا۔ عوامی کاموں میں اسموتھ ایکزیکیوشن کو ممکن بنایا۔ حال ہی میں ایم۔ایچ۔اے۔ نے لڈاخ کو ایڈمنسٹریٹیو دئے گئے فائنن شیل پاور واپس لے لئے تھے۔ بعد میں مختلف لوگوں کے کنسرن کے بعد اختیارات تو واپس دئے مگر بد قسمتی سے بات یہ ہے کہ چھوٹے سے لیکر بڑے پروجیکٹ اپروول اور اپریزل کی اہم پاور ایم۔ایچ۔اے۔ کے پاس ہی ہے۔

چیرمین صاحب، میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ لڈاخ ایڈمنسٹریٹیو اور جغرافیہ سیٹ اپ بغیر اسمبلی والے یونین ٹیرٹریز ہیں، اس سے بالکل مختلف ہیں۔ لڈاخ کی جغرافیہ اور سرحدوں کی وجہ سے سال میں 7-8 مہینے کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دسمبر سے مئی تک یہاں سڑکیں بند رہتی ہیں، لہذا اگر سارے پروجیکٹس کے اپروول اور اپریزل کے لئے ایم۔ایچ۔اے۔ کو بھیجنا جو زمینی حالات سے دور ہے نا صرف مشکل ہوگا بلکہ بہت وقت بھی لگے گا۔ جس سے لڈاخ کا پورا کام سیزن کا ضائع ہو جائے گا۔ کام کی مدت پوری نہیں ہوگی۔ چھوٹے مگر اہم ڈیولپمنٹ مقامی لوگوں کے لئے ضروری ہے، وہ دیری کا شکار ہوگا۔

چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ ہوم منسٹر اور فائننس منسٹر سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بہت مضبوط منصوبہ بندی اور وقت پر امپلی مینٹیشن کے لئے ضروری ہے کہ پروجیکٹس کے اپروول اور اپریزل کے اختیار جس طرح پہلے لیفٹنٹ گورنر، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے پاس تھے، اسے دوبارہ بحال کیا جائے۔

سے ہٹ کر کچھ اہم Budgetary Framework میں آپ کے ذریعہ آنریبل فائننس منسٹر کی توجہ کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ یوٹی۔اے۔ ایڈمنسٹریٹیشن نے لیہ اور کارگل میں پورے Liabilities پینڈنگ ہو چکے کاموں کے خرچے کے لئے 28 کروڑ روپے کی جو درخواست کی ہے، یہ پوری ہو چکی ہے، لیکن جو پینڈنگ ہے، اس کی ادائیگی میں دیری کام میں بہت زیادہ خلل پیدا کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹھیکیداروں کے یقین کو بھی کمزور کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ یوٹی۔ایڈمنسٹریٹیشن نے لیہ کے لئے 130 کروڑ روپے کی Compensation اور کارگل میں کاموں کے لئے زمین اور پلانٹیشن کے پڑی ہے، ان فنڈس کو جلد سے جلد ریلیز کیا جائے۔ لڈاخ میں انجینئرنگ کالج کئی سالوں Liability سے منظور ہو چکا ہے اور اس کے لئے کارگل ضلع میں زمین بھی ایلاٹ ہو چکی ہے۔ جلد سے جلد اس کے لئے فنڈس ایلوٹ کر کے شروع کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ڈیگری کالج جو کلسٹر کارگل ڈیگری [کالج چل رہا ہے، اسے بھی فنڈس کی وجہ سے دیری نہ کر کے جلد پورا کیا جائے۔

SHRI SHREYAS M. PATEL (HASSAN): Thank you, Sir. I rise to speak on the Supplementary Demands for Grants for 2025-2026. Every year, the Government comes back in mid-year for more money. Corrections are normal but the size of these Demands shows weak planning and frequent policy mismatches. The Government now seeks over Rs. 1.32 lakh crore as additional expenditure but much of it is adjusted through savings and recoveries. If planning was strong, such large revisions would not be needed.

Sir, let me highlight a few things. The first is regarding the Department of Fertilizers. The Ministry gave a statement saying that India will stop importing urea by the end of the year 2025. Now, additional demand for subsidy under the imported urea scheme shows that self-reliance is a distant dream in India. This can be substantiated by the fact that urea production has actually gone down from 314 LMT to 307 LMT. Most of our fertiliser plants are old but there is no new support for PSUs. Instead of moving towards self-reliance, the Government is asking for even more subsidy money.

The second is regarding the Department of Telecommunications. The Government now wants nearly Rs. 37,000 crore to convert Vodafone-Idea dues into equity. Overnight, the Government becomes the largest shareholder in a private company struggling for years. If the investment loses value, who takes the hit? It is the common taxpayer. These are not just corporate dues; these are the dues of the public.

In the Petroleum Ministry, the Government seeks Rs. 12,000 crore more for LPG under recovery, despite already approving Rs. 30,000 crore just a month ago. Yet many poor households still find LPG unaffordable, with subsidies not reaching them effectively via DBT. Despite substantial spending, regular refills remain a struggle, needing rethinking to prioritise the direct benefits for end-users over company stabilisation.

Sir, before I conclude, I want to briefly highlight the issues of my region, Hassan. The Upper Badra Project is the lifeline of our districts Arsikere and Kadur Taluk. The Centre had promised Rs. 5,300 crore. The State has requested again. If the project receives the National Project status, 60 per cent of the funding would be done by the Union Government, but the approval is still pending. The people back home feel that the Centre is not taking their water needs seriously.

The next is of the Mother and Child Hospital, which we have requested in the August House, for the Kadur and Arsikere Taluks. These are growing towns with a rising population. There is no allocation of support in the Supplementary Demands.

Sir, I have last two demands. The last is the human and animal conflict. There is a severe human and animal conflict day by day. It has been severe and it is more serious in my constituency. For the past 21 years, nearly 75 people have lost their lives. The farmers are not only struggling for the lives of themselves, they are struggling to safeguard the crops which we have grown. I request through you, Sir,

to the hon. Madam, that at least in this Supplementary Budget, it has not been allotted and so in the upcoming Budget to kindly include the human and animal conflict for the long term.

Sir, the last is our dream and it is the dream of our Haasan, that is an IIT for Haasan. Already the land has been allotted for the IIT. In this Supplementary Budget, it has not been allocated. Kindly, at least allot in the upcoming Budget an IIT for Haasan. It is the dream of our young Indians.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

Shri Abdul Rashid.

श्री अब्दुल रशीद शेख (बारामूला) : महोदय, यूटी होने के नाते हमारे बहुत से मामलात केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी पहली रिक्वेस्ट यह है कि जो पैकेज दिए जाते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है। वित्त मंत्री जी सदन में बैठी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर को फुल-प्लेज्ड पैकेज दिया जाए। इसके अलावा जितने भी सेंट्रल विभाग हैं, दो परसेंट नौकरियां जम्मू-कश्मीर के नजवानों के लिए रिजर्व की जाएं, जिन्होंने बहुत मुश्किलात देखे हैं। इंड्स वाटर ट्रीटी का जिक्र किया जाता है और वह तोड़ भी ली गई लेकिन जो लॉसेस जम्मू-कश्मीर के लोगों को हुए हैं,

How will you compensate it? We hope that you will come up with some concrete thing. इसी तरह हमारी फ्रूट इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, वह बरबाद हो चुकी है। आपने अमरीकन फ्रूट्स पर टैक्स कम कर दिए हैं और जम्मू-कश्मीर का फ्रूट तबाही के मुहाने पर है और इसके रिवाइवल के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह आपको नए टूरिस्ट्स डेस्टिनेशन्स बनाने की भी जरूरत है। गुलबर्ग, पहलगाम तो हैं ही, इनके अलावा बहुत ही खूबसूरत जगहें जैसे मंगास, दूधपत्थरी, तंगधार, मोनाबल, रंगवार या ऐसी जगहें हैं जो गुलमर्ग, पहलगाम से भी खूबसूरत हैं। उन्हें टूरिस्ट मैप पर लाने की जरूरत है। इसी तरह गुलमर्ग में हमारे जो होटल्स हैं, there are certain issues facing them. उन्हें लीज बढ़ाने के नाम पर तंग किया जा रहा है। They should not be displaced and dislodged. पटल में हमारा जो नेशनल हाईवे है, एक ट्रौमा अस्पताल की बहुत ज्यादा जरूरत है, along with a blood bank. मेरी सरकार से और वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि since I have got no redressal of my issues, क्योंकि मैं यहां से सीधा बदकिस्मती से जेल जाऊंगा। I cannot reach out to the Ministers and bureaucrats. इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक डायरेक्शन जाए कि मेरे जो इश्यूज हैं, वे संबंधित विभागों में जाएं। मैं नार्थ कश्मीर के लिए डिमांड करते हैं क्योंकि यह पहाड़ी और बार्डर का इलाका है, एक एम्स बारामूला में बनाया जाए। बांडीपोरा में एक मेडिकल कालेज बनाने की जरूरत है। सोपौर में आईआईएम कायम किया जाए। Since, it is a UT रेवेन्यू सेंटर डायरेक्टली डील करता है, सुपौर और हंदवाड़ा में आलरेडी हमारे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्हें आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स बनाएं तो मेहरबानी होगी। बीरबा को आप एक हिल डिस्ट्रिक्ट बनाएं। नरसिंह कालेज की जरूरत है। 950 करोड़ रुपये एमजी नरेगा में लेबर कम्पोनेंट में हमारा पैसा बाकी है, इसी तरह लोलाब सोपौर और लोलाब भांडीपुरा के दरमियान बड़े मेगा रोड्स बनाने की जरूरत है जिससे बार्डर टूरिज्म भी डेवलप हो। इससे काफी फायदा मिलेगा और मेडिकल कालेज जोगल हंदवाड़ा में। पिछले डेढ़ साल से काम रुका है, पचास करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं लेकिन उसके बाद कहा कि now, the area is flood-

prone. इन आर्किटेक्ट्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन्होंने नहीं देखा कि एरिया फ्लड प्रोन है। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेडिकल कालेज के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किए और बाद में याद आया कि यह एरिया फ्लड प्रोन है। लोगों ने सैंकड़ों कनाल जमीन दे दी। So, action should be initiated against the officials who identified the site. मेरा आखिरी पाइंट है कि मेडिकल कालेज पर काम तुरंत शुरू किया जाए और एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि एमपी कहाँ जाए। दिल्ली के एमएलए के पास दस करोड़ रुपये का एमएलए फंड है। On behalf of all MPs, दामन फैला कर कहता हूँ कि कम से कम 15-20 करोड़ रुपये रिक्मेंड कीजिए। यह मेरा हम्बल सब्मिशन है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दीजिए क्योंकि आप जो पैसा वहाँ देते हैं, वह खर्च नहीं हो रहा है।

श्री उमेशभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : माननीय सभापति जी, मैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारा छोटा-सा प्रदेश दमन एवं दीव, भले ही क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन यहाँ की जनता की आकांक्षाएँ बहुत बड़ी हैं। मुझे यह कहते हुए अत्यंत गर्व है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तथा माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी कि हमारे प्रदेश पर विशेष कृपा-दृष्टि रही है। उनका सीधा मार्गदर्शन हमारे प्रदेश को मिलता है और उनके मार्गदर्शन के फलस्वरूप हमारे छोटे से प्रदेश को केंद्र सरकार की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिला है। दीव को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल करना, नमो मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बर्ड एवियरी, नमो पथ, राम सेतु जैसी कई अमूल्य सौगातें तथा वनाकबारा (दीव) में लंबे समय से लंबित क्रीक ड्रेजिंग की माँग को पूरा करना ये सभी केंद्र सरकार की दूरदर्शिता के उदाहरण हैं। इस योजनाओं की घोषणा के बावजूद ये परियोजनाएँ अब तक शुरू नहीं हो पाई हैं, मुझे मुझे पता चला है कि दीव के वनाकबारा क्रीक ड्रेजिंग एवं दीव पोर्ट ड्रेजिंग कार्य फंड की कमी के कारण अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं। फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इसके साथ ही दीव स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अभी अधूरा है, एवं कोस्टल विलेज, सीसीआरवी प्रोजेक्ट भी अभी शुरू नहीं हो पाया है। दीव की 90%से अधिक आबादी मत्स्य पालन पर निर्भर है। क्रीक में ड्रेजिंग न होने से क्रीक से जहाज़ अंदर आते-जाते वक्त बहुत समस्याएं होती हैं। थोड़ा सा ध्यान हटने पर घटना घट जाती है और मछुआरों को बड़ा नुकसान हो जाता है। ड्रेजिंग कार्य की समस्या से मछुआरों की दैनिक आय पर सीधा असर पड़ रहा है हमें पता चला है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जरूरी फण्ड अभी भी सेंटर से पूरा रिलीज नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सेंटर की बाकी राशि त्वरित रिलीज की जानी चाहिए ताकि ये सारे कार्य समय पर पूरे हो सकें। मैं इस पटल के माध्यम से केंद्र सरकार से कुछ मांगे करता हूँ कि वर्तमान सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में ही दीव फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट, वनाकबारा क्रीक एवं दीव पोर्ट की ड्रेजिंग तथा दीव स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की शेष कार्यों हेतु पर्याप्त अतिरिक्त राशि तत्काल जारी की जाए। कोस्टल विलेज (CCRV) डेवलपमेंट सहित सभी स्वीकृत परियोजनाओं के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया जाए। इन परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक उच्चस्तरीय मॉनिटरिंग सेल गठित की जाए। भविष्य में छोटे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए "फास्ट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की जाए, जिसकी तिमाही समीक्षा प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कार्यालय स्तर पर हो, ताकि फंडिंग में कभी देरी न हो।

महोदय हमारे यहाँ नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज नहीं मिल पा रहा है तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारे नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिले और उसके लिए विशेष फंड दिया जाए। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज में पीजी की सीट्स में जो फीस रखी है, वह बहुत ही ज्यादा है। या तो उस फीस को घटा दिया जाए या फिर स्कॉलरशिप जैसी कोई नीति बनाकर बच्चों से यह अतिरिक्त भार हटाया जाए।

महोदय, मैं एमपीलैड स्कीम के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे प्रदेश में मैंने जितने भी काम प्रस्तावित किए थे, गाइडलाइन्स के हिसाब से उन कार्यों पर 45 दिन में कार्य होना था, मगर एक साल तक वे कार्य पहले लंबित रखे गए। जब मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में रुख किया, मैं पहला सांसद हूँ जो एमपीलैड स्कीम के काम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ। जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया तब उन सारे के सारे कार्यों में कुछ हलचल हुई। (व्यवधान)

महोदय, मुझे एक मिनट का समय दीजिए। मेरी वेदना को आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मैं एमपीलैड का कार्य करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि गाइडलाइन्स के हिसाब से अगर 45 दिन में सांसद निधि का इस्तेमाल न करें। (व्यवधान)

ADV. GOWAAL KAGADA PDAVI (NANDURBAR): Sir, this Supplementary Demand is long on paper, but short on expectations.

Sir, I just want to ask one question. Only Rs. 41,455 crore is net cash outgo, while a massive Rs. 90,812 crore is book adjustment. This raises the classic question asked by fiscal experts; if Ministries had such large savings earlier, why did they over-project their Budget Estimates in the first place? Is it because of increasing the negotiating power?

Sir, I just want to ask one question directly about the SDG, which is about the telecommunications, the funds allocated for telecommunications. In my constituency, there are 4G towers. I have requested for their upgradation to 5G towers. वहां पर हिली एरिया है, वहां माउन्टेन एरिया आता है, वहां पर नेटवर्क नहीं आता है, नेटवर्क नहीं आयेगा तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स रहती हैं, जो बेनीफिट्स रहते हैं, उनका लाभ वहां के लोग कैसे ले पाएंगे? I am requesting that the 4G to 5G upgradation should be completed in a time-bound manner. BharatNet has started a project called BBNL. BBNL is absolutely not paying attention in my constituency. I am requesting the Government, through you, that BBNL should be taken away and BSNL should be handed over all the works.

I want to talk about the fertilizers. The uploaded Supplementary Demands for Grants document clearly shows a massive additional provision of Rs. 11,000 crore for PNK fertilizers and Rs. 7,525 crore for imported urea subsidies, yet on the ground of Nandurbar, farmers are standing in line at 4 am in the morning and often returning empty handed. I request the Government that the release of urea stocks in Maharashtra should be expedited as well as aspirational districts such as my Nandurbar district should be given priority. Gram level centres, farmer cooperatives and the distribution centres should be made the central focus of it.

Real time stock monitoring through mobile Apps and transparency portals should be initiated.

Regarding higher education in the Supplementary Demand for Grants, it has been mentioned that a significant Rs. 2,023.25 crore allocation for ONOS that is, One Nation, One Subscription under higher education is recommended. I strongly urge this Government the inclusion of Nandurbar in the priority roll out of ONOS as our tribal students have almost zero access to high quality journals.

I request establishment of a National Tribal University in Nandurbar to serve Maharashtra, Gujarat as well as Madhya Pradesh. There cannot be a Viksit Bharat without considering the Adivasis in the Bharat. So, that should be considered.

Regarding the Pradhan Mantri Awas Yojana, there are a few villages which are converted into hamlets which are called Padas in Marathi. Therefore, the Awas Yojana has not reached them. That should be increased at the earliest.

Regarding health and family welfare, it has been mentioned that there is a capital funding to complete all the new hospitals quickly. Regarding hospitals, I want to just make a request that the hospital and the medical college is divided by a road. There should be a skywalk in the middle and the funds should be allocated for that.

Regarding the Tapi Irrigation Project, Rs. 800 crore have been allocated by the State Government. I request the Central Government also to give some more funds for it so that the project can be completed and the drought situation in Nandurbar could be resolved.

Regarding roads and national highways, (*Interruptions*) I will just complete. There are two or three more points. There are a lot of accidents happening in Kondai Bari Ghat, Sakri Tehsil as well as Shewadi Phata. There is an urgent need for flyovers there.

Kindly consider that. There is a black spot there. I would also request that there should be a new four-lane highway from Shahada to Hargaon to Devipada to Gujarat. Kindly consider the new national highway project.

In the end, I just want to say that यह पूरक अनुदान नहीं है, यह सरकार की नाकामी का पूरक प्रमाण है और इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बजट में कुछ अलग प्रावधान दिए जाएं और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए ।

माननीय सभापति : धन्यवाद ।

श्री राजकुमार रोट जी ।

श्री राजकुमार रोट (बांसवाड़ा) : धन्यवाद, सभापति महोदय । आपने आज वर्ष 2025-26 की अनुदान की पूरक मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान किया है । मुख्य बजट में जो बजट का प्रावधान था, अधिकतर यह कह सकते हैं कि यह कागजों या पाइपलाइन में फंसा हुआ है, जो ग्राउंड पर नहीं जा पाया है, तो उस पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे । मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि अनुपूरक मांगों में जो बजट घटाया या बढ़ाया गया है, तो हमने विशेषकर एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा धरती को नशीली बना दिया है । हम यूरिया डीएपी को जरूरी मानते हैं, लेकिन यह इतना आदी हो गया है, जो कि भविष्य में हम सबके लिए घातक होगा, इसलिए सरकार ऐसा प्रावधान करे कि ऑर्गेनिक खेती पर फोकस करे और आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के लिए प्रावधान किया जाए कि जिस फसल को ये तैयार कर रहे हैं, उसको वह वे कहां बेचेंगे, फसल खराब हो जाती है तो उसके लिए अलग से सब्सिडी देने का प्रावधान करे ।

मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था की बात होती है, तो भारत देश पर वर्तमान में आंतरिक और बाहरी कर्ज 181 लाख करोड़ रुपये का है और उस हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति पर, यदि राजस्थान की और पूरे देश की बात करें, तो वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति पर 86 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है । इस स्थिति में देखा जाए, तो आज हम कह रहे हैं कि पहले सुनने में आता था कि डॉलर रुपये से गिर रहा है, लेकिन आज रुपये के मुकाबले डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है और यह सुनने में आ रहा था कि काला धन लाएंगे, यह काला धन कितना आया? देश की जनता को कहा गया था कि 15-15 लाख रुपये देंगे, वह 15 लाख रुपये वर्ष 2014 से लेकर आज तक कहा है, किसी के समझ में नहीं आया ।

19.22 hrs (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

महोदया, आज वर्तमान में जो देखा गया है कि जीएसटी को घटाने और बढ़ाने को लेकर बात उठी । पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जीएसटी के नाम से ढिंढोरा पीटा जा रहा है, तो जीएसटी बढ़ाया किसने था? वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2025 तक सरकार किसकी थी? जीएसटी बढ़ाने की वजह से 2 लाख 30 हजार से अधिक देश के छोटे व्यापारियों का व्यापार-धंधा खत्म हो गया है ।

माननीय सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि ट्राइबल एरिया में जीएसटी का कलेक्शन होता है, परंतु इस जीएसटी का लाभ ट्राइबल एरिया के लोगों को नहीं मिलता है । यह जीएसटी सिर्फ राजधानी के आस-पास या बड़े शहरों तक ही सीमित रह जाती है । जीएसटी में ट्राइबल एरियाज़ हेतु सेस कर लगाया जाए, ताकि यहां से जो भी कलेक्शन होता है, उसका उपयोग ट्राइबल क्षेत्र के लिए किया जाए । वर्तमान में देखा गया है कि भाजपा सीना तानकर कहती है कि हम विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं । हमें भी गर्व है, क्योंकि हमारा भी देश है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वर्तमान में जो देखा गया है ...(व्यवधान) मैडम, एक मिनट हुई है, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा । हम प्रति व्यक्ति आय में विश्व में 136 वें नंबर पर हैं और अगर भुखमरी की बात करते हैं, तो विश्व में 102 वें नंबर पर हमारा देश है । यह विकास 140 करोड़ भारतीयों का नहीं हुआ है, यह मात्र एक-दो परसेंट उद्योगपतियों का हुआ है ।

मैं अपनी मुख्य मांगें रखना चाहूंगा कि नरेगा का जो बजट है, राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है, पूरे केन्द्र शासित प्रदेशों और 28 राज्यों सहित पूरा 2600 करोड़ रुपये का बजट है, इसमें राजस्थान का मात्र 1600

करोड़ रुपये केन्द्र सरकार की तरफ से बजट का पेंडिंग है, इस वजह से मनरेगा स्कीम खत्म हो रही है। मैं चाहूंगा कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारी राजीविका की महिलाओं, जब चुनावी दौर आता है, भीड़ की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम महिलाओं को याद करते हैं। राजीविका और आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गयी है? उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाए।

माननीय सभापति : श्री अरूण गोविल जी।

(व्यवधान)

श्री राजकुमार रोट : महोदया, मेरी अंतिम बात है कि मेरे क्षेत्र के अंदर कडाणा और माही डैम से उस क्षेत्र के अंदर...(व्यवधान)

श्री अरूण गोविल (मेरठ) : धन्यवाद, सभापति महोदया। मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत सप्लीमेंट्री डिमांड फोर ग्रांट्स फर्स्ट बेच वर्ष 2025-26 के समर्थन में बोल रहा हूँ।

Being an actor, I am a non-professional, I will not be playing to the gallery like most of the Opposition Members do. I will not discuss the numbers also presented by them. I will not talk about what they have spoken because they speak on every subject, but not the subject in discussion.

महोदया, मैं अपनी बात सीधा-सीधा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये अनुपूरक माँगें क्यों आती हैं और हमारे लिए इनको एपूव करना क्यों जरूरी है। ये पूरक अनुदान हमारे देश के विकास, जनता की जरूरतों और चल रही योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सरकार हर वर्ष बजट के माध्यम से पूरे साल का खर्च तय करती है, लेकिन वर्ष के दौरान कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य सामने आ जाते हैं, जिनके लिए पहले से तय राशि पर्याप्त नहीं रहती। कई योजनाएँ तेज़ गति से आगे बढ़ती हैं, कुछ विभागों को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, कुछ नई नेशनल प्रायोरिटीज़ भी सामने आती हैं। इन परिस्थितियों में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एक जरूरी कदम होते हैं, ताकि विकास कार्य में कोई रुकावट न आए।

माननीय सभापति महोदया, इस पहले बैच में सरकार ने 72 ग्रांट्स और एक एप्रोप्रिएशन के लिए अतिरिक्त निधि की मांग की है। कुल मिलाकर 1.32 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर की मंजूरी मांगी गई है। इसमें से लगभग 41,455 करोड़ रुपये वास्तविक अतिरिक्त नकद खर्च (net cash outgo) है, जबकि बाकी राशि मंत्रालयों की सेविंग्स और एडिशनल रिसीट्स से पूरी की जाएंगी। यह दिखाता है कि सरकार जिम्मेदारी के साथ, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए, देश के संसाधनों का उपयोग कर रही है। यह पहला बैच देश के कई प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए लाया गया है। इन क्षेत्रों में कृषि और किसान कल्याण, फर्टिलाइजर, स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएँ, शिक्षा, ऊर्जा, रेल, सड़क और ट्रांसपोर्ट, महिला और बाल विकास, पंचायती राज, एमएसएमई, जल संसाधन, अंतरिक्ष और विज्ञान, और विदेश मामले जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। इन कार्यक्रमों को मजबूती देना देश की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

महोदया, सप्लीमेंट्री डिमांड्स का मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता, बल्कि यह बताता है कि सरकार अपनी योजनाओं में स्मार्ट प्लानिंग, सेविंग्स और better use of funds को ध्यान में रखकर काम कर रही है। इन पूरक अनुदानों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि देश के विकास कार्य बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। सड़कें, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों से जुड़ी योजनाएँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट अगर समय पर पैसे न मिलने से रुक जाएँ तो इसका सीधा असर जनता पर पड़ता है। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स से यह सुनिश्चित होता है कि हर योजना समय पर पूरी हो और जनता को बिना किसी देरी के बेनिफिट मिले।

महोदया, आज भारत तेज गति से विकसित हो रहा है। हमें ग्लोबल स्तर पर कम्पीटिशन में आगे रहना है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे रेल मार्ग, सड़कें, डिजिटल और कम्युनिकेशन सिस्टम्स, बिजली, विलेजेज़ और सिटीज़ - सब मजबूत हों। इसी उद्देश्य से इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जा रहा है, ताकि देश की गोथ स्टोरी में कोई कमी न रह जाए। यह सप्लीमेंट्री बैच दिखाता है कि सरकार हर जिम्मेदारी को गंभीरता से ले रही है और देश के विकास को तेज़ और निरंतर रखने के लिए कमिटेड है।

अन्त में, मैं इस सदन से अनुरोध करता हूँ कि Supplementary Demands for Grants - First Batch 2025-26 को मंजूरी दी जाए। ये मांगें जनता की जरूरतों को पूरा करती हैं, देश की योजनाओं को गति देती हैं और भारत को मजबूत भविष्य की ओर ले जाती हैं। यह सरकार की दूरदर्शिता, जिम्मेदारी और विकास के प्रति संकल्प का प्रतीक है। धन्यवाद। जय श्री राम!

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Madam Chairperson. This is the first batch of supplementary Demands for Grants for the Financial Year 2025-26, having 72 Grants and one appropriation, coming to an amount of Rs. 1.32 lakh crore. Before entering into the various Ministries and Departments regarding the Supplementary Demands for Grants, I would like to question and challenge the sanctity of the budgetary process being followed by the Ministry of Finance.

Madam, this has become the usual practice in bringing a series of SDGs every year with huge amount. Last year also, I mentioned this matter by quoting the Public Accounts Committees observation. The Ministries and the Departments have been obtaining Supplementary Grants without conducting a proper scrutiny of the expenditure incurred or likely to be incurred by them during the financial year. This is happening due to lack of foresightedness in various Ministries and Departments and that would show the inefficiency of the Ministry of Finance in the budgetary process and in the planning process. Madam, I urge upon the Government and particularly to the hon. Minister to adhere to the strict compliance of financial rules and direction of the PAC to avoid huge Supplementary Demands for Grants. That is my first submission.

Madam, regarding the SDGs, most of hon. Members have already spoken where the major allocations are going. They are going to the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the Ministry of Communications, Ministry of Road, Transport and

Highways, and Ministry of Petroleum and Natural Gas. Madam, if you yourself examine the Ministry of Chemicals and Fertilizers, you can see the callous way the Budget is being prepared. It is 16 per cent in excess than that of the original Grant envisaged in the original Budget last year.

I do support the subsidies and grants but strongly oppose the way by which this is being brought in the House because the Union Government had estimated Rs. 1.67 lakh crore for fertilizer subsidy for the financial year 2025-26. This is lower than that of Rs. 1.91 lakh crore. That was a subsidy bill in the previous year. In the previous year, it was Rs. 1.91 lakh crore, and, this year, we have estimated only Rs. 1.67 lakh crore. And now the hon. Minister is coming to the Parliament demanding an additional amount of Rs. 31,000 crore. How could the Ministry justify this point in estimating these statistics or estimating this amount? Could the Ministry or the Government not anticipate the fertilizer subsidy in such a situation? So, all this exposes the hollowness of the Governments repeated claims of fiscal discipline and the agricultural reforms in the Budget speech in the year 2025-26. *(Interruptions)* Madam, I am not going into the details.

Regarding the urea also, as most of the hon. Members have spoken, I am not going to repeat it. For the domestic production to be increased, the fertilizer industry has to be strengthened and more amount has to be granted.

Regarding the Department of Telecommunications, there is a 33 per cent excess in the original Budget Estimates. I would like to make a comment on this. This conversion of a due of a company into a Government equity is a hidden subsidy, eroding the Budgets credibility on transparent spending. Finally, I am coming to the Ministry of Petroleum. I am not going into the details.

Further, I would like to say two points regarding the macro-economic situation. First one is regarding the GDP. Last month, the International Monetary Fund retained C Grade for the Indias GDP data, and in the next week, the Indian Government released a data showing the GDP growth rate surging 7.8 per cent to 8.2 per cent in the second quarter of the current financial year. This shows that the Indian economy is the fastest-growing economy. But the question raised by the economic experts like Monika Halan is significant which is to be answered. Though we are having a high GDP growth rate, why is the market not flourishing? She said, Why are markets cool though GDP is hot? The Finance Minister, in the last week, announced the steps that would be taken so as to upgrade the IMF's Grade through change in the base year. I fully appreciate it.

Regarding the expenditure status and fiscal deficit, Madam, fiscal deficit is Rs. 15.69 lakh crore. Now, after additional of Rs. 1.32 lakh crore, how could it be adjusted? I am not going into the rupee devaluation.

I would like to make one correction. The hon. Minister you may kindly see that there is a blatant error in Demand No. 71 because Rs. 95 crore is the original estimate in 2024-25 but you are giving Rs. 3,50,000 crore in the Supplementary Demands for Grants. Maybe, it is a typographical error. Please correct it. This is not the way by which the statistics have to be presented before the Parliament.

19.33 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

Hon. Speaker, Sir, I conclude with two questions. Why is the Government repeatedly pushing the Budget borrowings, unpaid bills, and hidden subsidies into the SDGs instead of placing true fiscal deficit before the House? And the second question is, why should the Parliament approve SDGs that arise from the Governments policy failure and cost overruns, rather than the genuine emergencies as required under the Rules of Procedure. With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you, hon. Speaker, Sir.

I think there were 43 hon. Members who spoke on the Supplementary Demands for Grants, if my numbers are right.

Sir, I will talk less on the details of the Supplementary Demands especially because I will be answering Shri N.K. Premachandran on specific questions that he has raised, which are very valid, and as an hon. Member, he has got every business to raise questions. I will certainly come to responding to him. But just to give a start, I would like to say that this First Batch of the Supplementary Demands for Grants includes 72 Grants and one Appropriation, that is, for the Supreme Court of India. So, the authorization is being sought for gross additional expenditure of Rs. 1,32,268.85 crore, wherein the net cash outgo or the cash supplementary is about Rs. 41,455.39 crore. I will give the break down a bit later.

The technical supplementary, which does not have an additional cash outgo, is about Rs.90,812.17 crore. Therefore, this Batch of the Supplementary Demand for Grants also provides for the recoupment of Contingency Fund advance of Rs.14,825.42 crore.

Much before I go into the details, I am a bit disappointed that there are Members who speak in a manner that shows a lack of budgetary planning and so on. Supplementary demands are absolutely necessary for a responsive Government. I cannot respond to the Departments or the States which ask for funds on certain very critical aspects by saying that what I have given you in the BAE is the final word, and that they should manage with that - I cannot say that. I will have to be responsive. But, yet, I agree (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री जी, आप इन्हें थोड़ा बताते रहिए । ये धीरे-धीरे सीख जाएंगे, अभी नए-नए ट्रेनिंग पार्ट में हैं ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Of course, I grant it that I cannot have too many supplementary demands. Actually, I would like to put on record here that, due to very careful monitoring by the hon. Prime Minister, I can stand up here and say that I have reduced the number of supplementary demands. I do not allow them to be more than two, two at the extreme. If anything, I will try to have just one supplementary.

Therefore, I would want that perspective to be brought in here. The revenue and capital break-up for the cash supplementary is Rs.40,058.35 crore for revenue and Rs.1,397.04 crore for supplementary. The technical supplementary, where there is no cash outgo, it is from one saving in that Ministry towards another. So, it just swaps within the Ministry or the Department. The amount is Rs.22,387.38 crore for revenue and Rs.68,424 crore for capital.

Members have rightly pointed out that there is a huge outgo for fertilisers, and I will explain it. I can quite understand the sense of outrage Shri N. K. Premachandran has expressed, saying, why should there be such an increase? But hang on, if farmers want more fertilisers and urea, the Government cannot sit and lecture them by saying, No, no, what do you mean? You cannot take more than this. Can I say that? No.

Particularly after a good monsoon, if there is a demand for additional urea utilisation, it is a business of the Government to get it. Despite the fact that, since Covid-19, there has been unpredictable fluctuation in the prices of urea, DAP, and other materials that we are importing, there has been a very careful management. I must appreciate the Department of Fertilisers, which carefully imports in time.

I will give you the exact numbers. Indian farmers have not been let down by the Ministry. They have ensured that there will be timely dispersal, both for the Kharif

season and the oncoming Rabi. (*Interruptions*) I will give you all the numbers, so that is fine.

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए, ऐसे बीच में नहीं उठते हैं । कृपया आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: So, I will speak. As I respond to the hon. Members, I thought the supplementary should have no issues for the hon. Members.

माननीय अध्यक्ष : अगर दादा नहीं उठें, तो सदन में जीवंतता भी नजर न आए ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : आप हमेशा सदस्यों के पक्ष में ही रहते हैं ।

माननीय अध्यक्ष : सदस्यों के कारण ही सदन है ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yes, I fully agree. Just to respond, again, I was a bit disappointed that the hon. Member Shri Deepender Singh Hooda was probably giving a political speech here, and I want to give him that space, but it cannot be on absolutely baseless arguments.

I do not want to use the word allegation. He is not alleging anything. He is just saying, oh, this is not right, that is not right. I will come point by point to say where he was not really right. He said, you are not spending much on education, R&D, Defence when it comes to percentage of GDP.

Sir, without spending money in education, would we have IITs? I am reading it. There were 16 in 2014 which have become 23 now. Can IITs be established without money? Indian School of Mines, Dhanbad, is also accorded the IIT status. Similarly, the number of IIMs have gone up from 13 to 21. Without money, can it be done? Sir, 31 NITs are established. NIT, Andhra Pradesh was established in 2015. IIITs have gone up from nine to 25. Sixteen new IIITs are there. Central Universities have gone up from 40 to 48. AIIMs have increased from seven to 12. Sixteen AIIMS are approved and 12 are established. So, education spending could not happen if there is no money given.

Similarly, for R&D, in the last ten years, Indias gross expenditure on research and development has more than doubled. In 2010-11, it was Rs. 60,200 crore whereas in 2021, just in ten years, it has touched Rs. 1.27 lakh crore without money being spent.

Separately one lakh crore rupees have been given for Research and Development Grant which has been launched and which will boost private led innovation. So, with that money, the anchor or the special body which is going to deal with it is going to raise more money from the market and provide for R&D. So, is that going to be without money? We are telling you that in the Budget we make this provision. So, Sir, the Government contributes 64 per cent of gross expenditure on Research and Development and private sector contributes 36 per cent. This is a published document. So, if 64 per cent is going for gross expenditure on Research and Development, hon. Deepender Hooda, your saying that no money being spent in education is not right.

Sir, now, I come to the Defence. Education was one thing. Research and Development was another thing. Defence was the third thing. He said, you are not spending money. Sir, Rs. 53.83 lakh crore have been allocated for Defence since 2014-15. Is that not money going for Defence? Otherwise, why would we also have defence production capabilities multiplied in this country? Indigenous defence production hit a record of Rs. 1.27 lakh crore in 2023-24, a 174 per cent surge from Rs. 46,400 crore in 2014-15. In 2014-15, it was Rs. 46,400 crore. Now, where has it reached? Even by 2023-24, it reached Rs. 1.27 lakh crore. Is that possible without spending? Sir, 16000 MSMEs are emerging as gamechangers, strengthening indigenous defence capabilities. Will they grow without support? These MSMEs are specialising in defence manufacturing. 788 industrial licenses have been issued for 462 companies for producing defence.

Now, I will come to Indias defence exports which I am sure the Defence Minister has said in so many different answers given in the Parliament Questions.

In 2014, defence exports from India was Rs. 1000 crore. In 2024-25, it is Rs. 23,622 crore. Is that possible without a policy which helps? So, that is one thing.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): It is much less than what the neighbouring countries are doing.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Do not worry. You can go on shifting the milepost, hon. Member but, yes, I am quite drawn to what the Parliamentary Affairs Minister is saying.

Compare it with your term, where a Defence Minister was compelled to stand up in this House and he said: I do not have money. आज वह हालत नहीं है कि रक्षा मंत्री जी इस सदन में खड़े होकर यह कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है । (व्यवधान) दीपेन्द्र हुड्डा जी, उस समय की हालात देख लीजिए

। आपको उस समय खड़े होकर चिल्लाना चाहिए था कि "मेरी पार्टी को पैसा दो, हमारे रक्षा मंत्री जी खड़े हो कर कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है ।" यह बात उस समय बोलनी चाहिए थी । (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Why do you not mention the name?
(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sureshji, you are from Kerala. It is a distinct signature of a Kerala-based Minister. (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Why do you not mention the name? (Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I will mention the name, and I will also keep the record with all authentication. Sir, do not ask me as though you do not know it.
(Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Please tell us the name. (Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: What is the satisfaction you are going to derive by my telling you? आपके ही मिनिस्टर थे, केरल से Oh, please, Sureshji, do not make me feel ashamed. (Interruptions) यह नाटक इस हाउस में नहीं होना चाहिए कि रक्षा मंत्री जी कुछ बोलें और मुझे कुछ मालूम नहीं है । आज विपक्ष में बैठे हुए हैं । (व्यवधान) नहीं, यह ठीक नहीं है । (व्यवधान) मुझे प्रोवोक कर रहे हैं कि मैं उस महान व्यक्ति का नाम यहां बोलूं, ताकि आप लोग तुरंत खड़े होकर वॉक आउट कर दें । (व्यवधान) यह सच्चाई है । यह नाटक यहां नहीं होना चाहिए । (व्यवधान) This is unfair Sureshji. (Interruptions) आपको सब मालूम है और मुझे उनका नाम लेने के लिए छेड़ रहे हैं । आप थोड़ा रिसर्च करके ढूंढ लो ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Please do not make any allegation against him.
(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: It is not an allegation. It is a fact recorded in this House. (Interruptions) आप जाकर थोड़ा होमवर्क करिए । (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य ऐसे नहीं किया जाता है । राजकुमार जी, यह सदन है । आप तरीका समझें ।

श्री राजकुमार रोट : सर, ये मुझे उठा रहे थे ।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आप सही तरह से जवाब नहीं देते हैं ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठ जाइए ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: It is called harassment to say: Tell me the name. I do not know the name of my own Minister who said that. ये क्या बात कर रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष : आपको अभी बुलाता हूं, आप दो मिनट रुक जाइए ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, there was one observation by hon. Member that income inequality has broken the record of 100 years. I just want to put the facts before the House. Regarding actual household consumption, the data shows that bottom 40 per cent of the population is acquiring wealth and assets at a significantly faster rate than the top 20 per cent. This is the data which I will leave for everybody to see. The inequality in asset ownership has massively declined, particularly in urban areas, where the disparity for key assets like motor vehicles and refrigerators has shrunk dramatically. The rural poor have experienced a significant growth in purchasing power that defies the incorrect analysis given by the hon. Member, Shri Hooda. The ownership of motor vehicles among the 40 per cent rural bottom surged sevenfold, rising from a mere 6.2 per cent in 2011-2012 to 47.1 per cent in 2023-2024. The motor vehicles have now become affordable for the bottom rung also. Similarly, refrigerator ownership in this group jumped nearly eightfold, from 2.9 per cent in 2011-2012 to 22.5 per cent in 2023-2024. Mobile phone ownership became near universal, leaping from 66.5 per cent to 94.3 per cent. Is this not asset being acquired by the bottom rung of the people?
(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे क्यों कमेंट कर रहे हैं?

श्री किरन रिजिजू : सर, यह पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन दादा ने इनको सीखा दिया है ।

माननीय अध्यक्ष : इनको अच्छी चीज सीखनी चाहिए, बुरी चीज क्यों सीखनी चाहिए?

श्री किरन रिजिजू : सर, ये बुरी चीज सीख रहे हैं ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, in urban India, the consumption gap is not just closing. For some assets, it has been completely reversed. For the first time, the urban bottom 40 per cent now owns more televisions, that is 77.4 per cent, than the top 20 at 72.1 per cent. At the upper level, it is 72.1 per cent; here it is 77.4 per cent. The ownership gap for aspirational goods like refrigerators in urban areas actually collapsed from 46.3 percentage points in 2011-12 to just 12 percentage points in 2023-24. The asset poverty expression is defined as households owning none of the key assets. That number has actually been thrashed, falling from roughly 30 per cent to just five per cent among rural poor,

which means rural poor, five per cent or less, are the ones without any asset at all, whereas the rest of them have some asset or the other. We need to understand that in the last one decade, growth has actually become quite broad-based and people from the bottom rung are the ones who are acquiring one of the assets.

PROF. SOUGATA RAY: President Donald Trump called India a Dead Economy.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I was going to come to that. Since Professor seems to be in a hurry, I will reply to that.

माननीय अध्यक्ष: माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि जो बैठे-बैठे बोलते हैं, उनके कमेंट्स पर टिप्पणी मत कीजिए ।

माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन है कि आप कृपया बैठे-बैठे टिप्पणी मत कीजिए ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए ।

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I want to give the advantage or the benefit of doubt to the hon. Member, Shri Deepender Hooda. He simultaneously used the expressions *Vyapar Ghata*, Current Account Deficit. So, when he spoke in English, he said Current Account Deficit, whereas he also used probably in interchangeable way *Vyapar Ghata*. Both the terms do not mean the same. So, it is very important to understand that we take both the terms seriously but separately. There should not be any confusion. I do not actually know which one was he referring to, *Vyapar Ghata* or Current Account Deficit. The same number cannot apply to both. (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको अंतिम बार बोल रहा हूँ ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका नाम लेकर नहीं बता रही हैं । आपने पहले बोला था, इसलिए वे उसके ऊपर बोल रही हैं ।

मंत्री महोदया आपकी स्पीच पर जवाब दे रही हैं, इसलिए आपका नाम ले रही हैं । चूंकि आपने बोला है, आपने जो-जो विषय उठाए थे, इसलिए आपका नाम लेकर वे उनके जवाब दे रही हैं । यह अच्छा है ।

(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the claim that the Current Account Deficit is at its maximum is factually incorrect. I want that to be clear. The record deficit claim that the hon. Member has made is really wrong. At the end of June 2025, India's Current Account Deficit stood at 0.2 per cent of GDP. Where was it? The hon. Member was mentioning some double-digit number. Current Account Deficit in June, 2025, stood at 0.2 per cent of the GDP. For the fiscal year, March 2025, it was only 0.6 per cent.

20.00 hrs

Let us place that on the record.

Sir, contrast this with the taper tantrum of 2013, when the current account deficit ballooned to a crisis level of 4.8 per cent of GDP. (*Interruptions*) In fact, that is the maximum that India has seen since 1970. So, hon. Members should actually consider that since 1970, that has been the maximum. I hope this correction comes into play. In 2013, there were volatile capital flows constituting 96.1 per cent of all our reserves, leaving the economy completely vulnerable to sudden outflows. Today, that ratio has fallen to 66.6 per cent, proving that we are far more stable now than at the time of 2013. So, hon. Member, please be assured that the economy today has moved from fragility to a level of fortitude. So, that is the matter of fact. (*Interruptions*)

Sir, the import cover has also strengthened. In 2013, we had foreign exchange reserves sufficient to cover only seven months of imports. Today, that figure has moved to 11.4 months as of June 2025. So, when I say we have moved from fragility to fortitude, this is the kind of number I am talking about. Therefore, projecting the anxieties of 2013, onto the stability of today, 2025, is a political fabrication that ignores hard reality that India has actually transitioned from external vulnerability to external resilience. I would like to draw this to the hon. Member's attention.

Sir, even worse was the comment on Debt-to-GDP ratio. The Central Government's debt in 2013-14 was 52.2 per cent of the GDP. That was actually reduced to 48.9 per cent by 2018-19 because of the strict monitoring that the hon. Prime Minister maintains on fiscal balance and strict adherence to the policy of gradual fiscal consolidation. Who would have thought that we would have COVID-19 pandemic, as a result of which the Government proactively took measures to protect lives and ensured that livelihoods were taken care of? Consequently, our debt went up to 61.4 per cent of the GDP. It actually shot up, but after that, because we gave

ourselves a steady path, which is a glide path, it has come down again. By 2023-24, we brought it down to 57.1 per cent, and it is estimated that by the end of this year, it will reach 56.1 per cent. Despite COVID-19 pandemic and heavy borrowing, the Debt-to-GDP ratio is actually coming down. If only the number from 2013-14 is kept in mind, you will see that we are getting closer to that mark. That is even without considering how it was managed during the global financial crisis in 2008.

Sir, I do not wish to speak again about the Debt-to-GSDP ratio of several States. I am not naming any State here. As it is a genuine concern, the Debt-to-GDP ratio will have to be brought down. It is also true that the Debt-to-GSDP ratio of many States is also rising. It is a legitimate concern, and I have addressed it. I am showing that we are bringing the debt to GDP down. We have given a commitment to Parliament, and we are abiding by it every year without failure since 2020-21. Equally, there should be concern about the Debt-to-GSDP ratio of many States. I am not naming any State. But many of us should be equally concerned about debt to GSDP in the States, which is also going really bad. Therefore, collectively, we have to work to bring down the debt to GDP and the debt to GSDP numbers.

Now, Make in India has become Make for the World. Again, sorry, Sir, absolutely ignored outcomes on the ground is not a fair comment to make. India has emerged as a net exporter in sectors such as electronics, pharmaceuticals, engineering goods and defence. When I say net exporter, I am sure the hon. Members know what we export and what we import are reconciled, and when you are a net exporter, you mean that you are exporting more than you are importing. I will just give a few numbers.

In 2014-15, the production of electronic goods in this country was only Rs.1.9 lakh crore. In 2024-25, it has increase to Rs.11.3 lakh crore. Exports of electronic goods in 2014-15 was merely Rs.38,000 crore, and today it stands at Rs.3.27 lakh crores, an eight-fold increase. Mobile manufacturing units were numbered only two in 2014-15. In 2024-25, there are 300 units, reflecting 150 times growth. In 2014-15, mobile phone production was about Rs.18,000 crore whereas in 2024-25, it is about Rs.5.45 lakh crore, a 28 times growth. Mobile phone exports stood at Rs.1,500 crore in 2014-15. Today, in 2024-25, it is about Rs.2 lakh crore, which is 127 times higher than earlier.

So, Make in India for the World is happening. We should just recognize this achievement of the people, and not ignore or undermine it.

Sir, several Members spoke about how IMF has highlighted concerns about GDP data. Not even a week ago, I stood in this House and explained, what that C grade is. What is it for? Singularly, it is for the fact that we are still keeping 2011-12 as the base year. The Ministry of Statistics and Programme Implementation has already announced that from late January 2026, the base year transition will happen, as a result of which, the grading for that one particular base year argument of our national statistics will change. We will change it. However, many Members who said, You were B, and now you have come to C, are utterly wrong. It is absolutely wrong. India's number grading has remained the same, and the median rating for this year is B. IMF did not downgrade India's rating. The same grade was given to India's National Account Statistics in the 2024 as well. So, it has added that the GDP series with 2011-12 as the base year should be rebased as soon as feasible. That is what they said. So, for us to go on saying that there has been a downgrade by IMF is misleading this House, which is not right. For this year, the IMF gave a B rating for overall statistics. I think it is important that the hon. Members get the facts right.(Interruptions)

Sir, some have said, Average growth rate in the last 10 years of UPA was 8.1 per cent and now it is 5.75 per cent, so what is there to rejoice? Who would have thought that we would face a once-in-a-century pandemic? Despite that, India has been the fastest growing economy, not for one year, but continuously for the second, third, and fourth year. Is that not something for which the people of India deserve to be recognized? On the contrary, you go on saying, ours was 8.1, yours is this.

Sir, I just want to put the facts before you. We had to actually deal with high twin deficits. In the year 2013, fiscal deficit was 4.9 per cent and current account deficit was 4.8 per cent - twin deficits. If that is the credit they want to take for themselves, they should. At no time in India both these deficits, ran simultaneously. That is the data point on which hon. Member Hooda Ji should introspect.

Regarding food articles, WPI for food articles averaged at 12.2 per cent annually in the five years ending 2013-14. Where is WPI today? Where is CPI today? Therefore, to go on repeating as though their record in inflation management was better, I do not know if I should take the name again. Recently, there is a lot of talk about how former Reserve Bank Governor, the former Chief Economic Advisor - the same person - has been commenting on how India has successfully managed inflation. If you want the name, I will say it also and get you the video of what he said. India

under Prime Minister Modi has succeeded in keeping inflation under control, is an observation given by former Governor of Reserve Bank. (*Interruptions*)

Sir, Trump said India is a dead economy. What is the Central Government saying? While the global growth is 3.2 per cent, India is growing at 8.2 per cent last quarter, becoming the fastest growing major economy. Every institution is raising our growth outlook for this year and for the forthcoming year. The IMF Chief Kristalina Georgieva on 14th October, 2025 said, I am very big on India because of the boldness of their reforms. India has proven the naysayers wrong. So, there are clear expressions recognising India's growth and no dead economy gets a credit rating upgrade by DBRS, S&P and R&I. If your economy is dead, why will they upgrade your growth and your credit rating? Why is it getting upgraded? So, somebody said something somewhere. However important that somebody is, we should not depend on that but rely on data available within the country and also data coming from elsewhere. Rely on data.

Can a dead economy grow at 8.2 per cent? Can a dead economy get credit rating upgrades? So, constantly looking at someone and saying, oh, you said that, what do you want to say? Numbers are saying it. (*Interruptions*) So, look at the indicators. Tractor sales in October 2025 reached the highest level for any month in the past 11 years. Retail commercial vehicle sales jumped by 17.7 per cent in October 2025, reaching a three-year high. Automobile registrations surged by 23.4 per cent. Passenger vehicle sales grew by 15.5 per cent. GST e-way bills grew by nearly 28 per cent year-on-year. Services export achieved their highest ever monthly level of \$38.5 billion in October. UPI transactions grew by 60 per cent in October 2025. So, that is the case.

Now, I move on to talking about fertilizer. It is very important. Between June and October 2025, kharif crop season, the projected requirement of fertilizer was 185.39 lakh metric tonnes. The availability which the Ministry ensured was 230.53 lakh metric tonnes.

What is the estimated requirement? It is 185.39 lakh metric tons. What is the availability? It is 230.53 lakh metric tons. You can say, oh, you have made it available, but it did not reach the ground. But what were the sales? They were 193.20 lakh metric tons. More than what was projected has been sold, and more than that is still available. Therefore, we have managed it in such a way that today we have a bumper buffer available even for the oncoming Rabi season. Within a month, by carefully managing imports, urea stocks increased from 48.64 lakh

metric tons as of 1st October, 2025 to 68.85 lakh metric tons by 31st October, 2025. That means within a month, 20.21 lakh metric tons were added through careful and steady imports. So, there is no shortage, neither during the Kharif season nor for the current Rabi season. This point was also made that if the overall stock increased from 48.64 lakh metric tons as of 1st October, as I mentioned, to 68.85 lakh metric tons by 31st October, where is the shortage? We have been importing without blinking our eye because we do not want any shortage for farmers.

Domestic urea production, about which N. K. Premachandran ji spoke, has also shown improvement. Production during October 2025 reached 26.88 lakh metric tons, which is higher by 1.05 lakh metric tons compared to the same month last year. So, even on a month-to-month comparison, we have increased domestic production by one lakh metric tons within the country. Not only we are importing despite the increase in cost, we are also increasing domestic production. The average monthly production between April and October has remained robust at about 25 lakh metric tons. I want this to be put on record that there is no shortage of fertilizers whether imported or domestically produced. The sales figures also reflect this. Yes, there is demand from farmers because, as I said, the monsoon was very good. They see prospects for one more crop because of the rain and the lovely moisture in the ground. Therefore, farmers want more urea, and to provide them with the additional urea they may require, we have made sure that both imports and domestic production are going up. So, I would like to tell N. K. Premchandran ji that there has been no carelessness in dealing with this matter. The Supplementary Demands for Grants is required because we are ensuring that there is enough stock of fertilizers. To that extent, additional appropriation is needed. That is why, we have come to the House to say, please give us the authority so that we can provide more for the farmers.

Further, imports of approximately 17.5 lakh metric tons are already lined up for November and December. They will keep coming. The payments have been made. These 17.5 lakh metric tons are being imported now, so that there are no doubts in anyones mind. The stock is there, and we will distribute it. The Centre has supplied fertilizers to every State, and the supplies are monitored in real time through the Integrated Fertilizer Management System. I want this to be put on record that there is no shortage.

Hon. Member, Neeraj Maurya mentioned that we have brought in this new scheme in the education sector one nation, one subscription and called it a comedy.

Honestly, education is an area where we are spending significantly. Please do not call it a comedy. Universities in top cities have subscriptions to very good journals and peer-reviewed articles, which come in digital form as well.

That university can afford to pay the money and get the subscription. But the universities which are in smaller towns, State Universities which are in Tier II and Tier III towns, cannot give that kind of money for subscription. So, India actually collectively bargained and I appreciate the Ministry of Education. I was in a university. It was so expensive to get the subscription paid to get some magazines or journals which are important. India has taken a very good decision under hon. Prime Minister Modi that this country will pay and get the subscription and it will be available for big towns, small towns, Tier II towns, any town anywhere, actually democratising the availability of such research-based magazines for all students in India. यह कॉमेडी नहीं है । श्री नीरज मौर्य जी, यह कॉमेडी नहीं है । सच में, यह स्टूडेंट्स के लिए वरदान है । It is a blessing. In any town, you will get the best of magazines subscribed by the country for your research requirement. इससे बढ़िया सुविधा किसी और चीज में नहीं हो सकती है, especially for education. इसका उपयोग बहुत-से स्टूडेंट्स कर रहे हैं । It has actually become a gold mine of knowledge available from top quality scholarly journals. लगभग 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हुआ है । (*Interruptions*)

Sir, there are last two points. Nearly 5.8 per cent was the overall unemployment rate. As per the usual status, the overall unemployment rate declined from 5.8 per cent in 2018-2019 to 3.2 per cent in 2023-2024. Similarly, female unemployment rate from 5.1 per cent in 2018-2019 has now come down to 3.2 per cent. Similarly, for youth aged 15-29 years, unemployment rate declined from 17.3 per cent in 2018-2019 to 10 per cent in 2023-2024. Rural unemployment rate declined from 5 per cent in 2018-2019 to 2.5 per cent in 2023-2024. Similarly, for urban, it has declined from 7.6 per cent in 2018-2019 to 5.1 per cent in 2022-2023. So, there were more data available but one important thing is EPFO.

The overall EPFO membership has increased from 3.76 crore in 2016 to 7.37 crore in 2024. The net additions to EPFO we get to know from the unique number of people who have newly joined. The net EPFO addition in 2025 stood at 129.8 lakhs, which reflects that jobs are being taken by young people. (*Interruptions*)

Sir, women safety was a question which one of the hon. Members raised. I want to say that under the Nirbhaya Fund, Rs. 7,712 crore has already been allocated, with over Rs. 6,200 crore already released and being utilised for women safety initiatives. A number of 843 One Stop Centres are operational across the country

having assisted over 11.9 lakh women. Womens Help Desks have been established in over 14,000 police stations and safe city projects are also being undertaken. Normally, if you put it all together, gender budget is a number that I can give. For the benefit of women and girls under different schemes, the Government of India has allocated Rs. 4.49 lakh crore for the year 2025-2026. That itself shows the quantum of money which is going through various schemes for the benefit of women.

Sir, lastly, hon. Member, Shri Gurmeet Singh Meht from Aam Aadmi Party raised this issue that there should be proper allocation to Punjab when it comes to Khelo India Scheme. I want to highlight that several initiatives have been taken under the Khelo India Scheme to engage and promote youth participation particularly in Punjab. A total number of 29 Khelo India Centres have been established in Punjab.

Punjab has a Khelo India State Centre of Excellence for hockey, boxing, and athletics. Twenty-four Khelo India Academies have been established in Punjab.
(Interruptions)

The Sports Authority of India also runs one National Centre of Excellence at Patiala and three SAI Training Centres at Mastuana Sahib, Badal and Ludhiana in Punjab. So, in sports, every Central scheme reaches Punjab.

Lastly, I want to refer to hon. Member, Shri Rajkumar Roat. *(Interruptions)* He is not here. He talked about natural farming against using pesticides and fertiliser. Actually speaking, hon. Prime Minister has spent a considerable amount of his time advocating natural farming. He has actually gone to different parts of the country to give encouragement. One last such meeting was held in Coimbatore where farmers came in hundreds to speak about how natural farming can help us.

So, hon. Member, Shri Rajkumar Roat should actually refer to all the Prime Ministers speeches on that issue. He also has spoken about GST बढ़ाया गया है । जीएसटी बढ़ाया नहीं गया है, बल्कि सबका जीएसटी कम कर दिया गया है ।

Maybe, I will send him all the details with which he will be sure that we have not increased anybody's GST except, of course, it is a demerit good.

Thank you very much, Sir.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं कई वरिष्ठ सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वे सदन के बीच बैठे-बैठे टिप्पणियाँ न करें । वरिष्ठ सदस्यों द्वारा बैठे-बैठे टिप्पणियाँ करना या बीच में खड़े होकर टोकना सदन की मर्यादा

की अनुरूप नहीं है। चूंकि आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कभी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि कोई आपको नोटिस भी न करे। यह भी चिंता का विषय है।

(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदय, हम लोग बहुत दुखी हैं, इसलिए हम लोग वॉक आउट कर रहे हैं। (व्यवधान)

20.27 hrs

At this stage, Prof. Sougata Ray and some other hon. Members left the House.

(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन और सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा कई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।

(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, the hon. Finance Minister has not given a satisfactory reply. (Interruptions) So, we are walking out. (Interruptions)

20.28 hrs

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members left the House.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कैसा बुरा समय आ गया है। आप यहां से अकेले जा रहे हैं, आपके साथ कोई भी नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन और सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा कई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के सामने मतदान के लिए रखता हूँ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रथम बैच को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन में आसन की तरफ पीठ करके खड़े नहीं होते हैं ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15 से 21, 23 से 30, 32, 35 से 38, 43 से 55, 58 से 66, 68, 69, 71, 72, 74, 76 से 79, 82, 85 से 89, 94 से 99 और 101 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।

<image: image001.jpg>

<image: image002.jpg>

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

-

-